

प्रकाशक :

गोकुलदास धूत,

नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर.

जनवरी १९४७

मूल्य १-१२-०

मुद्रक-

सी. एम्. शाह,

मॉडर्न प्रिन्टरी लि., इन्दौर.

प्राक्कथन



यो तो रियासतो पर लिखे गये साहित्य में अभिवृद्धि करने वाली प्रत्येक रचना का स्वागत करते हुए आनन्द होता है। परन्तु जब वह रचना श्री वैजनाथ महोदय जैसे सुयोग्य लेखको की हो, जिन्होंने विषय को अधिक अच्छी तरह समझने में सहायक होने वाली बुनियादी जानकारी को एकत्र करने में सच्चे दिल से यत्न किया है, तो वह त्रिवार स्वागत करने योग्य हो जाती है। क्योंकि लेखक ने निःस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में बरसो बिनाये है, गांधी सेवा संघ के मंत्री की हैसियत से तथ्यों को तालकर उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करने की उन्हें काफी ट्रेनिंग मिली हुई है, और फिर इन तमाम वर्षों में सदा रियासते और रियासती जनता की दोहरी गुलामी से मुक्ति, उनकी खास दिलचस्पी का विषय रहा है।

एक समय ऐसा था, जब रियासतों के सवाल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। अधिकार और लापरवाही उसकी किस्मत में थी। आज वह इस अवस्था से बाहर निकल चुका है। और उसने ऐसा महत्त्व धारण कर लिया है, तथा इतना जरूरी बन गया है कि जिसकी शायद ही पहले किसी ने कल्पना की हो। तमाम महान् आन्दोलनों का ऐसा ही होता है। पहले लोग उन्हें लापरवाही की नजर से देखते हैं, फिर वे सन्देह की वस्तु बन जाते हैं और अंत में जाकर लोग उनका सही सही स्वरूप समझ पाते हैं। इंग्लैंड के मजदूर आन्दोलन को भी इसी विकास-क्रम में से गुजरना पड़ा है। सन १८५८ में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसका केवल एक सदस्य था। पर आज मजदूर दल के सदस्यों की संख्या चार सौ अस्सी है, और वे ब्रिटेन तथा शक्तिशाली ब्रिटिश

साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे हैं। रियासती जनता के आन्दोलन को तो इसका एक तिहाई समय भी नहीं लगा है। अभी अभी बीस साल पहले तक कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, ऐसी दुर्दशा थी। आठ साल पहले हरिपुरा के अधिवेशन में वह प्रथम श्रेणी का प्रश्न बन गया। और आज तो राष्ट्र के प्रश्नों में उसने ऐसा महत्त्व धारण कर लिया है कि दूसरे अनेक प्रश्नों को अलग रखकर पहले उस पर विचार किया जाता है।

सचमुच, अगर भारतवर्ष स्वतंत्र होता है पर उसके एक तिहाई हिस्से को काटकर उससे अलग कर दिया जाता है और उसे स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करने दिया जाता तो भारतीय स्वतंत्रता निरी एक मिथ्या वस्तु होगी। उस भारत को हम स्वतंत्र भारत नहीं कह सकते। भारतीय स्वतंत्रता एक गोल है—द्वितीया के नहीं, पूर्णिमा के चन्द्र के समान वह एक पूर्ण विम्ब है। इस अर्थ में कांग्रेस ने रियासती जनता के आन्दोलन को देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन का एक और अविभाज्य अंग के रूप में माना है। एक समय एक ही उद्देश से प्रेरित ये दोनों आन्दोलन विभिन्न दिशाओं में जाते हुए दिखाई देते थे। बाद में दोनों समानान्तर रेखाओं पर बढ़ते रहे। और अन्त में वे दोनों एक ही केन्द्र-बिन्दु के आस-पास घूमने वाले वर्तुल की रेखा पर आ मिले। दोनों की मिलकर एक ही ट्रेन बन गई और दोनों के ड्राइवर भी पं० जवाहरलाल नेहरू के रूप में—जय सन् १९४६ में वे राष्ट्रीय महातम और अ० भ० देशी राज्य लोक परिषद के मन्नापति थे, एक ही हो गये। उम दिन से कश्मीर, और हैदराबाद, बड़ोदा और कावुशा, मलेरकोटला और फरीदकोट, मंसूर और ब्राणव कोर, बालियर और भोपाल, सागली और कोन्हापुर, तालचैर और धनकनाल, मणिपुर और कूचबिहार, चित्रल और कलान और मिरमौर और बिलानपुर की ग्यान्तें, देशी-राज्य-लोक-परिषद् तथा कांग्रेस की भी, नमान दिलचस्पी के विषय बन गई।

देशी राज्यों की जनता का असली शत्रु, नरेशों की निरंकुशता अथवा जनता की अकर्मण्यता नहीं, बल्कि राजनैतिक विभाग के षडयन्त्र हैं। अतः जब तक उनका खात्मा नहीं कर दिया जाता, तब तक रियासती जनता की—बल्कि नरेशों की भी—मुख्त की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बीमारी को दूर करने में हमें उसी मात्रा में सफलता मिलेगी, जिस मात्रा में उसकी जड़ को हम काटेंगे। इसके सिवा और सब उपाय तो ऊपरी ही होंगे। वे बीमारी को कम कर सकते हैं, उसे पूरी तरह दूर नहीं कर सकते। इसी प्रकार जबसे अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना हुई है, हमने इस बीमारी की जड़ में हाथ डाला है। और यद्यपि आज राजनैतिक विभाग से उसका बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है, तथापि उसका नैतिक प्रभाव तो उस विभाग पर प्रतिक्षण पड़ता ही रहता है, और निःसन्देह यह प्रभाव इस विभाग के फैलादी कवच को तोड़कर फेंक देगा। असल में तो जब अस्थायी सरकार बनने वाली थी उसी समय इस नई सरकार तथा नरेशों के बीच के सम्बन्धों को व्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाने वाली थी। पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकी। खैर !

प्रान्तों और रियासतों को जोड़ने वाली एक नई कड़ी विधान-परिषद् का अधिवेशन है। इसमें दोनों के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठकर विचार करना पड़ता है। और आज तो राष्ट्र का संपूर्ण ध्यान इस यत्न में लगा हुआ है, कि इस परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधि वास्तव में, और पर्याप्त मात्रा में, रियासती जनता के ही प्रतिनिधि हों।

अफसोस की बात है कि ऐसे मौके पर, सागली और कोचीन जैसे शुभ अपवादों को छोड़कर, शेष सब नरेश अपना हिरस्ता ठीक तरह से अदा नहीं कर रहे हैं। वे अपने प्रजाजनो की आकांक्षायों को बुझाने की मानो होड़ में लगे हुए हैं। दुनिया जानती है कि अंग्रेजों की सार्व-भौम सत्ता बहुत जल्दी यहाँ से उठने वाली है। तब याद रहे, काम

पड़ेगा नरेशो को सीधा अपने प्रजाजनो से ही । नरेश चाहे तो यह सम्बन्ध प्रेममय हो सकता है; और यदि वे न चाहे तो उनके और प्रजाजनो के बीच निरंतर संघर्ष भी चल सकता है । उस समय अंगरेजो की संगीनें नहीं, प्रजाजनो का प्रेम और सद्भाव ही उनकी ढाल होगी । अगर हम याद कर लें कि पिछले महायुद्धों में जर्मनी के कैंसर, इटली के राजा, आस्ट्रिया के बादशाह और रूस के जार जैसे और नरेशो से कहीं अधिक शक्ति-शाली तथा धनजन से सम्पन्न लोगो तक का नामोनिशान मिट गया है, तब नरेशो के सामने उनकी प्रजाजनो से और प्रजाजनो की उनसे होने वाली लड़ाई का सही सही चित्र खड़ा होगा और उसके परिणामो का उन्हें ठीक-ठीक भान होगा । आज राष्ट्रीय महासभा का धीरज कसौटी पर है, पर अब उसकी भी हद आ पहुंची है । हिम-शिखर की भांति किसी भी क्षण वह जोर से टूटकर गिर सकता है, या महासागर के ज्वार के समान, अपनी अतल गहराई से उमड़ कर, स्वाधीनता के प्रवाह को रियासतो ने जान से रोकने वाले इस फेन को हवा में उड़ाकर फेंक सकता है । सचमुच, नरेशो का भविष्य बया होगा, वही सोचें । अपनी किस्मत के निर्माता वे खुद ही हैं ।

नई दिल्ली
५ दिसम्बर १९४६

}

(डॉ०) पट्टाभिसीतारामैया

दो शब्द



पिछले वर्ष “रियासती जनता की समस्यायें” नामक मेरी एक छोटीसी पुस्तिका उदयपुर अधिवेशन के समय प्रकाशित हुई थी। वह दो-तीन महीनों में ही बिक गई और प्रकाशको की तरफ से मुझे उसका दूसरा संस्करण तैयार करने के लिए कहा गया। पर मैं महीनों इस काम को हाथ में नहीं ले सका। अभी जब उसे मैंने शुरू किया तब तक देश की स्थिति काफी बदल गई थी। उसके अनुरूप जब मैं उस पुस्तक को बनाने बैठा तो इतनी अधिक नई सामग्री उसमें देनी पड़ी कि वह दूसरा संस्करण नहीं बिलकुल दूसरी पुस्तक ही बन गई। इसलिये नाम भी बदल देना पड़ा।

रियासतों के सवाल पर इस प्रश्न के अधिक जानकार या कोई नेता लिखते तो अच्छा होता, परन्तु बड़े नेता इतने कार्यमग्न हैं कि उन्हें इस छोटेसे काम के लिए अवकाश मिलना कठिन है। फिर भी छोटी-मोटी रियासतों में काम करनेवाले असंख्य ग्रामीण कार्यकर्ताओं को इस विषय की कुछ आवश्यक जानकारी देनेवाली किताब की जरूरत तो थी ही। वही इस पुस्तक में देने का यत्न किया गया है।

इस आवश्यकता को किसी अंश में यह पुस्तक अगर पूरी कर सके तो मैं इस प्रयत्न को सफल समझूंगा।

रतलाम-यात्रा में,
६-११-४६.



वैजनाथ महोदय

अनुक्रमिका

१ देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात	१
२ रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था	३
३ नरेश और उनका शासन	७
४ वे दावे और उनकी वास्तविकता	१६
५ रियासतें और देशव्यापी जागृति	३३
६ नरेन्द्र मण्डल की घोषणा	५५
७ मंत्री मण्डल का मिशन	६१
८ नरेशों की प्रतिक्रिया	७४
९ जनता की प्रतिक्रिया	८८
१० रियासतों का समूहीकरण	९२
११ आज के प्रश्न	१०२

परिशिष्ट

(१) संधिवाली चालीस रियासतें	११७
(२) छैः प्रमुख रियासतें	११८
(३) धारासभा वाली रियासतें	१२०
(४) हिन्दुस्तान की कुल रियासतें	१२२
(५) रियासतों का वर्गीकरण	१४७
(६) लोन-परिणद्	१४८
(७) नमूने का विधान	१६०
(८) नरेन्द्र मण्डल	१६४

रियासतों का सवाल

पूर्व-स्वरूप

: १ :

देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात

रियासतों की समस्याओं पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि उनके बारे में कुछ जरूरी बातें हम जान ले। भारतवर्ष में कुल ५६२ रियासते हैं। (लोक-परिपद के प्रकाशन में इनकी संख्या ५८४ है।) रियासतों का कुल रकबा ७,१२,५०८ वर्ग मील और जन-संख्या ६,३१,८६,००० (सन् १९४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार) है। क्षेत्र के हिसाब से यह समस्त देश का ४० प्रतिशत और जन संख्या के लगभग २३-२४ प्रतिशत है।

मोटे तौर पर रियासते दो हिस्सों में बंटी हुई हैं।

(१) सैल्यूट स्टेट्स (जिनको सलामी का हक है)।

(२) नॉन सैल्यूट स्टेट्स (जिनको सलामी का हक नहीं है)।

२. हिन्दुस्तान में कुल १२० सलामी की हकदार रियासते हैं और ४४२ ऐसी रियासते या जार्गारे हैं, जिनको सलामी का हक नहीं है।

रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था

मारेट्यून्चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पहले जिन रियासतों का सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारों से था, बाद में उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध सीधा गवर्नर जनरल से कर दिया गया है। परन्तु इनका नियन्त्रण प्रायः एजन्ट के मार्फत ही होता रहता है।

भारत सरकार का पोलिटिकल डिपार्टमेंट भारतवर्ष की तमाम रियासतों के शासन के लिये जिम्मेवार है। यह सीधा वाइसराय के मातहत काम करता है। पर उन्हें तफसीलों की तरफ ध्यान देने का अवकाश कहाँ से हो ? इसलिए असल में सारे महकमे का नियन्त्रण पोलिटिकल सेक्रेटरी के हाथों में ही रहता है। वाइसराय को तमाम जानकारी अपने इस सेक्रेटरी से ही मिलती है, जिसके मातहत और भी कितने ही ऑफिसर हैं जिन्हें एजन्ट टु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट कहते हैं।

एजन्ट टु दी गवर्नर जनरल के मातहत अनेक रियासतें होती हैं और और उसका सम्बन्ध सीधे वाइसराय से होता है। उसके मातहत अनेक पोलिटिकल एजन्ट होते हैं। इन प्रत्येक के मातहत कुछ रियासतें हैं। रेसिडेन्ट उस पोलिटिकल ऑफिसर का नाम है, जो अकेली बड़ी बड़ी रियासतों पर ध्यान देता है।

इन तमाम अफीमरों को बहुत व्यापक और अलग अलग अधिकार होते हैं। उनका न तो कहीं खुलासा है और न ऐसा खुलासा करने का यत्न कभी किया गया है। यह रियासत का महत्त्व, नरेश का स्वभाव और पोलिटिकल ऑफिसर की मर्जी पर निर्भर रहता है। कभी कभी तो वह बहुत छोटी छोट्टी बातों में भी दस्तदाजी करता है, तो कभी नरेशों से बड़े बड़े

वृत्तित असाध हो जाने पर और भयंकर कुशासन होने पर भी हस्तक्षेप करने में इन्कार कर देता है। राजा अगर कमजोर है तो रोजमर्रा की बातों में भी पोलिटिकल एजेंट टांग अडाने लगता है, तो कभी राजा के दरबंग होने पर वह बहुत मोच समझ कर दस्तन्दाजी करने की उल्ट देखता है। हाँ उसे हमेशा सन्त्राज्य सन्कार और भास्त सन्कार की नीति और हिदायतों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। फिर इनकी सत्ता रियासतों के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है। आम तौर पर छोटी रियासतों पर इन अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार होते हैं। पर मन्ने अन्वज की बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि ये अधिकार क्या होते हैं। सारा काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिनके कारण नंगों पर इन महक्मे का भयंकर आतंक रहता है। पर कोई इसका अर्थ यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिमैण्ड के पाम इन नंगों की शिकायत ले कर जावे तो वह उनकी सहायता करता होगा। ऐसा जग भी नहीं। डिमैण्ड तो जैसा अपनी सुविधा देयता है वैसा करता है। इन्ने तो साम्राज्य न मन्तव्य है। वह नंगों को जन जागृति का डर दिखाता रहता है और जनता को सन्त्रियों टांग मुलहनामों का बताना बताकर इनकी निरकुशता को बख्तर रहता है। इस तरह अपने इस दुधार के बलपर उसने अपनी निरकुशता की रक्षा अब तक की है।

इसके मातहत अट्टाईस बड़ी, जिनके राजा-नवाबों को सलामी का हक है, और सत्तर छोटी रियासते हैं, जिनके नंगशों को सलामी का हक नहीं है।

डेक्कन स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन् १९३३ में उन रियासतों को अल्लहदा करके किया गया, जो अब तक बम्बई के मातहत थी। इनका एजेन्ट कोल्हापुर का रेजिडेंट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी-छोटी सोलह रियासते कर दी गई हैं।

ईस्टर्न स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण भी सन् १९३३ में हुआ। अब तक जो रियासते मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा के मातहत थी, उन्हें इस एजेन्सी में रख दिया गया है। इनकी संख्या ४० है। मयूरभंज, पटना, बस्तर और कालाहण्डी इनमें से मुख्य हैं। इनका एजेन्ट राची में रहता है, जिसके मातहत एक सेक्रेटरी और एक पोलिटिकल एजेन्ट भी हैं, जो सम्वलपुर में रहता है।

गुजरात स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण भी उसी वर्ष (१९३३) में किया गया था। बम्बई की मातहत की ग्यारह बड़ी सलामी की हकदार और सत्तर छोटी रियासते या जागीरे इसके नियन्त्रण में कर दी गई हैं। बड़ौदा का रेजिडेंट इनके लिए गवर्नर जनरल का एजेन्ट है। इन रियासतों में राजपूतपला मुख्य है। रेवा-कॉटा एजेन्सी भी इसी एजेन्सी के मातहत है।

मद्रास स्टेट्स एजेन्सी इनसे दस वर्ष पहिले बनी थी। इसके मातहत त्रावणकोर और कोचीन ये दो बड़ी रियासते हैं। एजेन्ट का मुकाम त्रावणकोर में रखा गया है।

सीमांत एजेन्सी के मातहत चित्राल सहित पांच रियासते हैं। सीमा-प्रान्त का गवर्नर खुद इनके लिए एजेन्ट भुकरर है।

पंजाब स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण १९२१ में हुआ था। इसके मातहत १४ रियासते हैं, जिनमें भावलपुर के नवाब मुस्लिम और पटियाला

के नरेश सिख हैं। सन् १९३३ में खैरपुर को भी इन्हीं के साथ इस एजेन्सी में जोड़ दिया गया है।

राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी का सदर मुकाम माउण्ट आबू पर रखा गया है। बीकानेर और सिरोंही इनके सीधे मातहत हैं। इनके अलावा बार्ड्स दूसरी रियासतें हैं, जो जयपुर के रेजिडेंट, मेवाड़ के रेजिडेंट, दक्षिणी राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकल एजेंट, पूर्वी राजपूताना स्टेट्स के एजेंट और पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के रेजिडेंट के मातहत कर दी गई हैं। इनमें से टोंक और पालनपुर के शासक मुस्लिम हैं और भरतपुर तथा धौलपुर के नरेश जाट हैं। शेष में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर प्रधान राजपूत राज्य हैं।

वेस्टर्न इण्डिया स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन् १९२४ में किया गया। तब से काठियावाड़ की रियासतें, तथा कच्छ और पालनपुर की एजेन्सियों को बम्बई के मातहत से हटाकर गवर्नर जनरल के मातहत रख दिया गया। महीकांठा एजेन्सी को भी सन् १९३३ में इनके साथ जोड़ दिया गया। इनका एजेंट राजकोट में रहता है, जिसके मातहत, साबरकांठा, तथा पूर्वी और पश्चिमी काठियावाड़ के पोलिटिकल एजेंट्स काम करते हैं। इन सबके मातहत कुल मिलाकर कच्छ, जूनागढ़, नवानगर, और भावनगर सहित, सोलह सलामी के एकद्वार नगेशों की ओर दो सौ छत्तीस रियासतें या जार्जरें छोटी हैं, जिनके शासकों को सलामी का एक नहीं है। इनके अलावा भी प्रांतीय सरकारों के मातहत कुछ रियासतें रह गई हैं। उदाहरणार्थ—

आन्ध्र प्रदेश में— मणिपुर तथा म.प्र. और जलिया की १६ पहाड़ी रियासतें।

बंगाल में—बूच दिवार और डिपुर

पंजाब में—जिमला की पहाड़ियों की पट्टा पर छोटी रियासतें जिनमें सबसे बड़ी नरहर है।

युक्त प्रान्त में—रामपुर, काशी, जिनका निर्माण १६११ में हुआ और हिमालय की टेहरी गढ़वाल रियासत ।

: ३ :

नरेश और उनका शासन

देशी राज्यों के शासकों अर्थात् राजाओं और नवाबों का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन तथा शासन लगभग एकसा होता है । कुछ मामूली फेरफार के साथ उनकी टकसाली कहानी यो कही जा सकती है:—

नरेशों का बचपन अत्यन्त लाड प्यार में गुजरता है । महली में इनकी माता ही अकेली रानी नहीं होती । उसके अलावा इनकी कितनी ही सौतेली माताएँ होती हैं, जिनमें बेहद ईर्ष्या द्वेष होता है इस वजह से युवराज की जान सदा खतरे में रहती है । इस खतरे से बचाने के लिए उसे लगभग कैदी की सी हालत में रखा जाता है । हमेशा खुशामद का वातावरण रहने के कारण बचपन से ही इनकी आदते बिगड़ने लगती हैं ।

राजकुमारों की शिक्षा के लिए देश में राजकोट, अजमेर, इन्दौर और लाहौर इस तरह चार कॉलेज हैं । सफन, चरित्रवान, और प्रजा की सेवा करने वाला शासक बनाने की अपेक्षा इन्हें यहाँ आजाधारक साम्राज्य सेवक बनाने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा है । इसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजने की प्रथा भी रही है । यह उच्च शिक्षा इनके लिए और भी हानिकर साबित होती है । युवराज अपने प्रजाजनो से दूर पड़ जाता है, जवानी के जोश में वह विदेशों में अनेक नये आचार, नये विचार और कई ऐसी नई बातें सीख लेता है कि अपने प्रजाजनो से प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के बजाय वह उनको मूर्ख और गंवार समझ उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का यत्न करने लगता है, यहाँ

तक कि अधिकार मिलने के बाद भी वह अपना अधिकार समझाकर
 दिवाता है। माननीय स्व० श्री निवास शर्मा ने एक बार नगेशों की विदेश
 यात्राओं के बारे में कहा था “आप लन्दन, पेरिस या किसी भी पैमाने पर
 शहर में चले जाइए। वहाँ आपको कोई हिन्दुस्तानी गाना गकर मिल
 जावेगा, जो अपनी अतुल्य संगति में वहाँ के लोगों को चकित कर रहा
 होगा और अपने संघर्ष में आने वालों को गति और ऊट दाना रहा होगा।”

नगेशों के चरित्र और तरह-तरह के दृष्टिगत व्यक्तियों के विषय में कुछ न
 कहना ही भला है। बड़े बड़े अंग्रेज पुर, वहाँ का गन्दा वातावरण और
 उनके अन्दर कैदी कासा जीवन दिवानेवाली अस्वस्थ सन्निधि दामिर्ग
 और ग़ैलों का दयनीय जीवन ही इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मन्तु फिर भी
 उन्हें इतने में नगेप नहीं होता। अपने सैर-समाये तथा देन-वेदेन की
 यात्राओं में यथा संभव इनके अन्तःपुर की और भी वृद्धि होती ही रहती है।

फण्डे की मिले हैं। दूसरी कुछ रियासतों में जिन-प्रेस वगैरा है। और जहाँ कुछ ऐसे कारखाने हैं वही कुछ थोड़ी सी जान और जागृति भी दिखाई देती है। अन्यथा तमाम रियासतों एक दम पिछड़ी हुई हैं। खेती और सरकारी नौकरी के अलावा वहाँ आजीविका का कोई जरिया नहीं होता। तमाम पढ़े-लिखे लोग और साहसी व्यापारी अन्धकार और प्रतिक्रिया के इन अधे कूओं से निकलकर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पास पड़ोस के ब्रिटिश प्रान्तों में चले जाते हैं। राजपूताने की रियासतों में आज भी गुलामी की कुप्रथा कायम है। दारोगा, चाकर, हुजुरी वगैरा गुलाम जातियों का वहाँ पशुओं के समान देन लेन होता है। इनकी न कोई संपत्ति होती और न घरबार। वे अपने मालिकों की संपत्ति होते हैं और लड़कियों की शादी के समय दामदासियों के रूप में इन्हें लड़कियों के साथ भेज दिया जाता है और तब से ये इस नये परिवार की संपत्ति बन जाते हैं।

बेगार लग-भग सभी रियासतों में जारी है यद्यपि कुछ रियासतों में वे कानूनन मना हैं। नाई, धोत्री, खाती, दरजी सबको बेगार देना पड़ती है। छूटने की कोई आशा नहीं होती।

रियासतों में कर तो प्रायः अधिक होते ही हैं। किन्तु इसके अलावा छोटी छोटी रियासतों में अनगिनत लाग-बागें होती हैं। वैरिस्टर चुडगर अपनी पुस्तक “इण्डियन प्रिन्सेस” में लिखते हैं किसानों की ६० प्रतिशत से भी अधिक आय इन करों में ही चली जाती है।

कानून असल में प्रजा की इच्छा और जरूरत के अनुसार उसीके द्वारा बनाये जाने चाहिये। इस अर्थ में रियासतों में कोई कानून नहीं होता। कानून और शासन दोनों वहाँ राजा के व्यक्तित्व में केन्द्रित होते हैं। कानून उसके जयान से निकलते हैं और दौलत उसकी नजर में होती है। वही वही अंग्रेजी इलाकों में प्रचलित कानून जारी कर दिये गये हैं। पर उनके भी कोई स्थायित्व नहीं होता। नरेश जब चाहे उन्हें उठा-

सकना है, संशोधन कर सकता है या सुलझी कर सकता है। जिनको जी चहे उठाकर मनमाने समय तक जेल भिजवा सकता है, या रियासत से निकाल बाहर भी कर देता है और इसके लिये किसी कारण आरोप या जाँच की जरूरत नहीं होती। हर किसी की सम्पत्ति जप्त की जा सकती है और अदालतों में चल रहे मामले भी रोके जा सकते हैं। कोई प्रजा जन अपने नरेश पर उसके अफसरों के खिलाफ बचन भंग या अधिकारों के अपहरण के लिये अदालत में मामला भी नहीं चला सकता। किसी सरकारी अफसर के द्वारा अगर ऐस, गुनहा भी हो जाय, जिसका सरकार या सरकारी काम में कोई तात्लुक न हो तो भी वगैर नरेश की आज्ञा के उसके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता। राज्य में सभा-संगठन करने और अखबारों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रायः कोई कानून नहीं होता। छोटे राज्यों में वगैर राजा सा० की आज्ञा के कोई सभा-सम्मेलन नहीं किये जा सकते और अगर कहीं कोई ऐसी सभा बगैर कर भी लेता है तो पौरन् पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐसी दस्तन्दाजी के खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता।

सरकारी नौकरियों के विषय में कोई खाम नीति नहीं होती। नवने बड़ा अधिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रतिनिध य रिश्तेदार होता है या पोलिटिकल डिपार्टमेंट का अपना आदमी होता है।

दीवान अपने साथ बाहरी आदमियों का प्रायः एक दल लाता है जो उसके विश्वासी होते हैं। जो भी ग्राम नीर पर रियासतों में प्रायः ऊँचे शोहदे पर बाहरी आदमियों को ही रक्खा जाता है जो स्थानीय आदमियों की अपेक्षा अधिक प्राणधारक और बहादुर माने जाते हैं। पर मान्यता एकदम गलत भी नहीं। क्योंकि इन बाहरी आदमियों का सर्वांग दीवान या नरेश अपने हैं। जनता में उगही कोई खाम दिखाने की नहीं करने के कारण नरेशों और उनके दीवानों के भले बुरे हुक्मों के प्रभाव में रहने के कारण ही यह स्थिति रह रही होती। पर यद्यपि इन स्थानों पर

स्थानीय आदमी होते हैं, तो उनके मित्र, रिश्तेदार जात-विरादरी वाले, जान पहचान के लोग भी समाज में होते हैं। अतः कोई भी बुरी बात करते समय स्थानीय आदमियों को यह ख्याल हो सकता है कि ये सब लोग उन्हें क्या कहेंगे ? बाहर के आदमियों को ऐसा कोई विचार या डर नहीं होता। इसलिए नरेशों और दीवानों की निरकुशता में ये उनका पूरा साथ देते हैं। राज्य के हिसाब-किताब में भी सफाई कम ही रहती है। राज्य-कोष में से कितना नरेश पर तथा उसके परिवार पर खर्च होता है इस विषय में निश्चित मर्यादा बहुत कम रियासतों में होती है और जहाँ यह होती है वहाँ भी उसका पूरे विवेक और कड़ाई के साथ शायद ही पालन होता है। अनेक नरेश रियासत के खजाने और जेब-खर्च में बहुत कम भेद मानते हैं और उनकी विदेश-यात्राएँ, प्रीतिपात्रों को इनाम तथा अन्य प्रकार से जो खर्च होता है वह मुकर्रर-खर्च से कहीं बढ़ जाता है। नरेन्द्र मण्डल के १०६ सदस्य नरेशों में से केवल २६ नरेशों ने अपना जेब-खर्च निश्चित किया है।

छोटी रियासतों में यह विवेक और भी कम रहता है। फलतः प्रजा जनो की सेवा और जीवन-सुधार सम्बन्धी कामों के लिए कमी पड़ जाती है और जब कभी इन कामों के लिये माँग की जाती है तो यही जवाब मिलता है कि बजट में कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारों की तरफ से ऐसा जवाब मिलना तो स्वाभाविक ही है। पर अब खुद प्रजाजनो को नरेशों का खानगी खर्च कम करने पर जोर देना चाहिए। उनकी अब निश्चित प्रतिशत मुकर्रर कर दी जाय और वह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा के लिये राज्य-कोष का अधिक से अधिक हिस्सा बचाया जा सके।

व्यक्तिगत रूप से नरेश राज-काज में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। हमेशा स्वार्थियों और खुशामदियों का झुण्ड उन्हें घेरे रहता है, जो इस बात की न्यून सावधानी रखता है कि उनके गिरोह को और उनके जैसे विचार वालों को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार का आदमी नरेश तक न

प्रह्वेजने पावे जिससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें। कागजात और मिल्ले वरों नगेशों की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं। खुद नगेश इतने मुस्त, विलासी और निष्क्रिय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि अनेक मर्तवा उन्हें बह भी पता नहीं रहता कि किन मामलों में उन्होंने किस प्रकार के निर्णय पर हस्ताक्षर किये हैं।

बहुत कम रियासतों में वैधानिक शासन के चिन्ह हम देखने हैं। कुछ बड़ी-बड़ी रियासतों में धारा सभायें बन गई हैं। पर उनमें सरकारी और गैर सरकारी नामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है। और इतने पर भी अधिकार कुछ-सी के बराबर हैं। ये धारासभायें क्या हैं, निरी शब्द-विवाद सभायें हैं। उनमें निर्णयों का महत्व सलाह ने अधिक नहीं होता। जिन्हें नगेश किसी हालत में मानने को बाध्य नहीं हैं।

केवल चौतीस रियासतें ऐसी हैं, जिनमें न्याय विभाग तथा शासन विभाग को अलग-अलग रखने का यत्न किया गया है। वरना अधिकांश इनमें प्रायः कोई तमीज नहीं करती। न्याय विभाग पर राजा का पूरा नियन्त्रण होता है। चालीस रियासतों में हार्डकोर्टों की स्थापना हो चुकी है जिनमें से कुछ में अंग्रेजी भारत की तरह कानून के अनुसार न्याय देने का यत्न होता है। पर याद रहे, राजा पर किन्हीं कानून की सत्ता नहीं होती। यही नहीं, बल्कि उसके आदेशानुसार काम करने वाले कर्मचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है। अधिकांश रियासतों में तो निष्चित आदम के अभाव में मनमानी ही चलती रहती है। प्रजाजनों या पीड़ितों को शिकायत या अपील करने तक की गुत्ताइश नहीं रहती। जब फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एकदमना तो नियामकी जनत के मौलिक अधिकारों का चिठा तब बनाना असंभव हो गया क्योंकि उस पर नगेश राजी हो नहीं देना चाहते थे। यह तो हमारा बड़ा निराशा का काम।

छोटी रियासतों की कहानी और भी दुःखदायी है। उनके नरेश तो एक दम निरकुश होते हैं। अपनी सत्ता का केवल एक ही उपयोग वे जानते हैं। प्रजाजनो को मनमाना तग करना, उनसे पैसा चूसना, और अपने ऐशो-आराम में तथा दुर्गुणों में एव व्यसनो में उसे बरबाद करना। न्याय-विभाग और पुलिस अगर होते भी हैं तो पतित और भ्रष्ट। अन्याय और जुल्म के साधन बन जाते हैं। कर अन्यायपूर्ण और असह्य होता है। भाषण, सगठन और मुद्रण जैसी मामूली नागरिक स्वाधीनता का भी वहाँ नामोनिशान नहीं होता।

नरेश अपने स्वार्थ और विषय-दिलासों पर अनियन्त्रित खर्च करते रहते हैं। लोग अत्यन्त घरिद्र है। लाखों लोगो को 'दिन में एक बार' भी 'पेट भर भोजन नहीं मिल सकता। राज और राज के कर्मचारी प्रजाजनों को यमराज के समान भयकर और दुष्ट मालूम होते हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि उनका जन्म प्रजाजनो से केवल पैसे बसूल करने के लिये ही हुआ है। और प्रजाजनो को उनकी टहल-चाकरी करने के लिये बनाया गया है। इनके अत्याचारों का वर्णन करना असंभव है। वह जानते हैं, जिनपर घीतती है।

लन्दन टाइम्स ने सन् १८५३ में रियासतों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था जिसमें छोटी बड़ी रियासतों में चल रही अन्धेर का चित्र और कारण भी खूब अच्छी तरह थोड़े में प्रकट किया गया है:—

“पुरुष के इन निस्तेज और निकम्मे राजा नामधारियों को जिन्दा रख कर हमने उनके स्वाभाविक अन्त से उनकी रक्षा कर ली है। बगावत के द्वारा प्रजाजन अपने लिए एक शक्तिशाली और योग्य नरेश ढूँढ़ लेते हैं। जहाँ अब भी देशी नरेश है, हमने वहाँ के प्रजाजनो के हाथों से यह लाभ और अधिकार छीन लिया है। यह इल्जाम सही है कि हमने इन नरेशों को सत्ता से हटा दिया और उनकी जगह पर उनके बरी ईश्वर का नाम है।

नरेशों के निरंकुश निजी स्वर्च, इनकी शान-शौकत, व्यमनाधीनता, अजीब और निकम्मे रस्मों-रिवाज और इन सब में होने वाली धन की बरबादी, कुत्ते, घोड़े, महलों में पलने वाले असंख्य नौकर-चाकर और बाँदा बाँदियों की फौज, बेरहम मारपीट, कानूनी शासन का सर्वथा अभाव, किसानों का शोषण इत्यादि ने रियासती जनता को राजनैतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इतना पीछे रख दिया और गिरा दिया है कि जिसकी ठीक ठीक कल्पना बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासतों के प्रश्न को सुलझाने में हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का रहेगा तभी उसका उचित हल हम निकाल सकेंगे।

: ४ :

वे दावे और उनकी वास्तविकता

नरेशों का और उनके शासन का यह एक मोटा सा चित्र है। इसकी तफ़सीलों में आज के बदले हुए जमाने में जाना बेकार है। आज तो भूत की अपेक्षा भविष्य की समस्याओं पर ही अधिक विचार करने की जरूरत है। फिर भी प्रश्न की सारी बाजुओं का यथावत् ज्ञान हो जाय इस ख्याल से रियासतों और नरेशों की पूर्वस्थिति का जो अब तक लगभग पत्रों की रसो कायम है—एक मोटा सा चित्र दे दिया गया है। हर कोई जानता है कि किसी भी स्वतन्त्र देश में नरेशों का ऐसा वर्ग एक गिनत भी नहीं टिक सकता। पर हम ब्रिटेशी सत्ता ने उसे यहाँ अपने स्वार्थ के लिए अब तक अन्धे के बल पर टिका रखा है। मन् १९२१ में हिन्दुस्तान में जिन उन्नत राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, हिन्दुस्तान के प्रश्न पर ब्रिटिश के विचारशील लोगों का भी ध्यान जागृत हो गया। परन्तु सत्कार भी इन बातों को जान गई कि अब राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति का नरेशों पर असर है और शासन-दुश्चार के तर्कों की बर्बाद हुई। पर दाँद था कि अब शासन का नया स्वरूप नया शासन ही

हो सकता है। पर इस सघ मे रियासतो की स्थिति क्या होगी? उनका भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उनका सम्बन्ध कैसा होगा, इत्यादि प्रश्न खड़े होते गये। और राज्यों मे उत्तरदायी शासन स्थापित करने की माग होने लगी।

इस सम्बन्ध मे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेशों का सवाल बिलकुल जुदा है। उनका सम्बन्ध सीधा सम्राट से है। साम्राज्य सत्ता उनके साथ सधियों और सुलहनामों से बंधी है। और इनके अनुसार नरेशों के प्रति सार्वभौम सत्ता के कुछ निश्चित कर्तव्य हैं जिनका पालन करने के लिए वह वचन बद्ध हैं। इस चर्चा ने नरेशों को भी अपनी सन्धियों की याद दिलाई। उसमे उन्होंने देखा कि हमारी स्थिति तो अंगरेजी सल्तनत के साथ मे समानता की है और हमारा सबंध सीधा सम्राट से है। नरेशों ने सोचा कि इस हलचल मे हमें भी अपनी पहले की सी स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके तो कितनी अच्छा हो। नवसंगठित नरेन्द्र मण्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशों मे शायद थोड़ी सी वर्ग चेतना पैदा कर दी। उन्हें एक लम्बे असें से यह शिकायत थी कि उनके अधिकारों पर पिछले सौ वर्षों मे अनेक बार गैर कानूनी और अन्याय पूर्ण आक्रमण हुए हैं। इस अन्याय की शिकायत करते हुए नरेश अपनी तरफ से कुछ दावे भी पेश करना चाहते थे। इसलिए सन् १६२७ में उनमे से कितने ही नरेशों ने यह मांग भी की कि साम्राज्य सत्ता के साथ उनके सम्बन्धों का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है और फिर उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार हो।

लॉर्ड बर्कन हेड उस समय भारत मन्त्री थे, उन्होंने इसके लिए एक कमिटी की नियुक्ति कर दी, जिसके तीन सदस्य थे—सर हार्कोर्ट बटलर मि सिडयूसर पील और मि होल्डस्वर्थ। कमिटी से कहा गया कि वह रियासतों और सार्वभौम सत्ता के बीच के सम्बन्धों के विषय में खासतौर पर—

(क) सम्बन्धे इकरागननों और समझे तय

(ख) नदियाँ, व्यवहार, एवं अन्य कार्यों में उत्तम सार्वजनिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट करे।

समिति सार्वजनिक सत्ता और रियासतों के बीच के आर्थिक सम्बन्ध और सैनिक के विषय में भी जांच करे और दोनों पक्षों के बीच अधिक संतुलनपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और भी सिफारिश करे, जो उसे उचित जान रहे।

आज की रियासतें तीन वर्गों में बांटी जा सकती हैं

वर्ग सख्या रकबा मीलो में जन-सख्या आय करोड़ों में

(१)—वे रियासते १०८ ५,१४,८८६ ५,०८,४७,१८६ ४२,१६
जिनके नरेश नरेन्द्र-
मण्डलके सदस्य हैं ।

(२)—वे रियासते १२७ ७६,८४६ ८०,०४,४१४ २.८६
जिनका प्रतिनिधित्व
नरेन्द्र मण्डल में
उनके नरेशों द्वारा
अपने ही श्रद्धर से
चुने १२ प्रतिनिधियों
द्वारा होता है ।

(३)—इस्टेटे, जागीरे ३२७ ६,४०६ ८,६१,६७४ .७४
वगैरा ।

रिपोर्ट में जो सुझाव हैं वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ग की रियासतों से सम्बन्ध रखते हैं । उनमें लिखा है—

“रियासतों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति में समय-समय पर कई परिवर्तन हुए—

(क) शुरू में निश्चित क्षेत्रों और विषयों को छोड़ कर रियासतों के भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप न किया जाय, यह नीति रही ।

(ख) बाद में लार्ड हैस्टिंग्स की सलाह के अनुसार रियासतों को मातहत के तौर पर रक्खा गया और उन्हें शेष भारत से सावधानी के साथ अलग रखने की कोशिश की गई । कालान्तर में यह नीति भी बदली और

(ग) आज गियासते तथा सार्वभौम सत्ता के बीच कुछे-कुछ इस प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक आगे बढ़ें ।

“तदनुमार ता० ८-२-१९२१ को शाही फर्मान द्वारा सम्राट ने नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना की । कुछ बड़े-बड़े नरेशों ने उसमें जाने से इन्कार कर दिया । फिर भी मण्डल का निर्माण और उसकी स्थायी समिति की रचना एक जबरदस्त घटना थी । क्योंकि इसमें सरकार ने गियासतों को एक दूसरे से और शेष भारत से अलग रखने की नीति को छोड़कर उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की है ।

“हम भी इस बात को मानते हैं कि गियासतों और सार्वभौम सत्ता के बीच का सम्बन्ध दृग्ग्रन्थ उनसे और सम्राट के बीच का सम्बन्ध ही है । और उनके साथ हुई सन्धियाँ मरी नहीं, जिन्दा और बन्धनकारक हैं । यद्यपि ऐसी सन्धियोंवाली गियासतों की मर्याद कुल चालीस ही है । परन्तु यहाँ सन्धियों में इकरागनामी और सनदों का भी समावेश कर दिया गया है ।

“पर सार्वभौम सत्ता और रियासतों के बीच डेढ़ सौ वर्ष पहले की गई सन्धियों के आधार पर कायम किया गया यह सम्बन्ध केवल सौदे की वस्तु नहीं है । यह तो जैसा कि प्रो० वेस्ट लोके ने कहा है, इतिहास, सिद्धान्त और प्रत्यक्ष वर्तमान की घटनाओं ने उत्पन्न परिस्थिति और अन्य परिवर्तनशील नीति के आधार पर बढ़ने वाली दिनात्मयील जिन्दा वस्तु है ।”

सार्वभौम सत्ता को ही है। वही अन्तराष्ट्रीय मामलों में रियासतों का प्रतिनिधित्व कर सकती है और उसके इस हक को कानून ने भी मजूरी दी है, जो उसे सन्धियों से और अधिकांश में रूढ़ि तथा प्रत्यक्ष व्यवहार से प्राप्त है।

“अभी-अभी तक सार्वभौम सत्ता केवल अन्तराष्ट्रीय मामलों में ही नहीं, उनके आपसी व्यवहारों में भी रियासतों की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करती रही। परन्तु वर्तमान शताब्दी में परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि रियासतों के आपसी सम्बन्ध में आवागमन वगैरा बहुत बढी गये हैं।

“भीतरी उग्रद्वो या बग़ावतों से रियासतों की रक्षा करने के लिये सार्वभौम सत्ता बचन बद्ध है। यह कर्तव्य उसे सन्धियों, सनदों वगैरा क शतों के अनुसार प्राप्त है। नरेशों के अधिकार, प्रतिष्ठा वगैरा को अनुगुण बनाये रखने के सम्बन्ध में स्वयं सम्राट ने भी बचन दिया है।

“सम्राट के इस बचन के अनुसार उनपर यह कर्तव्य-भार भी आता है कि अगर किसी नरेश को हटाकर रियासत में दूसरे प्रकार के बानी लोक तंत्री शासन की स्थापना का प्रयत्न हो, तो उससे भी नरेश की रक्षा की जाय। और अगर इस तरह के प्रयत्न की जड़ में कुशासन नहीं, बल्कि शासन के परिवर्तन के लिये जनता की व्यापक माँग हो तो सार्वभौम सत्ता को नरेश की प्रतिष्ठा, अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा तो करनी ही होगी, परन्तु साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुझाना होगा, जिससे नरेश को न हटाते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके। पर आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है और शायद आगे भी न आवे, अगर नरेश का शासन न्यायपूर्ण और सक्षम होगा और खास तौर पर लॉर्ड इर्विन की सलाह पर, जिसको नरेन्द्र-मण्डल ने भी माना है, देशी नरेश अमल करे।” इस घोषणा में लॉर्ड इर्विन ने नरेशों को सलाह दी है कि वे अपना जेव-

स्वर्च बाँध ले, रियासत की नौकरियों में स्थायित्व निर्माण करें और न्याय-विभाग को स्वतंत्र एवं तेजस्वी बना ले ।

“ फिर भी नरेशों के एक सचमुच गम्भीर भय (यह कि कहीं सार्वभौम सत्ता रियासतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को उनकी सम्मति के बगैर ब्रिटिश भारत में आनेवाली भारतीय सरकार को—जो कि धारासभा के प्रति जिम्मेदार होगी—न सौंप दे) की तरफ ध्यान दिलाये बगैर हम नहीं रह सकते । इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर अपनी यह राय बलपूर्वक पेश कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि नरेशों और सार्वभौम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है । अतः नरेशों को जब तक वे राजी न हो जायें, भारतीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार रहने वाली किसी नई सरकार के आधीन न सौंप दिया जाय । ”

नरेशों का भय और साम्राज्य सरकार की चिन्ता दोनों अध्ययन करने की वस्तु हैं । इतने लम्बे अरसे से जो प्यारे आश्रित रहे हैं, उनको अंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के अथाह समुद्र में कैसे ढकेल दें ? यह प्रेम सम्बन्ध कितना पवित्र है, नरेशों को उनकी तथा-कथित मन्धियों के अनुसार ब्रिटिश सरकार के मातहत कितना सम्मानजनक (या अपमानजनक) स्थान रहा है तथा इस सम्बन्ध में सार्वभौम सत्ता का कितना स्वार्थ है इसका पता भी बटलर कमिटी की निष्कारिशो और रिपोर्टों के अध्ययन से लग सकता है ।

भारतीय नरेशों को अपने राजत्व की रक्षा की बड़ी चिन्ता है और इनके लिये वे अपने पुरखों के साथ की गई मन्धियों बर्गस की दुहाई देते हैं । पर दरअसल वे साम्राज्य सरकार की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि खुद साम्राज्य सरकार का इनमें स्वार्थ था । देखिये साम्प्रतिक स्थिति क्या है :

कमिटी ने देखा सदा पन्न लिये, नरेशों की तरफ ने नियुक्त किये गये नगी वसीलों की वरम भी सुनी । उनके बाद वह जिस नगीसे पर पहुँची है, उसका मार इस प्रकार है—

(अ) रियासतों की कोई अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा न० ३६ में लिखा है :—

“ऐतिहासिक तथ्य से यह कथन मेल नहीं खाता कि ब्रिटिश सत्ता के संपर्क में देशी रियासते जब आईं तब वे स्वतंत्र थीं, प्रत्येक राज्य पूर्णतया सर्व सत्ता धारी ‘सावरिन’ था और उसको वह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक आधुनिक वकील की राय में अन्तराष्ट्रीय कानूनों के नियमानुसार सचमुच अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा कहा जा सकता हो। सच तो यह है कि इन रियासतों में से एक को भी अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रायः सब रियासतें मुगल साम्राज्य, मराठों या सिक्खों की सत्ता के आधीन या मॉडलिक थीं। कुछ को अंग्रेजों ने छोटा बना दिया और कुछ का नया निर्माण किया।”

(आ) उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं थी

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के ४४ वे पैरे में लिखा है:—

यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि आज कल के राजनीतिज्ञों की भाषा में ‘राजत्व’ का तो विभाजन हो सकता है, परन्तु स्वतंत्रता का नहीं। ‘आंशिक स्वतंत्रता’ शब्दों का प्रयोग भी साधारणतया किया जाता है। पर वह तो सरासर गलत है। इसलिये भारत में ‘राजत्व’ या ‘राज-सत्ता’ अनेक प्रकार की पाई जा सकती है। परन्तु स्वतंत्र राज-सत्ता तो केवल ब्रिटिश सरकार ही है।”

असल में जिनको सुल्हनामा कहा जा सकता है, हिन्दुस्तान की २६२ रियासतों में से सिर्फ ४० रियासतों के साथ ही हुए है। (बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा १२)।

शेष रियासतों में से कुछ के साथ इकरारनामे है, तो कुछ को सनदे दी हुई हैं। और जिनके साथ इन दो में से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनका

नियन्त्रण तड़ी और शुरु से चले आये तथा समय समय पर बदलने वाले व्यवहार के अनुसार होता है ।

सुलहनामे १७३० से लेकर १८५८ तक के हैं । ये ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों और नरेशों के बीच व्यक्तिगत हैसियत में नहीं, बल्कि अपनी रियासतों के वैधानिक शासक की हैसियत से पारस्परिक वचाव या सम्मिलित रूप से आक्रमण करने के लिए की गई मित्रता की सन्धियों के रूप में हुए हैं । रियासत (स्टेट्स) शब्द में जनता भी शामिल है ।

ये तमात सुलहनामे एकसे नहीं हैं । जिस वक्त जैसा मौका या हेतु रहा है, वैसी उनकी शर्तें या स्वरूप हैं । इसलिए तमाम रियासतों के लिए अधिकारों या उनके प्रति जिम्मेदारियों का सर्वसामान्य नाप इनमें नहीं पाया जाता ।

इन तमाम सुलहनामों में एक आश्वामन नाफ तौर से प्रकट या अप्रकट रूप में पाया जाता है । यह की अगर नरेश का शासन मन्तोप-जनक रहा तो साम्राज्य सत्ता राज्य की (व्यक्तिगत नरेशों की नहीं) रक्षा करेगी ।

समय और परिस्थितियों के परिवर्तन और राजनैतिक व्यवहारों के नाथ-साथ इन सुलहनामों का महत्त्व और मूल्य बहुत कम हो गया है ।

इन सुलहनामों के बावजूद और न्यतन्त्र रूप में भी मार्चभाूम सत्ता ने प्रत्येक कारणा में देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने के अपने हक का हमेशा दावा किया है और उस पर अमल भी किया है । मार्चभाूम सत्ता के इस अधिकार पर अभी किसी ने उन भी नहीं दिया है ।^१

१ नरेश राज जो भीतरी उपद्रवों में और बाहरी आक्रमणों में मग्न रहें तो अन्तर्गतत्व ब्रिटिश सरकार की शृंखला की प्रतीक हो । उस राज्य के हितों का भंग होना, या किसी विराम के सामने

नरेशों की तरफ से उनके अधिकारों की पैग्वी करने के लिए सर लेस्ली स्कॉट मुकर्रर थे। कमिटी के सामने उनकी बहस कई दिन तक जारी रही। वह सब सुन लेने के बाद बटलर कमिटी ने पाया कि सार्वभौम सत्ता को नीचे लिखी हालतों में रियासतों के मामलों में नियन्त्रण, व्यवस्था और हस्तक्षेप करने का अधिकार है:—

१. वैदेशिक संबंध

(क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या सुलह करना तथा बातचीत करना या अन्य प्रकार से व्यवहार करना।

(ख) रियासतों के अन्दर विदेशी राज्यों के प्रजाजनो की रक्षा करना।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासतों का प्रतिनिधित्व करना।

(घ) सार्वभौम सत्ता अगर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले, तो उसका पालन रियासतों से करवाना।

(ङ) वैदेशिक अपराधियों को (जो रियासतों में पहुँच गये हो)

सौंपने पर रियासतों को मजबूर करना।

(च) गुलाम-प्रथा को मिटाना।

(छ) विदेशी प्रजाजनो के साथ अच्छा सलूक करने पर रियासतों को

की बजह से रियाया के हितों को गम्भीर या दुखदायी हानि पहुँच रही होगी, और इसे दूर करने के लिये किसी उपाय के अवलम्बन की जरूरत होगी तो इसकी अन्तिम जिम्मेदारी सार्वभौम सत्ता की ही होगी। नरेश-गण अपने राज्य की सीमाओंके अन्दर जिस विविध प्रकार की राजसत्ता का उपभोग करते हैं, सो सार्वभौम सत्ता की इस जिम्मेदारी के मातहत ही कर सकते हैं।

मजबूर करना और अगर उन्हें कोई चोट पहुँची हो, तो उसका हर्जाना दिलवाना । (बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा ४६) ।

२ रियासतों के आपसी ताल्लुकात

(क) सार्वभौम सत्ता की अनुमति के बगैर रियासते अपने प्रदेश में से कोई हिस्सा आपल में दे-ले नहीं सकती, बेच नहीं सकती या अदल-बदल नहीं कर सकती ।

(ख) रियासतों के आपसी झगड़ों को रोकने और तय करने का हक सार्वभौम सत्ता का है ।

३. बचाव और संरक्षण

(क) देशरक्षा-विषयक फौज बगैरा का रखना, युद्ध-सामग्री और आवागमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सार्वभौम सत्ता का होगा ।

(ख) गत (१९१४ कं) महायुद्ध में तमाम रियासते साम्राज्य की रक्षा के लिए जुट गईं और उन्होंने अपनी सारी साधन-सामग्री सरकार के सिपुर्द कर दी । यह खुद भी सार्वभौम सत्ता के अधिकार और उनके प्रति रियासतों के कर्तव्यों का एक सबूत है ।

(ग) रियासतों की रक्षा के लिए सार्वभौम सत्ता रियासतों के अंदर जो कुछ भी करना मुनासिब समझे रियासतों को उसे बर सव करने देना होगा ।

(घ) सड़कें, रेलवे, हवाई जहाज, डाकघर, तार, टेलीफोन, ग्राम फोन, रेडियो, सिनेमा, फौजों के आवागमन, शस्त्रास्त्र तथा युद्ध सामग्री की प्राप्ति वगैरा के विषय में युद्ध की दृष्टि में जो भी आवश्यक होगा उसे रियासतों से प्राप्त करने और रखने का अधिकार सार्वभौम सत्ता को है । (बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ४७)

४. भीतरी शासन

(क) जब कभी जरूरत या मांग की जायगी, सार्वभौम सत्ता को रियासतो मे शासन-सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। इसका कारण यो बताया गया है—

“सार्वभौम सत्ता ने भीतरी बगावत से नरेशों की रक्षा करने का जिम्मा तो लिया है, पर उसके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी आ गई है कि वह इस बगावत के कारणों की जाँच करे और नरेशो से यह चाहे कि वे वाजिब शिकायतों को और तकलीफों को दूर करे। सरकार को इसके लिए उपाय भी सुझाने ही होंगे।”

(बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ४७)

(ख) रियासतो मे प्रजाजनो की मांगों को पूरी करने के लिए सार्वभौम सत्ता का यह कर्तव्य और अधिकार भी है कि वह शासन मे परिवर्तन करने की मांग का संतोष करे। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट का ५० वा पैरा खास तौर पर वर्तमान समय मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है—

“सम्राट ने नरेशो के अधिकार और विशेषाधिकारों को एव प्रतिष्ठा तथा शान को ज्यों-का-त्यों कायम रखने का वचन दिया है। उसके साथ उन पर यह भी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर नरेश को हटाकर राज्य मे दूसरे प्रकार की (अर्थात् जनतन्त्रीय) सरकार कायम करने का प्रयत्न किया जाय तो उससे भी उसे बचाया जाय। अगर इस प्रकार के प्रयत्न शासन की बुराई की वजह से हुए तो नरेशो की रक्षा केवल पिछले पैरे मे बताये अनुसार ही होगी। पर अगर इनकी तह मे शासन की खराबी नहीं, बल्कि शासन के तरीके मे परिवर्तन करने की व्यापक मांग होगी तो सार्वभौम सत्ता को नरेश के अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुझाने पड़ेंगे, जिससे नरेश को कायम रखते हुए भी जनता की मांग की पूर्ति की जा सके।

५. राज्य की भलाई के लिए हस्तक्षेप

रियासत के शासन में जब कभी भयंकर खराबी पैदा हो जायगी तो मार्चमौम सत्ता नीचे लिये उपाय काम में लायेगी—

(१) नरेश को गद्दी से उतार देना ।

(२) उसके अधिकारों में कमी कर देना ।

(३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई अपना अफसर मुकदर कर देना ।

(४) वफादारी कबूल करवाना तथा बेवफाई की सजा देना । कई नरेश वफादारी को अपना एक व्यक्तिगत गुण समझते हैं और बार-बार उसका प्रकाशन-प्रदर्शन करते हैं । पर असल में वह एक शर्त है, जिसका पालन उनके लिए लाजिमी है ।

(५) घोर अत्याचारों की सूत में नरेश को सजा देना । ममलन प्रत्यक्ष अन्यायपूर्ण अत्याचार या जंगली सत्ताये आदि ।

(६) गंभीर अपराधों के लिए नरेश को सजा देना ।

(बटनर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ५५)

६. झगड़ों के निपटारे और समझाने के लिए

कभी-कभी कोई रियासत इतनी छोटी होती है कि वह एक सरकार की हमियन में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती । तब भी मार्चमौम सत्ता को धीरे में पढ़कर उसकी सहायता करनी होगी ।

(ब. क. रि. पैरा ५४)

७ समस्त भारत के हित में

उदाहरणार्थ ग्लेड्स-लाइन टालने, तार या टेलीफोन की लाइन ले जाने, ब्रिटिश भारत के सिक्के जारी करने आदि के विषय में ।

(रिपोर्ट पैरा ५५)

८ न्याय-दान में

कई सुलहनामों में इस बात का उल्लेख है कि ब्रिटिश अधिकारियों को देशी रियासतों के अन्दर कोई अधिकार न होगा, परन्तु छावनियों के अन्दर की फौजों या इसी तरह के अन्य मामलों में उनको अधिकार होगा।

(रिपोर्ट पैरा ५६)

९. जनरल

बटलर कमिटी अपनी रिपोर्ट के ५७ वे पैरे में लिखती है—

“सत्ता की सार्वभौमता के ये कुछ उदाहरण और नमूने मात्र हैं। पर असल में तो सार्वभौम सत्ता को सार्वभौम ही रहना है। उसे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निवाहना ही होगा और यह करते हुए समय की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार तथा रियासतों के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार अपने आपको जब जैसी जरूरत हो, सकुचित या विस्तृत बनाना होगा।”

सार्वभौम सत्ता ने रियासतों के बारे में समय समय पर जो घोषणाएँ की हैं और यह कैसे समय समय पर अपने रूप को बदलती रही उसका अध्ययन बहुत मनोरंजक है। जब तक नरेश बलवान रहे, उनकी ताकत को तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार अपनी सोची-समझी नीति के अनुसार शुरू-शुरू में कभी प्रजाजनों के हित की, कभी रियासतों के अन्दर सुशासन की, और कभी उनके प्रति सार्वभौम सत्ता की अपनी जिम्मेदारी की दुहाई देकर रियासतों के भीतरी शासन में हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार का समर्थन और अमल करती रही है। परन्तु बाद की जब प्रजाजनों में जागृति फैली और स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की माग जोरदार धनने लगी, तो अंग्रेजी हुकूमत को दूमरा खतरा दिखाई देने लगा, जो बहुत बड़ा था। अब नरेशों की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों के साथ किये गये पवित्र सुलहनामों, वगैरा का बहाना बनाकर (जिनका पर्दा बटलर कमिटी

ने अग्नी रिपोर्ट में पूरी तरह फाश कर दिया है) उसने लोक-जागृति की कड़ती हुई ताकत को तोड़ने के यत्न किये । इस मनोवृत्ति का विकास नीचे दिये गये भाषणों और घोषणाओं में स्पष्ट दिखाई देता है । मन् १८८१ में लार्ड लिटन ने अपने एक विरूप में स्टेट सेक्रेटरी को लिखा था:—

“अब ब्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यों को बाहरी आक्रमणों से बचाने के कर्तव्य का भार ग्रहण कर रही है । इसके साथ ही वह नेशों की कानूनी सत्ता की रक्षा एवं प्रजाजनों को दुशासन से बचाने के लिए आवश्यक उपायों के अवलम्बन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रही है । समस्त साम्राज्य में शान्ति बनी रहे तथा प्रजाजनों का मन बर्तने में भला हो, इस दृष्टि से उसमें यह जिम्मेदारी भी अपने आप आ ही जाती है कि वह नेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का तरीका और उनका स्वल्प क्या हो और इस बात पर जोर दे कि वे उस में अमल करें ।”

इसी प्रकार लार्ड कर्जन ने कहा है:—

“एक देशी नरेश, जहाँ तक उसका सम्बन्ध साम्राज्य में है, वह सम्राट की बकायार रिश्तावा होने का दावा करता है । पर अपने प्रजाजनों के सामने तो वह एक गैर जिम्मेदार निर्बुद्ध अत्याचारी बना रहता है और जेल तमाशों में तथा बाह्यवर्त बातों में अपना समय और धन व्यर्थ करता रहता है । ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती । उन्हें पर मर्याद करना चाहिए कि उसे जो अधिकार दिया गया है उसका उपयोग वह करे । वह अपने प्रजाजनों का अधिकार तथा स्वयं भी दबे । वह इस बात को समझे कि राज्य का मतलब उसके अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं बल्कि प्रजाजनों की भलाई के लिए है । वह जान ले कि विद्वान्ता या भीखी शासन मारंगीन सत्ता के अन्तर्गत में उसी पद तक नहीं होगा जहाँ वह कि वह ईमानदारी में

कर्त्तव्य करता रहेगा। उसका सिंहासन विषय-विलासो के लिए नहीं, बल्कि कर्त्तव्य-पालन के लिए है। वह न्याय-कठोर आसन है। केवल पोलो ग्राउण्ड, रेस कोर्स और यूरोपियन होटलो में ही वह दिखाई न दे। उसका असली स्थान और काम तथा राजोचित कर्त्तव्य तो यही है कि वह अपने प्रजाजनो में रहे। जो हो, एक नरेश के बारे में कम-से-कम मेरी अपनी कसौटी तो यही होगी। और आगे चलकर यही कसौटी उसके भाग्य का निर्णय करेगी, या तो वह जिन्दा रहेगा या दुनिया से मिट जायगा।

इसी नीति की समर्थन करने वाली घोषणाएँ समय-समय पर सम्राट के अन्य अनेकानेक प्रतिनिधियों ने उदाहरणार्थ लार्ड हाडिङ्ग, लार्ड नार्थब्रूक, लार्ड हैरिस, लार्ड फैन ब्रोक, लार्ड मेयो, लार्ड चेम्सफोर्ड, लार्ड रीडिंग और लार्ड इरविन ने भी की है। परन्तु इनके बाद सम्राट के प्रतिनिधियों की घोषणाओं का सुर एकाएक बदलने लगा। रियासतो में वैधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही अंग्रेज अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे कि अगर देशी नरेश अपने राज्यों में कोई वैधानिक सुधार दे रहे हों तो न तो सम्राट की सरकार उनमें अपनी तरफ से कोई रोड़ा अटकाना चाहती है और न ऐसे सुधार देने के लिए उन पर किसी प्रकार की जोर-जबर्दस्ती करना ही पसंद करती है। पर आगे चलकर वह इससे भी आगे बढ़ी। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश भारत का वातावरण बदलता गया ब्रिटिश सरकार की भाषा भी बदलती गई। वह नरेशों को प्रत्यन्त रूप से इस आशय की सलाह देती गई कि नरेशों को अपने राज्यों के शासन में समयानुकूल परिवर्तन करने चाहिए। पर व्यवहार में इन हिदायतों के अमल पर कभी जोर नहीं दिया गया। बल्कि पोलिटिकल डिपार्टमेंट का रुख प्रायः प्रतिगामी ही रहा है, और नरेश उसके इशारों पर चलते रहे हैं। क्योंकि नरेश सार्वभौम सत्ता के पूरे मातहत हैं, जैसे कि उसके दूसरे अधिकारी, इसलिए वह उनके प्रति अपनी पवित्र जिम्मेदारी की दुहाई देकर भारतवर्ष की

मे रहे। हाँ, बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर भाषा-प्रयोग जरूर बदलते रहे हैं। शोषण के अखरने लायक तरीको को छोड़ दिया गया है और उनके स्थान पर अधिक सूक्ष्म तरीको से काम लिया जाने लगा है। अनिवार्य अवस्थाओं में अपने कदमों को थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी किया गया है। पर यह ध्यान तो सदा ही रहा है कि कहीं सत्ता सम्राज्य सरकार के हाथों से निकल न जाय।

: ५ :

रियासतें और देशव्यापी जागृति

कांग्रेस और लोकपरिषद का कूच

नरेश और सार्वभौम सत्ता जब अपने अपने स्वार्थों की साधना में लगे हुए थे, तब रियासतों की जनता एक दम सोई नहीं थी। उसमें भी जागृति के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। यही नहीं, बल्कि कुछ बड़ी बड़ी रियासतों की जनता तो प्रान्तों के राष्ट्रीय आन्दोलनों के साथ कदम बढ़ाते हुए चलने का यत्न करती थी। अनेक रियासतों में कांग्रेस कमिटियों कायम हो गई थी और रियासतों की जनता इनके द्वारा कुछ करना भी चाहती थी। पर कांग्रेस शुरू से इस मत की रही है कि अभी कुछ समय देशी राज्यों में हस्तक्षेप न किया जाय। पहले हम प्रान्तों में अपनी शक्ति को सगठित करें, यहाँ विदेशी सत्ता से मोर्चा लेकर उसकी ताकत को तोड़ें, तो इसका असर देशी राज्यों के शासन पर अपने आप होगा। विदेशी सत्ता और देशी राज्यों के साथ के सम्बन्ध में उसने कुछ फर्क भी रक्खा है। देशी नरेशों के साथ उसने सदा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की है। उसका पहला प्रस्ताव सन् १८६४ में महाराजा मैमोर की मृत्यु पर शोक प्रकाशन और राज्यपरिवार तथा मैमोर के प्रजाजनो के साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला था। मैमोर नरेश के वैधानिक दृश सन की कद्र करते हुए कहा था कि उनकी मृत्यु से न केवल राज्य की जनता बल्कि समस्त भारतीय जनता जबरदस्त हानि अनुभव करती है।

दूसरा प्रस्ताव सन् १८६६ में नेशों को गद्दी से हटाने के सम्बन्ध में इस आशय का हुआ था कि "भविष्य में किसी नेश के कुशासन के बहाले गद्दी से नहीं हटाया जाय, जब तक कि उनका व्यवहार खुली अशक्तता में जित्त पर सरकार तथा भारतीय नेशों को भी विश्वास में ऐतन्त्रिक न हो जाय।"

लोक-शांति और राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का निदर्शक तीसरा प्रस्ताव कांग्रेस के न गपुर अधिवेशन में हुआ, जिसमें उनमें समान देशी नेशों ने अंगीत की कि "वे अपने प्रजातन्त्रों को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन द्वारा सार दें।"

इसके बाद अन्वयोग का उदरदत्त आन्दोलन आया उसमें देशी नेश और सर्वभौम सत्ता दोनों को अपने भविष्य की निता ही गई और वे अपनी हिली हुई जड़ों को पुनः मजबूत करने की दौड़धूप में लगे। मार्गभौम सत्ता जिन नेशों को अब तक दुर्गि तरह दबती रही, अरगर्भ-कैदेयों की तरह सदा मजबूती में उनकी प्रत्येक हलचल पर बड़ी गजर रखती आई, उन्हें अब मजबूत खींचकर, अपने विचारों में लेकर अपना मजबूत सदास बनाने की उन्नत उमे मजबूत होने लगी। सन् १९०१ के फरवरी मास में कुछ बड़गाढ़ के हुक्म में गेन्द्र सभ्यता की स्थापना की गई। मुक्त मुक्त में नेशों ने इस कदम का बहुत दुःसाह में स्वागत नहीं किया। बड़े बड़े नेश इसमें अलग ही थे। लंदन के गेन्द्रभवन को हटाकर मस्को एक साथ बंटाने वाला यह काम उनके अलग-अलग उन्होंने इसमें शरीक होने में उत्सुक न दिया। पर म प्रत्यक्ष के भला नेशों को उनके शरीक हुए ही और उन्होंने अपने नाम के गिने को कुछ लगे में इसका उपयोग करना मुक्त किया। मार्गभौम सत्ता में प्रत्येक लोच मजबूत करने नेशों ने अपनी निरालों में समान भी दिया। इसका भला और दुःसाह दोनों प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष हुक्म। लंदन के गेन्द्र के लोच मस्को की सत्ता में इसमें इतनी दौड़धूप

असहयोग से चैतन्य प्राप्त होने के कारण रियासती जनता भी सगठित होने लगी। बड़ौदा में तो ठेठ सन् १९१६ में प्रजा मण्डल की स्थापना हो गई थी। काठियावाड़ की रियासतें और भी पहले से सगठित होने लग गई थीं। मैसूर भी आगे बढ़ा। इन्दौर में भी प्रजा परिषद् की स्थापना हुई। पर ऐसी रियासतें तो गिनती की थीं। शेष रियासतें गहरे अधरे में टटोल रही थीं—वहाँ न कोई जागृति थी और न अपने अधिकारों का कोई भान। कुछ बड़ी थी, अनेक छोटी थी। इनके अलग अलग प्रश्न और समस्याएँ थीं। ये कैसे एकत्र हो? फिर भी उन्हें एकत्र तो करना ही था। इतने सारे प्रदेश को पीछे, अधिकार में छोड़कर देश कैसे आगे बढ़ सकता था? इन रियासतों के साहसी और शिक्षित प्रजाजन बाहर प्रान्तों में रहते थे। एक तरफ देशव्यापी जागृति को देखकर और दूसरी तरफ अपनी छोटी-मोटी-पिछड़ी रियासतों के अधरे, अज्ञान, और दुख को देखकर उनमें रियासती जनता को सगठित करने की भावना प्रबल होने लगी। हाल ही में हुई रूस की महान् क्रान्ति का चित्र उनके सामने था जिसमें सर्व सत्ताधीश जार को सपरिवार गोली से उड़ा दिया गया था। पिछले महाद्वन्द्व में भी देखते देखते बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट जन सत्ता के सामने धूल में मिल गये थे। असहयोग आन्दोलन से खुद लॉर्ड रीडिंग चकरा गया था। यह सब देखकर देशी राज्यों के जाग्रत प्रजाजनो में भी अपना एक अखिल भारतीय सगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई और इस उद्देश्य से सन् १९२६ के मई-जून मास में देशी राज्यों के कुछ सेवक बम्बई में सर्व-ट ऑफ इण्डिया सोसायटी के भवन में एकत्र हुए। इनमें बड़ौदा के डॉ० सुमन्त महेता, सांगली के प्रो० अभ्यकर, पुना के श्री पटवर्धन बम्बई के श्री के. टी. शाह और श्री अमृतलाल सेठ प्रमुख थे। प्रारम्भिक चर्चा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनों में एक बड़ा अधिवेशन करने का निश्चय हुआ। कांग्रेस अभी प्रत्यक्ष रूप से देशी राज्यों के प्रश्न को हाथ में नहीं लेना चाहती थी। इसलिए प्रेरणा और मार्ग दर्शन के लिए इन्हें नरम दल का सहारा लेना पड़ा और नरम

साल १९२७ में प्रसिद्ध नगम दली नेता एलोर के प्रसिद्ध नगम दली नेता दावान बहादुर (जो बाद में सर हो गये थे) एम. रामचन्द्र राव की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन बड़ी शान और उत्साह से हुआ । अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद की विधिवत् स्थापना हो गई । उनका उद्देश्य था “उचित और शांतिपूर्ण उपायों से रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना ।”

इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था । लोक परिषद का एक शिष्टमण्डल कांग्रेस के सम्मेलन में मिला और उसने कांग्रेस का ध्यान विशेष रूप से देशी राज्यों की ओर दिलाया । मद्रास के अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा—“कांग्रेस की यह जोरदार गवाह है कि रियासती जनता तथा नरेश दोनों के हित की दृष्टि से राजाओं को अपने अपने राज्यों में शीघ्र ही प्रातिनिधिक धारणभाव एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देनी चाहिए ।”

इन तर्कमूलक हलचलों से नरेशों में फिर एक भय की लहर दौड़ गई । अपने अपने राज्यों में संपूर्ण सत्ता मिलने के लिए वे चिन्ताग्रस्त मचाने लगे । इन्हीं दिनों काठियावाड़ के कुछ बन्दरगाहों को सुधारने का प्रश्न भारत सरकार ने उठाया था । और इससे उनमें जो नव्य अग्रगण्य किया था उस पर बहुत से नरेश बड़े व्यग्र हो रहे थे । उन्होंने कहा कि उनकी सत्ताओं पर इस तरह भारत सरकार आक्रमण न करे और उनके साथ सन्धियों के अनु-

अगले वर्ष काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बारडोली की विजय से देश में चारों तरफ आशा और आत्मविश्वास का वातावरण फैल गया था केवल टीकाये करने के बजाय अपने भावी स्वराज्य की कोई निश्चित योजना पेश करनी चाहिए इस तरह की मार्ग के जवाब में पं. मोतीलाल नेहरू के संयोजकत्व में एक कमिटी की नियुक्ति हुई थी। इस कमिटी ने कलकत्ता के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। देशी राज्यों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में लिखा था—

“नई संघ सरकार देशीराज्यों पर और उनके प्रति उन्हीं अधिकारों और जिम्मेदारियों का पालन करेगी जो वर्तमान भारत सरकार सुलहानों के अनुसार तथा अन्य प्रकार से उनके प्रति आज कर रही है।

कमिटी का आशय यह था कि भारतीय पार्लियामेंट में उनके जिम्मेदार देश भाई होंगे। नरेशों को विश्वास करना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों को उनके अधिकारों, शान और प्रतिष्ठा वगैरा का जितना ख्याल और आत्मीयता हो सकती है उससे कम तो उनके इन देश भाइयों को नहीं होगी।

पर अपने कलकत्ता अधिवेशन में काँग्रेस ने जनता के अधिकारों के विषय में साफ साफ कह दिया कि “नरेशों को चाहिए कि वे अपने प्रजा-जनो को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर दें और तुरन्त ऐसी घोषणाएँ कर दें या इस आशय के कानून राज्यों में जारी कर दें कि जिससे जनता को भाषण, मुद्रण, सगठन और अपनी जान माल की सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक स्वाधीनता के अधिकार मिल जायें।” इसी प्रस्ताव में काँग्रेस ने रियासती जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उत्तरदायी शासन की प्रति के लिए वह जो जो भी उचित और शान्तिमय प्रयत्न करेगी उसमें काँग्रेस की पूरी सहानुभूति और समर्थन रहेगा।
(—assures the people of Indian states of its

sympathy with and support to their legitimate struggle for the attainment of full responsible Government in states) इसी अधिवेशन में कांग्रेस विधान की धारा ८ के नीचे लिखे शब्द पं. जय हलाल नेहरू के आग्रह से हटा दिये गये—“मनदाताओं में रियासती जनता को शामिल करने का अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करेगी।” सन १९२६ के लाहौर अधिवेशन में जब कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य को अपनाया था कांग्रेस ने नरेशों से फिर कहा कि अब देशी राज्यों में भी जिम्मेदाराना हुकूमतें स्थापित करने का समय आ गया है।

इन्हीं दिनों पटियाला ने नियो के उखाड़े जाने, बलारहार, और भयंकर हत्याओं के रोगटे खड़े करने वाले समाचार पाये। यह खबर थी कि महाराजा पटियाला ने किर्ना अमरसिंह नामक आदर्मी की श्रान्त को उडवाग और अपनी पारिवारिक विषय लालना को तृप्त करने के लिए हत्याये तक करवाई। लोक परिषद को यह उचित मालूम हुआ कि वह इस मामले को हथों में ले और उसने निराल जून की मंग की। पर नरेश और सासुर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिगत थे। इसलिए वह उनका बचान करना चाहती थी। बार बार माग करने

रहते हैं और किस तरह अपनी प्रजा को तबाह करते रहते हैं। और आश्चर्य यह कि इन फुलकन रियासतों के पोलिटिकल एजेंट ने भी उस औरत को उड़ाने में महाराजा पटियाला की सहायता की है। क्या देशी राज्य और क्या प्रान्त समस्त देश की जनता का दिल दहल गया और उसने अपने दिल में पक्का निश्चय कर लिया कि इस अन्धेरशाही का अंत तो करना ही होगा। परन्तु अभी कांग्रेस खुद रियासतों में प्रत्यक्ष कोई काम करने के पक्ष में नहीं थी। और न रियासतों की जनता में इतनी ताकत आई थी कि वह खुद अपने बल पर वहाँ कुछ करती। अतः अभी तो देशी राज्यों में चल रहे अन्यायों को दूर करने का एकमात्र उपाय यही था कि देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों जगह के निवासी मिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सब जुल्म अंधेरे करते थे उसकी कमर तोड़े ! तदनुसार देशी राज्यों की जनता ब्रिटिश भारत के आन्दोलन में और भी उत्साह के साथ भाग लेकर उसे बलवान बनाने में योग देने लगी।

इस बीच शासन-सुधार के सम्बन्ध में भारत की परिस्थिति का निरीक्षण करके रिपोर्ट करने के लिए सायमन कमीशन आया। उसका सर्वत्र बहिष्कार हुआ। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पर उसे सारे देश में सर्वजनिक रूप से जलाया गया। सन् १९२८ के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी कि एक साल में इसमें पेश की गई मग को सरकार मंजूर कर लेगी तब तो उसे औपनिवेशिक स्वराज्य मंजूर होगा वरना एक साल बाद वह पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय की घोषणा कर देगी और अपने मार्ग पर अग्रसर होगी। तदनुसार लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को ध्येय बनाकर २६ जनवरी १९३० को सारे देश में स्वाधीनता दिवस अपूर्व उत्साह से मनाया गया। और इस वर्ष के मध्य में सपना भी छिड़ गया। इधर इस बढ़ते हुए असंतोष का उपाय ढूँढ़ने की गरज से सरकार ने लन्दन में

हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान तैयार करने की गरज से एक गोल मेज परिपद का आयोजन किया। इसके सदस्यों का चुनाव, संगठन और कार्य-प्रणाली सब साम्राज्यशाही ढंग की थी।

ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियों की जगह अपने मन के खुशामदी और नरमदली लोगों को नामजद करके वहाँ बुलाया गया था। रियासतों से भी जनता के प्रतिनिधियों को नहीं, नरेशों को निमन्त्रित कर लिया गया था। काग्रेस ने ऐसी परिपद में जाने से साफ इन्कार कर दिया। और जहाँ काग्रेस न हो ऐसी परिपद क्या सफल होती? इधर देशव्यापी सघर्ष छिड़ा, सारे देश भर में कानून भंग की लहर फैली धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ होने लगी लोग हजारों की सख्या में जेल में रकते जाने लगे और उधर लन्दन में गोल मेज परिपद का नाटक चल रहा था। रियासतों की जनता भी इस सघर्ष में कूट पड़ी और उसने अपनी शक्ति भर इसमें योग दिया। आखिर सरकार भी समझी कि ऐसी परिपदों से काम न चलेगा, जैसे तेने उस नाटक को पूरा किया, काग्रेस के तमाम नेताओं को छोड़ा, समझौता किया और दूसरी गोल मेज परिपद की योजना की। इस परिपद में काग्रेस की तरफ से महात्माजी एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये थे। इसमें भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। अन्तः लोकपरिपद का एक शिष्ट मण्डल महात्माजी ने जाकर मिला और उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पक्ष को भी परिपद में पेश करें। महात्माजी ने कहा "मैं पूरे चलते साथ आपके पक्ष को पेश करूँगा पर आप यह अपेक्षा न करें कि रियासतों के पक्ष पर वातर्जित को मैं तोड़ दूँ।"

इसी मौके पर मोर्टन रिच्यु के प्रसिद्ध मतदाता श्रीगमान द चटर्जी के महापण्डित में परिपद का तीसरा प्रतिनिधित्व करने में उनकी जल्दी में न हो तब तो हमें के लिए निमन्त्रित किया गया कि गोलमेज परिपद में रियासती जनता भी पारदर्शित करने के लिए परिपद को बरा उभार

करना चाहिए। आखिर यह तय हुआ कि महात्माजी की सहायता करने तथा इंग्लैण्ड की जनता को रियासतो की स्थिति से परिचित कराने के लिये प्रो० अभ्यकर और श्रीअमृतलाल सेठ का एक शिष्ट मण्डल इंग्लैण्ड भेज दिया जाय। रियासतो की जनता का शासन में परिणाम-जनक हाथ हो इस दृष्टि से शिष्ट मण्डल को परिषद में कोई सफलता नहीं मिली। परन्तु जहाँ तक इंग्लैण्ड के लोकमत को जागृत करने का प्रश्न था इसने खूब अच्छा काम किया। दीवान बहादुर रामचन्द्र राव भी परिषद के सदस्यों में से थे। उन्होंने भी शिष्ट मण्डल की बड़ी कीमती सहायता की।

पूज्य महात्माजी ने इस परिषद में रियासती जनता की तरफ से बोलते हुए नरेशों से कहा—

“चूँकि मैं जनता का सेवक हूँ और समाज के निम्नतम अंगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इसलिए मैं नरेशों से आग्रहपूर्वक कहूँगा कि इस विधान समिति की मजूरी के लिए जो भी योजना आप सब बनावें उसमें इनके लिए भी जरूर स्थान रखें। अगर नरेश इतना भी मजूर कर लें कि सारे भारत में प्रजाजनो के कुछ मौलिक अधिकार होंगे—फिर वे जो कुछ भी हो, और इनका ठीक तरह ने पालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच करने का अधिकार न्यायालयों को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी भले ही नरेशों के बनाए हुए हों और एक तीसरी बात—नरेश शासन में प्रजाजनो का प्रतिनिधित्व स्वीकार ले चाहे वह प्राथमिक टग का हो, तो मेरा ख्याल है यह कहा जा सकेगा कि प्रजाजनो को संतोष दिलाने के लिए नरेशों ने कुछ किया।”

इस उद्धरण में हम देखते हैं कि महात्माजी कितनी माध्यानी ने आगे बढ़ रहे हैं। रियासतो के प्रश्न पर अभी अधिक जोर देने के पक्ष में वे नहीं थे। उनके विचार और कांग्रेस की स्थिति याद को ध्यान में चिन्तामणि केलकर के लिखे पत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। जिम्मे

उन्होंने लिखा है कि “रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस अ-हस्तक्षेप की जिस नीति का अवलम्बन कर रही है, उसमें बड़ी समझदारी है।”

“ब्रिटिश भारत के नाम से पहचाने जानेवाले हिस्सों की रियासतों की नीति के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है।—ठीक उमी तरह जिस प्रकार कि हम अफगानिस्तान और सीलोन के विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत चाहता हूँ कि ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता। पर मैं विवश हूँ। हम रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाते हैं उनसे हमें काफी सहायता भी मिलती है। फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनको कट नहीं करते बल्कि हममें हमारी बेवसी है।”

पर मेरा यह मत है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल करेंगे उसका असर रियासतों पर भी अवश्य पड़ने वाला है। (जुलाई १९३४)

सन् १९३५ के अप्रैल मास में जबलपुर में कांग्रेस की महामहिमि (A I C C) की बैठक में जो प्रस्ताव पाम हुया उसमें मात जाति होता है कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे धीरे, पर सावधानी के साथ रियासतों जनता के पक्ष को बल पहुँचाने में आगे बढ़ती जाती थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था “कांग्रेस को देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी उतनी ही चिन्ता है, जितनी ब्रिटिश भारत के निवासियों के हितों की प्रीति वह रियासती जनता को आश्रय देती है कि वह अपनी आजादी के लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें कांग्रेस की पूरी सहायता देगी।”

इसी वर्ष के अक्टूबर मास में महामहिमि की मन्तव्य में कांग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिखे आशय का कथन प्रस्तावित किया था “रियासतों जनता की सहायता पाने की उतनी ही इच्छा है जितनी कि ब्रिटिश भारत की जनता। अक्टूबर कांग्रेस ने अपनी इच्छा को निम्न

भी कर दी हैं कि वह रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना देखना चाहती है। और उसने नरेशों से यह अनुरोध भी किया है।”

“कॉंग्रेस अपनी नीति पर दृढ़ है। वह समझती है और स्वयं राजाओं का भी भला इसी में है कि वे अपने राज्यों में शीघ्रातिशीघ्र उत्तरदायी शासन कायम कर दें। जिससे उनके प्रजाजनो को नागरिकता के पूर्ण अधिकार मिल जावे।”

अपनी मर्यादा को प्रकट करते हुए कॉंग्रेस ने इसी वक्तव्य में आगे कहा है कि यह बात समझ लेने की है कि उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखने का भार खुद देशी राज्यों के प्रजाजनो को ही उठाना है। कॉंग्रेस तो राज्यों पर नैतिक और मैत्री पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती है। और जहाँ कहीं भी संभव होगा यह प्रभाव वह अवश्य डालेगी। परन्तु वर्तमान परिस्थिति में कॉंग्रेस के पास कोई सत्ता नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी—चाहे वे अंगरेजों के आधीन हो या देशी नरेशों के या अन्य किसी सत्ता के—सब एक हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।”

इसी मौके पर सभ योजना के सम्बन्ध में कॉंग्रेस ने देशी राज्यों के प्रजाजनो को यह भी अश्वासन दिया कि नरेशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी अन्तिम योजना में कॉंग्रेस प्रजाजनो के हितों का बलि कदापि नहीं होने देगी। “असल में कॉंग्रेस शुरू से ही असहिष्णु रूप से जनता के हितों की समर्थक रही है। और जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्वार्थ खड़े होंगे, कॉंग्रेस जनता के न्याय-हितों का अवश्य समर्थन करेगी।”

इस बीच लोक परिषद के दो और अधिवेशन महाराष्ट्र के नेता श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर और मद्रास के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री नटराजन की अध्यक्षता में हो गये। शुरू से लेकर इन दोनों अधि-

वेशनों में परिषद ने अधिकांश में प्रारम्भिक काम ही किया। वान्द्र में परिषद के अन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसके कराची अधिवेशन से ही हुआ जब कि उसके सभापति डॉ० पट्टाभिषीतारामैया हुए। रियासती जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेकर उन्होंने जिन्ने जोर और वेग के साथ काम किया। उतना अब तक किसी अल्पक के कार्यकाल में नहीं हुआ था। राजपूताना, काठियावाड़ और दक्षिण भारत में उन्होंने लम्बे दौरे किये और रियासती जनता को खूब बल पहुँचाया। डॉक्टर सा. कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के भी सदस्य थे, परिषद में उनके सक्रिय होने से परिषद का कांग्रेस के साथ भी अनायास घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। सन् १९३६ के लखनऊ अधिवेशन में और १९३७ के फैजपुर अधिवेशन में देशी राज्यों में नागरिक स्वाधीनता की दुरवस्था पर दुःख प्रकट करते हुए कहा गया था—“क्या देशी राज्य और क्या ब्रिटिश भारत कांग्रेस चाहती है कि सबको संपूर्ण नागरिक स्वाधीनता प्राप्त हो। या जब तक यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगे बढ़ती रहेगी। परन्तु कांग्रेस मान्यमान करती है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज राजनैतिक आजादी ही है। इसलिए उसकी प्राप्ति में देश को अपनी सारी ताकत बटोर कर लगा देनी चाहिए।”

रियासती जनता के प्रश्नों में कांग्रेस की बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ साथ उसकी भाषा भी रियासतों के विषय में अधिक व्यापकता भरी और तेजस्वी होती गई। सन् १९३७ में मेमोर के दमन का कड़ा विरोध करते हुए महासमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत तथा रियासती की जनता में संशय निवृत्ति की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। महासमिति की राय में इस प्रस्ताव में कांग्रेस की आ-आवेदों की पूर्ण प्रतिबन्धता से रहा था। निम्नलिखित सर्त-सर्तियों के दृष्ट पर रियासती जनता की थी। इसे कांग्रेस की एक प्रतिबन्धता की प्रतिज्ञा के रूप में नहीं बल्कि प्रतिबन्धक शब्दों में कहा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने

मैं रियासती कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से अपील की कि वह रियासतों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदले, और रियासती जनता को बल पहुँचावे। सन् १९३८ में हरिपुरा के अधिवेशन में रियासतों सम्बन्धी प्रस्ताव इन्हीं कोशिशों का प्रतिकूल था। इसमें कांग्रेस ने अपनी अहस्तक्षेप की नीति को दोहराते हुए भी रियासतों के प्रति अपने रुखको तथा रियासतों सहित समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिये यत्न करने का जितनी साफ़ तरह से ऐलान किया है उतना पहले कभी नहीं किया था परन्तु साथ ही रियासतों के उद्धार का भार कांग्रेस ने स्वयं रियासती जनता पर ही ढाल दिया और कह दिया वह जो कुछ भी कार्य या सघर्ष वगैरा करे अपने बलपर ही करे। स्थानीय प्रजामण्डल जैसी संस्थाओं के द्वारा करे। कांग्रेस के नाम प्रतिष्ठा वगैरा का उपयोग न करे। पूरा प्रस्ताव यों है—

“चूँकि रियासतों में सार्वजनिक जीवन का विकास और आजादी की माँग बढ़ती जा रही है, वहाँ नई समस्या खड़ी हो रही है और नये नये सघर्ष भी निर्माण हो रहे हैं इसलिये कांग्रेस रियासतों के सम्बन्ध में अपनी नीति को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती है।”

“कांग्रेस रियासतों को हिन्दुस्तान का ही एक अंग मानती है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अतः शेष भारत में जिस प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता वह चाहती है वही रियासतों में भी हो, ऐसा उसका यत्न है। पूर्ण स्वराज अर्थात् सम्पूर्ण स्वाधीनता कांग्रेस का ध्येय है। यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के लिए है। क्योंकि जो एकता गुलामी में कायम रही है उसे आजाद होने पर भी अवश्य ही रक्खा जाना चाहिए। कांग्रेस तो केवल ऐसे ही सघ (शासन विधान) को मंजूर कर सकती है जिसमें रियासतें स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में शरीक हो सकेंगी। और जिसमें वे भी उन्नी जनतान्त्रिक स्वाधीनता का अभोग करेगी, जो शेष भारत में होगी। इसलिए कांग्रेस देशी राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा नागरिक स्वाधीनता की

परिस्थिति में रियासतों में स्वाधीनता की लड़ाई का भार वहाँ के प्रजाजनो को ही उठाना चाहिए। कांग्रेस की शुभ कामनाएँ और समर्थन ऐसे शान्तिपूर्वक और उचित तरीकों पर चलाये जाने वाले संघर्षों को सदा मिलते रहेंगे। परन्तु कांग्रेस-संगठन की यह सहायता मौजूदा परिस्थिति में केवल नैतिक समर्थन और सहानुभूति के रूप में ही होगी। हाँ, कांग्रेस-जनो को यह आजादी रहेगी कि वे खुद व्यक्तिगत रूप से इससे अधिक सहायता भी करें। इस तरह कांग्रेस के संगठन को बगैर उलझाते हुए और साथ ही बाहरी बातों या परिस्थितियों के खयाल से न रुकते हुए भी रियासती जनता की लड़ाई आगे कदम बढ़ाती जा सकती है।

“इसलिए कांग्रेस आदेश करती है कि फिलहाल, रियासती कांग्रेस की समितियाँ कांग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति के मार्ग-दर्शन और नियन्त्रण में ही काम करेगी। कांग्रेस के नाम अथवा तत्त्वावधान में न तो पार्लियामेंटरी काम करेंगी और न सीधे संघर्ष को उठावेंगी। राज्य की जनता की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम से नहीं उठाई जानी चाहिए। इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र संगठन खड़े किए जावें। और अगर पहले ही से हों तो उनको जारी रखना चाहिए।

“कांग्रेस रियासती जनता को यह आश्वासन देना चाहती है कि वह उनके साथ है और स्वाधीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी लड़ाई में उनकी पूरी सहानुभूति और सक्रिय तथा सावधान दिलचस्पी है। कांग्रेस को विश्वास है कि रियासती जनता की मुक्ति का दिन भी दूर नहीं है।”

इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि—

जहाँ तक देश की एकता, स्वाधीनता की लड़ाई और नवोन्नत भावी निर्माण से सम्बन्ध है, देशी राज्य और ब्रिटिश भाग में जोड़

ने कुछ भिन्नक के साथ परिपद के अधिवेशन का सभापतित्व करना मंजूर किया पर इस शर्त के साथ कि अगर वह उनके यूरोप से लौटने के बाद हो। कार्यकर्ताओं ने यह खुशी से मंजूर कर लिया। नरेशों में जहाँ पंडितजी सभापति हो रहे हैं यह सुनते ही तहलका मच गया। तहाँ रियासती जनता के खुशी का पारावार नहीं रहा। उसने सोचा जवाहरलाल देश के प्राण हैं। सारा ससार उनकी आवाज आदर के साथ सुनता है। इसलिए उनका सभापतित्व हमारे लिए वरदान होगा।” अगला अधिवेशन लुधियाना में बड़ी शान से हुआ।

लुधियाना अधिवेशन ने रियासती आन्दोलन में एक नया अध्याय शुरू किया। जनता के लिए जनता का राज्य स्थापित करने के उद्देश्यों का इसमें समर्थन किया गया। और यह साफ बताया गया कि बदली हुई परिस्थिति में छोटी छोटी रियासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस विषय के प्रस्ताव में बनाया गया था कि ‘आने वाले संघ-शासन में वे ही रियासतें या उनके सघ स्वतंत्र इकाई के रूप में सुधरे हुए शासन की सुविधाये अपने प्रजाजनो को दे सकेंगे जिनकी आवादी कम से कम २० लाख और आय पचास लाख रुपये होगी। जो राज्य इस शर्त का पालन नहीं कर सकते उन्हें एक एक करके या मिला कर पड़ोस के प्रान्त में जोड़ दिया जाय। इस सिद्धान्त को आगे चल कर सरकार ने भी अपनी “मर्जर स्कीम” में अपना लिया। पर इसके अमल में चालाकी से काम लिया गया। छोटी छोटी रियासतों को प्रान्त में मिलाने की अपेक्षा अपने साम्राज्य के स्तंभ रूप बड़ी रियासतों को मजबूत करने के लिए उनमें मिला दिया गया। और यह करते हुए जनता की राय तक जानने की कोशिश नहीं की गई। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा परिपद ने उन सन्धियों और मुलहनामों को सगने से इन्कार कर दिया जो दो पक्षों के बीच अपने स्वार्थों के लिये हुई थीं पर जिनकी वे बड़ी दुहाइयाँ दिया करने थे और वेद समाप्त ने अपना मन्वन्ध बताते थे। लुधियाना के अधिवेशन के

वाद परिषद के केन्द्रीय दफ्तर का भी पुनः संगठन करके उसमें एक संशोधन और प्रकाशन विभाग जोड़ कर उसे इलाहाबाद ले जाया गया।

इस प्रकार पं० जवाहरलालजी के नेतृत्व में परिषद जोर के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए जा रही थी कि सन् १९३६ में एकाएक दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। और सरकार ने प्रांतीय मन्त्रिमण्डलों में बगर सलाह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इन मनमानी का जोर के साथ विरोध किया और सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को साफ करने के लिए कहा। परिषद ने भी नरेशों के द्वारा रियासतों के लार्डों में घमाटे जाने पर इसका विरोध किया। इधर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल त्याग पत्र देकर अलग हो गये और युद्ध गोर भी भीषण रूप धारण करने लगा। हिन्दुस्तान पर आक्रमण का एतद् भी बढ़ गया। साम्राज्य महा नकट में आ गया तब एक योजना लेकर सर स्टैफर्ड क्रिश्चियन भाग्य आये। इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक्र तो था पर रियासती जनता का कहीं पता नहीं था। दिल्ली में उस समय नई परिस्थितियों पर विचार करने के लिए स्टैंडिंग कमिटी की बैठक बुलाई गई। डॉ० पट्टाभि साहसराभेय्या क्रिश्चियन ने वातचीत करने के लिए चुने गये। मुलाकात में सर स्टैफर्ड ने प्रस्तावों में कोई फेर बदल करने में मनाही

ये कार्यकर्त्ता अपने अपने राज्यों में पहुँचने पर प्रजा मण्डल के द्वारा नरेशों से कहे कि वे अंग्रेजी हुकूमत से अपना सम्बन्ध तोड़ कर प्रजा को फौरन उत्तरदायी शासन दे दें। अगर वे यह मजूर करें जिसकी बहुत कम सम्भावना थी—तो ठीक अन्यथा वे भी ब्रिटिश भारत के समान सघर्ष छेड़ दें। तदनुसार ता० ६ को पू० महात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा देश के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देशी राज्यों के कार्यकर्त्ताओं ने भी उपयुक्त आदेशों का पालन किया और अनेक रियासतों में भी जबरदस्त सघर्ष छिड़ गया। सारे देश में खुली बगावत फैल गई इतनी बड़ी, उग्र और देशव्यापी बगावत पहले कभी नहीं हुई थी। दमन भी अभूतपूर्व हुआ। गाँव के गाँव वीरान हो गये। पर कई जिलों में से विदेशी हुकूमत एक दम उठ गई। जनता ने असंख्य कष्ट बहादुरी से सहे और नेताओं के न रहने पर भी खुद अपनी बुद्धि से जिस तरह सत्ता जुल्मों का डट कर प्रतिकार किया। अतः में तूफान शान्त हुआ। महायुद्ध भी समाप्त हुआ और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई के साथ फिर आजादी की लड़ाई शुरू हुई। पं० जवाहरलालजी ने सारे देश में घूम घूम कर प्रत्येक प्रान्त का निरीक्षण किया और देखा कि आजादी की आग पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित है। देश अधीर हो रहा था। इसी मौके पर आजाद हिन्द फौज का मामला शुरू हो गया जिमने सारे देश में विजली का संचार कर दिया और अंग्रेजों को हम बात का निश्चय करा दिया कि अब तो फौज भी उनके हाथ से निकल गई और यह कि हिंदुस्तान में अब उनके लिए हुकूमत करना असंभव है। सारा वातावरण एक दम बदल गया।

इसी वातावरण में पिछले वर्ष राजपूताने की कड़कता की सन्दी में दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिषद का आठवाँ अधिवेशन हुआ। सभा पति फिर पं० जवाहरलाल ही चुने गये थे। अधिवेशन पहली बार एक देशी राज्य में हो रहा था। फिर भी उनकी शान को देख कर नहीं मल्लू हो रहा था मानो कांग्रेस का खुला अधिवेशन है।

१ मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की गैरएटी

४ स्वतंत्र न्याय प्रणाली

५ आर्थिक स्वतंत्रता और

६ मनुष्य के विकास में बाधाये डालने वाले सामन्तशाही- अथवा अन्य सभी प्रकार के बन्धनों और बोझों से मुक्ति ।

क्योंकि जिस भविष्य की हमारी तस्वीर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होंगे और सबको अपनी तरक्की के लिए भी अवसर भी समान ही होंगे ।

रियासतों के संधीकरण में उन्हें दूसरी बड़ी रियासतों के साथ नहीं बल्कि प्रान्तों से मिलाने पर जोर दिया । हैदराबाद की स्थिति पर अफसोस प्रकट किया । अधि की सराहना की । विधान परिषद में प्रजा के ही चुने हुए प्रतिनिधि लेने पर तथा इनकी चुनाव की पद्धति पूर्णतया जन-तन्त्रात्मक होने पर जोर दिया । और नरेशों को अपने भीतरी शासन में भी प्रान्तों के समान परिवर्तन करने की हिदायत दी ।

अधिवेशन के प्रस्ताव भी लगभग इन्हीं विषयों पर थे । मुख्य प्रस्ताव में आने वाले शासन विधान में परिवर्तनों के बारे में कहा गया था कि “वे परिवर्तन तभी स्वीकृत हो सकेंगे जब कि उनका आधार स्वतंत्र भारत के अग्रभूत हिस्सों की शक्ति में रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा और विधान परिषद के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तों के समान व्यापक आधार पर चुने हुए होंगे । ” यह भी कहा गया था कि “यदि रियासतों की सरकारों की नीति में कोई परिवर्तन होता हो तो पहले नागरिक स्वतंत्रताओं को पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए । जिनके दिना स्वतंत्र चुनावों का होना या आजादी और प्रातिनिधिक शासन की दिसा में कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति का होना अनम्भन है । ”

छोटी बड़ी रियामनों के समुदीकरण के सम्बन्ध में मुख्य आधार यह बताया कि जनता की सामाजिक और आर्थिक तग्वी आधुनिक दर्ज के अनुकूल हो। लुधियाना वाले प्रस्ताव को भी इसी अर्थ में पढ़ा जाय। जो रियासत या रियामने इस शर्त को पूरी नहीं कर सकती उन्हें पटोस के प्रान्त में मिला दिया जाय और यदि सम्भव हो तो इन्हे सामुदायिक या अन्य प्रकार की आवश्यक स्वायत्तता दी जाय। इनके नरेशों के लिए मुनासिब कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्पत्ति और स्थिति की रक्षा की जाय।

इण्डोनेशिया का अग्निन्दन और पिछले मघर्ष के शहीदों के सम्मान विषयक प्रस्तावों के अलावा, अंग्रेजों की प्रायः प्रजातन्त्री पद्धति की सराहना करने वाला भी एक प्रस्ताव था। रियामनों में बसने वाले आदिवासियों के प्रति रियामनी सरकारों और समाज के उनकी प्रगति में बाधा डालने वाले रूढ़ पर अफसोस प्रकट करते हुए उनसे अपने ऐसे रूढ़ को बदल कर उनके प्रति सहायक बनने को कहा गया।

एक प्रस्ताव रियामनों के अप्रगतिशील रूढ़ की निन्दा करने वाला भी था।

नरेन्द्र मण्डल की घोषणा

असल में सन् १९४५ में जब मैं कार्यसमिति के सदस्य रिहा हुए देश का वातावरण बड़ी तेजी से बदलता जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे देश में घूम कर मानो विजली का संचर कर दिया। जब तक वे देशीराज्य लोकपरिषद के सभापति नहीं हुए थे तब तक उनके विचार बड़े उग्र थे। कभी कभी तो वे यह भी कह जाते कि स्वतन्त्र भारत में नरेशों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। परन्तु लोकपरिषद के सभापति होने के बाद उनकी भाषा सौम्य होने लगी। पहले वे रियासतों में जाना पसन्द नहीं करते थे। पर अब की बार रिहा होने पर काश्मीर, जयपुर, जोधपुर आदि रियासतों में वे गये और वहाँ उनका स्वागत सत्कार भी अच्छा हुआ। उनकी भाषा भी नरेशों के प्रति सौम्य होने लगी। इसका कारण यह नहीं था कि उनके आदर्श या विचारों में कोई अन्तर हो गया। बल्कि यह था कि नरेशों की स्वाधीनता के आन्दोलन की तरफ खींचने की उनकी उत्सुकता ने उनके व्यवहार में यह परिवर्तन कर दिया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम भी हुआ। नरेश जो अब तक उनसे चौंकते थे उनके नजदीक आने लगे। अपने दिल की बातें करने लगे और रियासतों के आन्दोलनों को भी बल पहुँचा। उदयपुर के अधिवेशन ने तो रियासतों के सारे सकोच को तोड़ दिया। इस अधिवेशन में मेवाड़ की सरकार ने स्वागत समिति की हर तरह से सहायता की। खुद नरेशों के मानन में भी प्रत्यक्ष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगा। इसका कारण केवल भारतीय जागृति ही नहीं थी। मासिक परिस्थिति के कारण ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। और खुद उसे भीतर में ऐसा महसूस होने लगा कि अब अगर सत्तार की एक बड़ी सत्ता के रूप में उसे अपना अस्तित्व कायम रखना है तो साम्राज्य के सभी अंगों के सम्यन्धों में संशोधन करके उनको मिला बना लेना होगा। इस दिशा में उसने हिन्दुस्तान में भी प्रयत्न जारी कर दिया। औरता० १८ जनवरी १९४६ को

२ परन्तु यह ससार व्यापी महान् सगठन तभी सफल होगा जब उसके सदस्य राष्ट्र और उनके निवासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, सहिष्णुता और सहयोग का निःस्वार्थ भाव से आचरण करेंगे। क्योंकि इन गुणों के बगैर कभी कोई राष्ट्र और जातियाँ न तो एक साथ रह सकती हैं और न तरकी कर सकती हैं।

३ यही बात हमारे अपने देश के बारे में भी है। ब्रह्मस्मृति से आज मतभेदों और नाइत्तफाकी के कारण हम छिन्न-निच्छिन्न हो रहे हैं। पर यहाँ भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं न्याय, सहिष्णुता और सहयोग के बल पर हम उस लक्ष्य को पहुँच सकेंगे जिसकी आकांक्षा इस देश के राजा से ले कर रक्त तक कर रहे हैं। क्या हम में ऐसा एक भी मनुष्य है, जो हमारे इस मातृभूमि को स्वतन्त्र, महान् और सारे ससार में आदर नहीं देखना चाहता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मानव जाति को ऊँच उठाने में उसने जो जबरदस्त काम किया वैसा वह अब भी न करे ?

अगर हम सब यही चाहते हैं तो आइए इस महान् लक्ष्य को पूरा करने में हम सब लग जावे और इसके लिए आवश्यक त्याग करने को तैयार हो जावे। हम यह याद रखें कि लेने के बजाय देने में अधिक आनन्द है।

इस दिशा में एक प्रयत्न के रूप में और रियासतों को बल के भारत में अपना हिस्सा अदा करने योग्य बनाने की गरज से मैं रियासतों में वैधानिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में नीचे लिखी घोषणा करता हूँ—

१ नरेन्द्र मण्डल ने मन्त्रियों की समिति के साथ रियासतों के अन्दर वैधानिक सुधारों के विकास के प्रश्न पर चिन्तापूर्ण विचार किया। रियासतों की सही तरीक़े वैधानिक स्थिति के बारे में सम्राट की सरकार ने पार्लियामेंट में पुनः घोषणा कर दी है और राज के प्रतिनिधि स्वयं श्रीमान् वाइसराय ने उसे दोहराया भी है कि “अपने अपने प्रजाजनों और रियासतों को किस किस प्रकार का शासन-विधान प्रदान होगा—इसका निर्णय करने का अधिकार उन उन लोगों को ही है।” इस वास्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी बाधा न पहुँचाने हुए नरेन्द्र मण्डल अपनी नीति को साफ़ साफ़ बता देने और उन दिशा में तुरन्त कदम उठाने की उन रियासतों को सिफारिश करता है जहाँ ऐसे कदम लदे तक नहीं उठाये गये हैं।

तदुत्तर नरेन्द्र मण्डल के वास्तविक को अधिष्ठाता दिया जाता है कि वह नरेन्द्र मण्डल की तरफ़ से और उसकी पूर्ण सलाह से नीचे लिखी घोषणा करें—

३ अधिकांश रियासतो ने पहले ही से अपने राज्यों में कानूनी राज्य और जान माल की रक्षा का आश्वासन देने वाले कानून बना दिये हैं। फिर भी जिन रियासतो में अभी यह नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में अपनी नीति और उद्देश्यों को साफ साफ शब्दों में प्रकट करने की गरज से घोषित किया जाता है कि रियासतो में प्रजाजनो को नीचे लिखे अत्यावश्यक अधिकारों का पूरा आश्वासन दे दिया जाय और रियासत के न्यायालयों को यह अधिकार दिया जाय कि इनका भंग होने पर वे प्रजाजनो को राहत दिलावे।

अधिकार—

- (क) कानून के बाहर किसी भी मनुष्य की आजादी न छीनी जाय और न किसी के मकान या जायदाद में कोई घुसे या उससे छीने या जव्त करे।
- (ख) हर आदमी को हेवियस कॉर्पस के अनुसार अधिकार होगा। युद्ध, विप्लव या गम्भीर भीतरी गड़बड़ी के प्रसंग पर एंग्लान द्वारा इस अधिकार को थोड़े समय के लिए मुत्तवी किया जा सकेगा।
- (ग) हर आदमी अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, मिलने जुलने और सम्मेलनों की स्वतन्त्रता होगी, और कानून तथा नैतिकता के अविरोधी उद्देश्यों के लिए बगैर हथियार लिये या फौजी टंग को छोड़ कर लोग एकत्र भी हो सकेंगे।
- (घ) सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था का भंग न करते हुए हर आदमी को अपने विवेक के अनुसार चलने और अग्ने अग्ने धर्म का गलन करने का अधिकार होगा।
- (ङ) कानून की नज़रों में सब मनुष्य एक से होंगे इसने जल, ज़ेद, धर्म विश्वास का ख्याल नहीं किया जायगा।

(च) गर्जनिन (सरकारी) पद, प्रतिष्ठा या सत्ता या न्याय, या व्यापार-पेशा दगैरा में जात-पति धर्म मतमतान्तर या विश्राम के कारण किसी पर कोई बंद न होगी।

(छ) देना नही रहेगी।

४ व० पुनः घोषित किया जाता है कि शासन नीचे लिखे नियमों पर आधारित होगा और जहाँ इन पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है, कठोरता पूर्वक इस पर अमल कराया जायगा—

(अ) न्याय दान का काम निष्पक्ष और सुयोग्य व्यक्तियों के ही हाथों में रहे। वे शासन विभाग में रह सकें। और व्यक्तियों एवं निगमों के बीच के मामलों के निष्पक्ष निर्णय देने की सुव्यवस्था रहे।

(आ) नगरी अपने राज्यों में शासन विषयक बजट में निजी माल को विलकुल अलग बताया करें और राज्य का सत्तारण्य राज्य पर उसका कोई निश्चिन्त और उचित प्रतिक्रिया करने के लिए।

(इ) हर-भार न्योचित और न्य पर मान ले और राज्य की ताकत एक निश्चित और यथा स्थिति बनाती मलाई त राज्यों में समानता पर राष्ट्र-निर्माणात्मक सत्त्वों पर समानता।

अभव से मुक्त करे लोग मन और वाणी में अधिक स्वतन्त्र हों और पारस्परिक स्नेह सहिष्णुता, नेवा और उत्तरदायित्व के मजबूत आधार पर इसका उत्तरोत्तर विकास और परिवर्द्धन हो।

इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विचारों और उद्देश्यों को भूतकाल में बार बार और बुरी तरह पेश किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्ताव की भूपा और नरेद्र मण्डल की तरफ से की गई यह घोषणा अब भविष्य में किसी प्रकार की शकाओं के लिए गुंजाइश नहीं रहने देगी। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। आशा है आप इस प्रस्ताव को मजूर करेंगे। प्रस्ताव यों है—

‘नरेद्र मण्डल यह दोहरा देना चाहता है कि देश अपने पूर्ण विकास की स्थिति को तुरन्त पहुँचे इस सम्बन्ध में तमाम लोगों में जो भावना है उसमें रियामते पूर्णतया शरीक है, और वे भारतवर्ष की वैधानिक गुत्थी को सुलझाने में अपनी शक्ति भर पूरा हाथ बटवेंगे।’

१८ जनवरी १९४६

मन्त्रि मण्डल का मिशन

नरेद्र मण्डल की बैठक के साथ साथ इंग्लैंड में इस सम्बन्ध में चर्चाएँ चल रही थीं कि भारतीय समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाय। और इनका अन्तिम निर्णय इस निश्चय में हुआ कि मन्त्रिमण्डलों ने वजनदार और अधिक से अधिक अनुभवी सदस्यों का एक मिशन भारत भेजा जाय। वह भारतीय नेताओं में तथा सभी पक्षों में बातचीत करे और इस प्रश्न को हल कर के ही आवे। उसे इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक अधिकार भी दे दिये जावे। इस निर्णय की घोषणा करते हुए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट ऐटली ने ता० १५ मार्च को पार्लियामेंट में जो घोषणा की उसमें बताया था कि ‘मान्यमन्त्री टॉड टेडर लॉरेस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा मि. वि एलेग्जान्डर जैसे तीन

अत्यन्त वजनदार और अनुभवी साधियों को मन्त्रिमण्डल की तरफ से भारतवर्ष भेजने का निश्चय किया गया है ।

“मैंने ये माथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उसे जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक पूर्ण आजादी हासिल करने में संपूर्ण सहायता करें । आजकी सरकार के स्थान पर वहाँ किस प्रकार का शासन कायम किया जाय इसका निर्णय तो मुझे हिन्दुस्तान ही करेगा । हा उसका यह निर्णय करने के लिए तुरन्त एक सभा बनाने में जल्द पूरी सहायता करना चाहते हैं ।

“मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ (राष्ट्र पत्र) में रहना पसन्द करेगी, मुझे निश्चय है कि इस निर्णय से उसे बहुत लाभ होगा ।

पर यह निर्णय वह अपनी स्वेच्छा से ही करे, ब्रिटिश राष्ट्र मंत्र ना साम्राज्य दबकी बन्धनों के आधार पर नहीं बना है । वह स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वेच्छापूर्वक बनाया गया मंत्र है । पर अगर हिन्दुस्तान पर यह स्वतन्त्र भी होगा तब तो हमारी राय में उसे इसका प्रतिहार है । यह परिवर्तन जितना भी यमान्य होय शान्तिपूर्ण हो सके उसे ऐसा बना देना हमारा काम है ।

निर्णय और योजना प्रकाशित कर दी। इस योजना में बताया गया था कि विधान-परिषद् तथा अस्थायी सरकार का निर्माण होकर अब शीघ्र ही विधान बनाने का काम जारी होने वाला है। वक्तव्य में सर्वसममत योजना बनाने के प्रयत्नों की असफलता का जिक्र करने के बाद कहा गया है कि “मुसलिम लीग के समर्थकों को छोड़ कर लगभग सब ने एक मत से भारत की एकता के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट की है। पर इसने हमें हिन्दुस्तान के बंटवारे की संभावना पर निष्पक्ष भाव से और बारीकी से विचार करने से रोका नहीं। मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से स्वतंत्र राज्यों के रूप में अलग कर दिये जावें। इनमें से पहले हिस्से में पंजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो और दूसरे में बंगाल तथा आसाम। इन प्रान्तों की सीमाओं को बाद में निश्चित किया जा सकता है। परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्त के रूप में पहले मंजूर कर लिया जाय। इस माँग के समर्थन में दो दीलीले हैं—

१ जिन प्रान्तों में मुसलिम बहुमत है वहाँ शासन किस प्रकार का हो यह निर्णय करने का अधिकार मुसलमानों को हो।

२ और शासन तथा आर्थिक दृष्टि में यह योजना व्यावहारिक बन जाय इसलिए इसमें कुछ मुस्लिम अल्पमत वाले प्रदेश और जोड़ दिये जावें।

इनमें से पहले हिस्से में २२६ लाख अर्थात् ६२ प्रतिशत मुसलमान और लगभग ३८ प्रतिशत गैर मुस्लिम आवादी है। और दूसरे हिस्से में ३६४ लाख अर्थात् ५१ ३/४ प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८ ३/४ प्रतिशत गैर मुसलिम आवादी है। इसके अलावा दो करोड़ मुसलमान शेष प्रान्तों में बटे हुए हैं।

इन अंकों से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की माँग के अनुसार हिन्दुस्तान से ये दो हिस्से पाकिस्तान के रूप में अलग निकाल दिये जायें तो (१)

अल्पमत की समस्या हल नहीं होगी फिर (२) पंजाब, बंगाल और आसाम के जिन जिलों में मुसलमान कम सख्या में हैं उन्हें पाकिस्तान में जोड़ देना कैसे व्यव संगत होगा हम नहीं समझ पाते । पाकिस्तान के पक्ष में जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वे सब दलीलें इन जिलों को पाकिस्तान में न जोड़ने के पक्ष में दी जा सकती हैं ।

तब क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है और उस पर कोई समझौता हो सकता है ? (३) खुद मुसलमान ही इसे अवांछनीय मानते हैं । फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से मानते हैं कि हम तरह पंजाब और बंगाल के टुकड़े टुकड़े करना वहाँ की जनता के बहुत बड़े हिस्से की इच्छा और हितों के प्रतिकूल होगा । फिर (५) ऐसे टुकड़े करने में सिकन्दर जाति भी दो टुकड़ों में बंट जायगी । इसलिए हम बस इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान और न छोटा पाकिस्तान जातीय समस्या को हल कर सकेगा ।

पर मुसलमानों को जो वास्तविक भय है उसका भी हमें पूरा खयाल है इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है उसके अनुसार देश रक्षा, आवागमन के साधन और वैदेशिक विभाग जैसे कुछ विषयों के अपवाद के साथ प्रान्तों को संपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है।

कांग्रेस ने इस योजना में यह भी गुंजाइश रखी है कि जो प्रान्त शासन और अर्थ के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर किये जाने वाले संयोजन में भाग लेना चाहे वे इन उद्भुत अनिवार्य विषयों के अलावा अन्य कुछ विषय भी स्वेच्छापूर्वक केन्द्र को सौंप सकते हैं।

इस योजना में कई कठिनाइयाँ बताने के बाद मिशन ने रियासतों के प्रश्न पर लिखा है—

“अपनी। सफारिशें पेश करने के पहले हम ब्रिटिश भागन और रियासतों के सम्बन्ध पर विचार कर ले। यह तो विलकुल स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद—चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र नष्ट के साथ रहे या अलग—रियासतों और ब्रिटिश सम्राट के बीच अब तक जो सम्बन्ध रहा है वह अब आगे नहीं रह सकेगा। हिन्दुस्तान में नवभोग सत्ता न तो सम्राट के हाथों में रह सकती है और न वह नई संस्था को सौंपी जा सकती है।

रियासतों के जिन जिन लोगों ने हम मिले वे नव इन बातों को जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि हिन्दुस्तान में आने वाले इस नवीन परिवर्तन को वे पसन्द करते हैं और उनमें संशय होने की भी तैयारी है। इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्या होगा वह हमें दिवान बनाने समय आपसी बातचीत में तय होगा। और यह भी कोई जल्दी बात नहीं कि इसका स्वरूप सबकुछ एक सा होगा। इसलिए नीचे दिये गये हैं रियासतों के बारे में हम इतनी तफ्तील में नहीं गये हैं।

हमारी योजना इस प्रकार है—

(१) हिन्दुस्तान की एक प्रतिष्ठा (नव) के, जिन्होंने ब्रिटिश शासन

और नियमों भी हो। और उसके अधीन वैदेशिक आवागमन तथा देश रक्षा के विभाग हों। इन महकमों के लिए लगने वाला आवश्यक सर्व निष्कलने के लिए कोश एकत्र करने का अधिकार भी इन यूनिता के हो।

(२) यूनिता का एक मन्त्रि मण्डल और धन सभा भी ऐसी जिसमें ब्रिटिश भाग्य तथा रियासतों के प्रतिनिध होंगे।

अगर कोई ऐसा सवाल आवे जिसमें कोई बड़ जमीन प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो उसके निर्णय के लिए दोनों जातियों के उत्पन्न और वोट देने वाले सदस्यों तथा तत्काल सभा में उत्पन्न और वोट देने वाले सदस्यों की बहुसंख्यि अस्तित्व गय लाजिमी होगी।

(३) यूनिता के विषयों को छोड़ कर तत्काल विषय और सारी सन्ना- जिसका निर्देश नहीं कर दिया गया है—प्रान्तों के अधीन होंगे।

(४) यूनिता को जो विषय सौंप दिये जावें उनको छोड़ कर सारी सन्ना और विषय रियासतों के अपने अधीन होंगे।

(२) प्रत्येक प्रान्त मे प्रधान जातियों की जैसी आवादी होगी उनकी संख्या के अनुसार इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियो मे बंट जायगी ।

(३) [वास्तव मे यह प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही वालिग मताधिकार के आधार पर चुने जाने चाहिए । परन्तु आज इस तरह के चुनाव मे अनेक कठिनाइयाँ है और बहुत अधिक विलम्ब हो जाने की संभावना है । इसलिए] इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य ही जातिवार कर लेंगे ।

परिषद के लिए तीन प्रधान जातिया मानी गई है—

१ जनरल

२ मुस्लिम

३ सिक्ख

छोटी छोटी जातियो को उपर्युक्त नियम के अनुसार या तो स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता या बहुत थोडा मिल सकता है । इसलिए उनको जनरल विभाग मे शामिल कर दिया गया है ।

प्रान्तों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या

सेक्शन A.	जनरल	मुसलिम	कुल
मदरास	... ४५	४	४९
बम्बई	... १६	२	२१
युक्तप्रान्त	... ४७	८	५५
बिहार	... ३१	५	३६
मध्य प्रदेश	१६	१	१७
उड़ीसा	.. ६	०	६
	<hr/> १६७	<hr/> २०	<hr/> १८७

सेक्शन B.

	जनरल	मुसलिम	मिक्ख	कुल
पजाव	... ८	१६	४	२८
सीमाप्रान्त	... ०	३	०	३
मिन्ध	... १	३	०	४
	<hr/> ६	<hr/> २०	<hr/> ४	<hr/> ३०

सेक्शन C

	जनरल	मुसलिम	कुल
बगाल	२१	३३	६०
आगाम	.. ७	३	१०
	<hr/> २४	<hr/> ३६	<hr/> ६०

ब्रिटिश भारत के
+ रियासतों के

२६२ } + ३८५
२३

दिल्ली (A)

१

अजमेर (A)

१

ब्रिटिश बलूचिस्तान

१

३८८

(२) पहले अधिवेशन में नीचे लिखे कार्य होंगे—

(क) कार्यक्रम का निश्चय

(ख) सभ पति तथा अ य पदाधिकारियों का चुनाव

(ग) नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यक जातियाँ, कबीलो और आदिमवासी सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने वाली कमिटी की नियुक्ति.

(३) इनके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन (A. B ()) विभागों में बंट जावेंगे । और वे नीचे लिखे काम करेंगे—

(क) अपने अपने विभाग के प्रान्तों के लिए विधान बनाना ।

(ख) इन प्रान्तों के लिए कोई सम्मिलित विधान बनाने या न बनाने के बारे में निश्चय करना ।

(ग) अगर ऐसा सम्मिलित विधान बनाने का निश्चय हो तो उसके नियमों का निश्चय करना ।

प्रान्तों को इन समूहों से अलग होने का अधिकार रहे ।

(४) इसके बाद तीनों रजिस्ट्रारों व तथा रियासतों के प्रतिनिधि बंट कर यूनिफ़ॉम का विधान बनावेंगे ।

अलग हो सकेगा न नये विधान के अनुसार किये गये चुनाव हो जाने के बाद नई धारा सभा यह (अलग होने का) निर्णय करेगी ।

७ नागरिकों, अल्पसंख्यकों तथा कबीलों और आदिम निवासियों के मौलिक अधिकारों के बारे में सलाह देने वाली समिति ने सम्बन्धित जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा । कमिटी यूनिन की परिषद को रिपोर्ट देगी कि—

- (क) मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे ?
- (ख) अल्पसंख्यकों के बचाव की क्या क्या तजवीजे हों ?
- (ग) कबीलों के तथा आदिम वासियों के शासन की योजना क्या हो ?
- (घ) इन अधिकारों का समावेश प्रान्तीय गूप के या केन्द्रीय विधान में कर लिया जाय अथवा नहीं ? इस विषय में भी यह कमिटी सलाह देगी ।

(द) नाईसराय तुरन्त प्रान्तीय धारा सभाओं से विनिलि करेंगे कि वे अपने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव तुरन्त कर लें । और रियासतों में करेंगे कि वे निगोशिएटिंग कमिटी बना लें ।

(६) आशा है कि विधान बनाने का काम न्यायमय जल्दी में शुरू हो जाये । ताकि अस्थायी सरकार का काम छोटे में छोटा हो सके । यूनिन का विधान बनाने वाली परिषद और इनाइटेड किंगडम के बीच इस सन्धान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ विवादों के बारे में एक सतिनामा बना लेना जरूरी होगा ।

एक तरह जहाँ विधान बनना होगा दूसरी तरफ देश का शासन तो जारी ही रहेगा । इसलिए हमारी राय में यह अत्यन्त जरूरी है कि देश में प्रधान दलों का समर्थन प्राप्त अस्थायी सरकार की जल्द स्थापना कर दी जाय । भारत की सरकार के सामने जो बर्तमान काम हैं : इस

मध्यकाल में अधिक से अधिक सहयोग के साथ हो यह बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में वाइसराय ने बातचीत भी शुरू कर दी है उन्हें आशा है कि वे बहुत जल्दी ऐसी अस्थाई सरकार की स्थापना कर लेंगे जिसमें युद्ध मन्त्री सहित सभी जिम्मेदारियों भारत की जनता के संपूर्ण विश्वास का उपभोग करने वाले नेताओं के हाथों में होंगी।

ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार को शासन में तथा इस परिवर्तन को सरलता और शान्ति पूर्वक लाने में पूरा सहयोग देगी

इन प्रस्तावों से आप को शायद पूर्ण संतोष न हो। पर भारतवर्ष के इतिहास में इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग पर राजनैतिक दूरदर्शिता का यह तकाजा है कि आप मेल जोल से काम लें और करें। जरा सोचें कि अगर इन प्रस्तावों को मजूर नहीं किया गया तो नतीजा क्या होगा? कितनी भयंकर मार काट, अव्यवस्था और गृह युद्ध होगा। इसलिए हम इस आशा के साथ इन प्रस्तावों को आप के सामने पेश करते हैं कि वे उसी सद्भाव के साथ मजूर कर लिये जावेंगे, जिसके साथ उन्हें पेश किया गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनों से हम अपील करते हैं कि अपनी अपनी जाति तथा स्वाधों से ऊपर उठ कर चालीस करोड़ के हितों का ध्यान रख कर जो कुछ करना चाहिए करें।

सन्धियों और सार्वभौम सत्ता पर नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर को मिशन द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण

१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में साधारण सभा में जो वक्तव्य दिया है उसमें नरेशों को यह आश्वासन दिया था कि सन्धियों और मुल्कनामों से जो अधिकार नरेशों को प्राप्त हैं उनमें वगैर उनकी स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने का उद्देश्य सम्राट का नहीं है। इसके साथ ही (सम्राट को नरेशों की तरफ से) यह कहा गया था कि इन बातचीत के फल स्वरूप कोई परिवर्तन करना तब हुआ तो नरेश भी उसके लिए

अपनी स्वीकृति देने से नाहक इन्कार नहीं करेंगे। हमारे बाद तो गेन्द्र मण्डल ने यह कह कर कि नगश भी मारे देश के साथ बड़ी चाहते हैं कि भाग्यवश जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर उद्युक्त आश्रामन का समर्थन कर दिया है। मन्नाट की सरकार ने भी अब यह घोषणा कर दी है कि यदि हिन्दुस्तान की भावी सरकार या सरकारें स्वतन्त्रता चाहेंगी तो उनकी गह में रुकावट नहीं डाली जायेगी। इस घोषणा का अर्थ यह हुआ है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के नियमों जिन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं है, वे यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र हो—यदि चाहें वह ब्रिटिश राष्ट्रमन्त्र के साथ रहे या अलग। हिन्दुस्तान की हम इच्छा की पूर्ति में सहायता करने के लिए मिशन का प्रावधान है।

अनेक मिल कर ऐसी सयुक्त इकाइयाँ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था में वे ठीक बैठ सकें। अगर रियासती सरकारों ने अपनी जनता के साथ नजदीक का और रोजमर्रा का संपर्क अभी कायम नहीं किया है तो इस निर्माण-कार्य में राज्य के अन्दर प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना कर के वह करे। इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी ही।

४ इस बीच के काल में रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ अर्थ और कोष जैसे सामान्य विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना पड़ेगा। रियासतें नई वैधानिक व्यवस्था में शरीक हो या न हो यह बातचीत और मशविरा जरूरी है और इसमें काफी समय लगेगा। जब नई सरकार स्थापित होगी शायद तब तक यह बातचीत अधूरी भी रहे। ऐसी सूरत में शासन सम्बन्धी असुविधाएँ खड़ी न हों इसलिए रियासतों और नई सरकार या सरकारों के बीच कोई ऐसा समझौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक कि इन सामान्य विषयों के सम्बन्ध में नये इकरारनामे नहीं बन जाते तत्कालीन व्यवस्था में ही जारी रहे। इस विषय में अगर चाहा गया तो ब्रिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि अपनी तरफ से शक्ति भर आवश्यक सहायता करेंगे।

५ जब ब्रिटिश भारत में संपूर्ण सत्ताधारी नई स्वराज्य सरकार या सरकारें कायम हो जाएँगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा असर या प्रभाव नहीं रह सकेगा कि वह सार्वभौम सत्ता की जिम्मेदारियों को अदा कर सके। फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि इसके लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजी फौजें रखी जा सकेंगी। इस प्रकार तर्क से भी यह साफ है और रियासतों की तरफ से जो इच्छा प्रकट की गई है उसे ध्यान में रखते हुए भी सम्राट की सरकार सार्वभौम सत्ता का अमल करना छोड़ देगी। इसका अर्थ यह है कि सम्राट के साथ के इस सम्बन्ध से रियासतों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे खत्म हो जाएँगे और रियासतों ने अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को सौंप दिये थे वे वापिस रियासतों के पास लौट जाएँगे।

इस प्रकार रियासतों और ब्रिटिश भारत तथा ब्रिटिश क्राउन (सम्राट) के बीच अब तक जो राजनैतिक सम्बन्ध था वह सम्बन्ध हो जावेगा । और इसका स्थान वह सम्बन्ध ले लेगा जो रियासतें ब्रिटिश भारत की नई सरकार या सरकारों के साथ संघ में शामिल हो कर स्थापित करेंगी । अगर यह न हो सका तो वे इन सरकार या सरकारों के साथ कोई खास राजनैतिक सम्बन्ध या जुलूस कर लेगी ।

[यह स्मृतिस्वरूप चान्सेलर को तारीख १२ मई १९४७ को भेजा गया । पर अखबारों में प्रकाशन के लिए यह तारीख २२ मई को भेजा गया इसके साथ जोड़ी गई टिप्पणी में मिशन ने यह भी कहा है कि गवर्नर लीडर्स के साथ उसने बातचीत शुरू की उसके पहले यह मिशन नहीं था]

नरेशों की प्रतिक्रिया

अब हम कैबिनेट मिशन के कथन पर नरेशों तथा जनता पर जो असर पड़ा उसका निरीक्षण करें ।

नामो और सार्वभौम सत्ता के बारे में दिया है—गौर से अध्ययन किया। कमिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान को अपनी आजादी हासिल करने के लिए आवश्यक तत्र तथा आगे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण आधार प्रदान करती है। सार्वभौम सत्ता के बारे में मिशन की घोषणा का कमिटी स्वागत करती है परन्तु बीच की अवधि के लिए कुछ तात्कालिक व्यवस्था की जरूरत होगी।

२ फिर भी योजना में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका खुलासा हो जाना जरूरी है। फिर कई जड की महत्वपूर्ण बातें बातचीत और निर्णय के लिए छोड़ दी गई हैं। इसलिए निगोशियेटिंग कमिटी बनाने के लिए वाइसराय ने जो निमन्त्रण दिया है उसे कमिटी ने स्वीकार कर लिया है और चान्सलर सा. की योजना में बताये अनुसार वहस और बातचीत करने की व्यवस्था करने की अधिकार दे दिया है। यह योजना की गई है कि इन बातचीतों का नतीजा नरेशों की आम परिपद तथा रिय मनों के प्रतिनिधियों के सामने पेश कर दिया जाय।

३ अंतःकालीन व्यवस्था के बारे में चान्सलर ने जो नीचे लिखे प्रस्ताव किये हैं उनका यह कमिटी समर्थन करती है:—

- (क) अंतःकाल की अवधि में सामान्य हितों के मामलों में बातचीत कर के निर्णय करने के लिए एक स्पेशल कमिटी बना दी जाय जिसमें रियासतों के और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों।
- (ख) न्याय पाने योग्य, कर सम्बन्धी और आर्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में वाद उपस्थित होने पर उन्हें पंच के मामले पेश करने का अधिकार रहे।
- (ग) प्रतिगत या राजवंश से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में उस शासक में निर्णय हो जाय उनके अर्द्ध अर्द्ध का और न्याय

सत्ता के प्रतिनिधि को लिखे अपने उपर्युक्त १६ जून १९४६ के पत्र में नरेशों के दृष्टिकोण को और भी इस प्रकार साफ किया है:—

“डेलीगेशन के वक्तव्य पर नरेशों के विचार पृथक् रूप से एक वक्तव्य में प्रकाशित किये जा रहे हैं। X X परन्तु रियासतों और स्टैंडिंग कमिटी का अन्तिम निर्णय तो इन बातचीतों के बाद संपूर्ण तस्वीर देखने पर ही प्रकट किया जा सकेगा।”

नरेशों को अभी अपने देशभाइयों और जनता से कुछ भय तो मालूम होता ही है। इसलिए चान्सलर वाइसराय को लिखते हैं—“कमिटी को यह विश्वास है कि जो चीजें अभी अनिर्णयित तथा अगली बातचीत के लिये अधूरी पड़ी हैं उन सब का निर्णय आप की सहायता से गियामतो के लिए सन्तोष जनक रीति से हो जायगा।

पर नरेशों का दिल की बात तो उनके आपसी पत्र व्यवहार या भीतरी बातचीत से ही मालूम हो सकती है। इसका एक नमूना इन पत्राग में मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरेश ने अपने अन्य भाइयों को सावधान करते हुए लिखा है।

“हिन्दुस्तान को निकट भविष्य में पूर्ण स्वतन्त्रता देने की योजना ब्रिटिश सत्ता द्वारा हाल ही में हुई है, उसने भारतीय नरेशों की स्थिति को निश्चित रूप से अत्यन्त कमजोर बना दिया है।

त्याग और नक़्क़ कर और फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने में श्रम काम न चलेगा। इनमें हम उल्टा अपने भविष्य को बिगाड़ लेने।”

“छोटी और मझले आकार की रियासतों की समस्या को सुलझाने के लिए हम जो उपाय काम में लावेंगे वे ऐसे ही होने चाहिए जो अंग्रेजी भारत के नेताओं को मजूर होंगे। उनका आचरण निश्चित रूप से इन सम्बन्धित रियासतों की जनता की भलाई होगा तभी वे सही भी होंगे। जनता के हित का बलिदान करने हुए अथवा उन्हें गौण मानने हुए वर्तमान नरेशों के अथवा उनके सहायों की रक्षा के खयाल में की गई उपाय-योजना नरेशों के लिए न केवल आत्मगत ही नाशित होगी बल्कि उनकी कल की मूल्य का त्याग ही पर ले आयेगी।”

तो इस आदर्श के सही साबित होने की कोई आशा नहीं रही है। आज तो यही शका का विषय बन गया है कि उनका और उनकी रियासतों का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं तो क्या जब कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है, नरेश अब भी राजनीति और राज-काज से पहले की भाँति दूर दूर ही रहेंगे ? या सदियों से अपने जिस स्वर्ग में विचरते रहे हैं उससे बाहर निकल कर इस सघर्ष भरी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जावेंगे, जहाँ कि उनके व्यक्तित्व, वैभव और सत्ता के लिये जिसका कि वे आज तक उपभोग करते आये हैं आदर का नामो निशान भी नहीं होगा। नरेशों को खूब सोच विचार कर तुरन्त निर्णय कर लेना है कि वे क्या करेंगे ?”

इसके बाद प्रान्त की रियासतों का किस प्रकार एक सघ निर्माण करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि “जिस यूनियन का विधान आपके विचारार्थ भेजा जा रहा है उसमें नरेशों का भी एक कौंसिल होगा जिसके अन्दर नरेश बैठ कर अपने प्रान्त के पूरे यूनियन के शासन में भाग लेंगे। और इस यूनियन की सरकार को वे जो मना और जिम्मेदारियाँ सौंपेंगे उनके निर्वहन में अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे। यह सच है कि यह स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे अब तक उपभोग करने आये हैं और शायद इसको वे पसन्द भी न करें। पर सवाल यह है कि दूसरे किस प्रकार वे प्रान्त की यूनियन सरकार से अपना सम्बन्ध रख सकते हैं जो कि एक सुन्दर सुसंगठित शासन प्रणाली होगी। कौंसिल ऑफ प्रिन्सेस के स्थान पर बड़ी आसानी से कौंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई जा सकती है जिसके अन्दर रियासतों की सरकारों के प्रतिनिधि चुनाये जा सकते हैं। शायद इन कई नरेश मजूर भी कर लें। उनके मंत्री तो उन्हें पसन्द कर लेंगे और दूसरे तो ऐसा चाहेंगे भी। पर नरेशों को यह रचना चाहिए कि इसने तो नारी राजनैतिक सत्ता उनके हाथों में हमेशा के लिए निकल जावेगी और वे हाथ मलने रह जावेंगे।

तो क्या वे पेंशन और जेब खर्च ले कर पेंशन के राजस्व में निवृत्त हो जाना पसन्द कर लेंगे ? स्टेट्स को वे और उनके राजस्व

पहले के राजवंशों के समान दुनिया में गिटे जावेंगे। क्योंकि आगे चल कर पेशानों को दन्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरी तो मलाह है कि इस समय नरेशों को अपने वैभव, भारी शान, वर्तमान मत्ता और प्रतिष्ठा के ऊपर में जारी रहने के दिखावे के मोह को भी हटा देना चाहिए। वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जावें। यों भी उनके पर तो कट ही गये हैं। उनकी वह मत्ता, वैभव और प्रतिष्ठा भी गई। शान-शौकत भी कहा रही। फिर भी अगर वे अपने स्थान पर बने रहें और प्रजाजनों के साथ प्रान्त के राजकाज में भाग लेने रहेंगे तो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे।”

“सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी प्रान्तीय यूनिवर्स को हम अपनी क्या-क्या मत्ता दें? आमतौर पर नरेशों की वृत्ति इस विषय में यह हो सकती है कि हम उनकी ही मत्ता प्रान्तीय केन्द्र को दें जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। पर मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इन विषय में कोई निर्णय लेने से पहले देश की परिस्थिति व समय की आवश्यकता पर पूरी महारद के साथ विचार नहीं किया गया तो भारी गलती होगी। हमें केवल यही नहीं सोचना है कि हम सिर्फ बरी बात करेंगे कि जो टल नहीं सकती। बल्कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्त देश की उन्नति में क्या करना लाभदायक होगा?”

उन और अनुशासन को उतना ही मजबूत बनाना होगा। ऐसे सघ के बनाने में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना होगा—

(१) कानून बनाने के सम्बन्ध में केंद्रीकरण की नीति से काम लिया जाय। अर्थात् सारी यूनियन के लिये कानून एक-से हो, परन्तु इनके अमल में विकेन्द्रीकरण की नीति बरती जाय अर्थात् प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति को देख कर के अपने ढंग से उस पर अमल करे।

(२) जहाँ-जहाँ शासन का विकेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियन को उसकी देख-भाल, मार्गदर्शन और नियंत्रण का पूरा अधिकार हो।

(३) इस यूनियन का संगठन और विधान बहुत अधिक संगठित और केन्द्रीय पद्धति का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की अधिकांश सदस्य रियासतों में साधनों और योग्य आदमियों के अभाव और नागरिक जिम्मेवारी की भावना का ठीक-ठीक विकास नहीं होने के कारण, वे व्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेगी। इस अर्थ में व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक रियासत में अलग अलग जिम्मेदाराना हकूमत न तो संभव है और न इष्ट ही है। हाँ, पूरी यूनियन में जनतन्त्र शासन पद्धति कर देने से राजनैतिक नेताओं को जरूर सन्तोष हो सकन है।

(४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानून और न्यायालय भी होने चाहिए। क्योंकि उसके अन्दर अनेक रियासतें होने के कारण प्रायः दिन शासन सम्बन्धी अनेक उलझने खड़ी होती रेंगी, उनका ब्यां निर्णय हो जाय।

(५) यूनियन का कोष इसके लिए प्रत्येक राज्य की तरफ से कुछ का सौंप दिये जावे।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कानून का विधान बहुत साफ नहीं है। विधान के अनुसार उन्ने के मन्त्र

होगी। एक का नाम कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस होगा और दूसरी का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। पहली में बड़ी गिमानतों के राज और छोटी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक प्रतिनिधि होगा। कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस के सदस्य नरेशों का एक एक सदस्य होगा।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ५० हजार पर एक इन हिसाब में प्रजाजन के प्रतिनिधि होंगे। २५ हजार से ऊपर वाले सन्त का भी एक प्रतिनिधि होगा। चुनाव के लिये रियासतें मिल भी सकती हैं। कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस अपने में से एक सदस्य को यूनियन का अध्यक्ष चुनेगा जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा। अध्यक्ष यूनियन का वैधानिक प्रधान होगा और यूनियन की कौन्सिल की सलाह ले काम करेगा।

यूनियन की कौन्सिल में मात्र सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस उन नामों की सूची में से करेगी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा भेजी जायेगी। इसमें ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता है जो यूनियन एग्जेक्यूटिव की सदस्यता की पात्रता रखता है।

यूनियन के अधीन सभी विषयों पर दोनों हाउस अलग अलग विचार करेंगे।

और व्यावहारिकता का ध्यान रखने वाली भी है। परन्तु इसमें भी प्रजा-जनो की सत्ता को मुक्त हृदय से सर्वोपरि नहीं माना गया है। नरेशो के हाउस को प्रजा प्रतिनिधियों के समान अधिकार देने से प्रगति में बाधा ही पड़ने वाली है। क्योंकि नरेशों और प्रजाजनो की मनोवृत्ति स्वार्थ, सत्कार तथा भूमिका में स्वभावतः बड़ा अंतर होने के कारण बार बार गतिरोध का अन्देशा रहेगा। शोषण कम जरूर होगा पर किस हद तक कम होगा इसका ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

दूसरी योजना बुन्देलखण्ड के नरेशों की है, वह इससे कहीं पिछड़ी हुई और प्रतिगामी है। इसमें रूलर्स चेम्बर और पीपुल्स एसेम्बली इस तरह दो सभाये होंगी। इसका नाम युनायटेड स्टेट्स ऑफ बुन्देलखण्ड होगा। शामन रूलर्स चेम्बर पीपुल्स एसेम्बली के सहयोग से करेगा। रूलर्स चेम्बर में बुन्दलखण्ड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले सभी अधिकार इस रूलर्स चेम्बर को होंगे, जिसकी मन संख्या ६६ होगी। सदस्य तो कम होंगे पर नरेशों की अपनी अपनी रियासतों की आवादी के अनुसार कम या अधिक मत होंगे।

पीपुल्स एसेम्बली में १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होंगे, जिनमें में ७७ बालिग मताधिकार के अनुसार इतने ही चुनाव क्षेत्रों में चुने जायेंगे और ५० में ले कर ७० नामजद होंगे। प्रजा प्रतिनिधियों को एक एजेंड ही होगा।

नामजद सदस्यों की तफसील यह है—

(क) प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्री—	५ = ७
(ख) रियासतों के जागीरदार	२० = २५
(ग) पिछड़ी जातियाँ	१० = १५
(घ) मजदूर वर्ग	१० = १५
(ङ) विशेष हित	५ = ८

मोटे तौर पर रूलर्स चेम्बर तथा पीपुल्स ऐसम्बली को प्रत्येक रियासत में नीचे लिखे अनुसार मन होंगे।

रियासत	आवादी	रूलर्सचेम्बर	पीपुल्स ऐसम्बली
ओगछा	३ लाख	१२	१०
दतिया	११	१२	६
ममथर	३३	४	३
पन्ना	२	६	७
नरखारी	१,२०	७	४
अजयगढ़	८६	१	३
मैर	६१	४	३

इस प्रकार बड़ी रियासतों के नरेशों को अधिक और छोटी रियासतों के नरेशों को कम मन होंगे।

रूलर्स चेम्बर एक एजीक्यूटिव कौन्सिल या चुनाव करने अन्दर से करेगा। उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तीन में ले २००० सदस्य होंगे। यह कौन्सिल रूलर्स चेम्बर की तरफ से यूनिफ़ॉर्म के नाम पर शासन संचालन का काम करेगी। इसका कार्यालय पाँच साल का होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और कार्यालय भी यही होगा।

३० प्रतिशत तक की व्यवस्था रखी गई है जो स्पष्ट ही अत्यधिक है । आज के वातावरण में ऐसी योजनाओं को देख कर हसी आती है ।

मध्यभारत की कुछ छोटी रियासतों ने मिल कर यह तय किया है । बताया जाता है कि वे अपने ऐसे अलग अलग सघ बना लें जिनकी सलाना आय लगभग एक करोड़ के हो । इस योजना में खास हाथ भोपाल नरेश का दिखाई देता है । क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती यह रियासत स्वतंत्र यूनिट के रूप में कायम रह ही नहीं सकती ।

महाराष्ट्र की रियासतों के नरेश भी मिल कर अपना एक सघ बनाने का विचार कर रहे हैं । पिछले दिनों वे महात्माजी से मिले थे । पर उनकी तरफ से उन्हें प्रोत्साहन ही मिला । महात्मा जी ने सलाह दी कि वे जो कुछ करना चाहे देशी-राज्य लोक-परिषद के अध्यक्ष प० जवाहरलालजी की सलाह और मार्ग-दर्शन में करें ।

नरेशों की एक और ऐसी योजना का भी पता लगा है । कहा जाता है कि काठियावाड़ गुजरात (बड़ौदा उनमें शामिल नहीं) दक्षिण राजपूताना मध्यभारत और उड़ीसा तक की रियासतें मिल कर वे पूर्व समुद्र से ले कर पश्चिम समुद्र तक का एक लम्बा रियासती कटिबन्ध बनाना चाहते हैं । दोनों समुद्रों पर उनके बन्दरगाह होंगे । और अपनी एक रेलवे लाइन भी होगी ।

हिन्दुस्तान के सवाददाता ने अपने ३ अगस्त का एक मसौदा में लिखा है—‘ नरेश इस बात का बड़ा टिठोरा पीटते रहे हैं कि हम भारत के वैधानिक विकास में बाधक नहीं बनना चाहते ’ पर वह अब टोला पड़ता जा रहा है । इस समय उनका रख यह जान पड़ता है कि ब्रिटिश सत्ता के भारत से हट जाने के बाद रियासतें स्वतंत्र हो जाती हैं । उन पर किसी सर्वोपरि सत्ता का प्रभुत्व नहीं रह जाता, भारतीय संघ में वे विदेशी

सम्यक्, यातायात और रक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। ने १।
सन्धि के बाद।

सन्धि को मोक्ष अग्नी पूर्ण स्वतंत्रता का दोषक समझते हैं। एक क्ष-
भी विचार है कि केन्द्रीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सन्धि करने का
न करने की स्वतंत्रता भी राज्यों की है।

सन्धि में अच्छी से अच्छी गतों पाने के लिए गुटबन्दी का प्रयोजन
किया जा रहा है। ऐसे नीति निवेत्ता प्रचलित गुट नाशक हेतु प्रत्येक
गुट की निदामतों की सख्या बर्णन इस प्रकार है:—

गुट	संख्या	रकबा	जन सं०	शक्ति
(१) दक्षिणी भाग की रि०	१६	२८०००	३.८	७
(२) गुजरात की रि०	१७	७०००	१.३	१८
(३) मध्य-भारत की रि०	२८	४१,०००	१.८	८
(४) पूर्वी-भारत	२५	५६०००	१.८	५
(५) दक्षिणी रि०	१८	१००,००	१.५	१.५
(६) पश्चिमी रि०	१७	५००००	१.५	८.५
(७) गन्धर्वना की रि०	२१	१०००००	१.३	१२

कल्पना का राजस्थान ही है, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की स्वाधीनता और एकता के लिये बाधा जनक होगा ।

नरेश इस हलचल में लगे हैं इसके कुछ और भी प्रमाण मिल रहे हैं । पश्चिमी भारत की कुछ रियासतों की एक कान्फ्रेंस सितम्बर के प्रारंभ में हुई थी । जिसमें उन्होंने पश्चिमी भारत और गुजरात की रियासतों का ग्रुप बनाने का निश्चय किया और उन्हें जबरदस्ती कहीं अन्यत्र मिला देने का विरोध किया ।

उड़ीसा की रियासतें प्रान्त से स्वतंत्र नहीं रह सकती । उनका प्रदेश बहुत छोटा है । राष्ट्र निर्माण, कानून और सुव्यवस्था, वगैरह सब उनके लिये असंभव होगा पहले वे उड़ीसा की मुहताज रहो हैं । ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा के प्रधान मंत्री श्री हर कृष्ण गेटताव से सलाह लेकर उड़ीसा के नरेशों ने अपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिसमें यह तय हुआ था कि श्री मेहताव भी उपस्थित, रहेंगे और उनके मामले में रियासतों के भविष्य पर विचार करेंगे । परन्तु कहा जाता है कि बीच ही में एक दिन उन्होंने अपनी बैठक कर ली । श्री मेहताव को उसी समय दिन की सूचना भी नहीं दी और निश्चय कर लिया कि वे प्रान्त में शामिल नहीं होंगे जब कि इन रियासतों के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि ये रियासतें उड़ीसा प्रान्त में मिला दी जावे ।

इस प्रकार नरेशों पर मिशन की घोषणा का असर तो सर्वत्र यही हुआ है कि अब हमारा भविष्य खतरे में है परन्तु उसकी उद्धार-योजना प्रत्येक प्रान्त के नरेशों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग प्रकार से की है । कुछ बिल्कुल पिछड़े हुए प्रतिस्पर्धावादी हैं तो दूसरे अधिक उदार हैं । परन्तु अपने पद और राजवंश का रक्षण और उसे बनाये रखने की चिन्ता सभी की है । और यह स्वाभाविक भी है ।

जनता की प्रतिक्रिया

कांग्रेस और लोक परिषद् के प्रस्ताव

कांग्रेस और क. मा. देशीराज्य लोक परिषद् ने केंद्रित डेलीगेशन के वक्तव्य के रियासतों सम्बन्धी हिस्से पर अपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावों में प्रकट की है—

कांग्रेस की कार्य समिति ने वा. २४ मई को मिशन के वक्तव्य पर एक लम्बा प्रस्ताव मंजूर किया था। उसमें देशी राज्यों ने सम्बन्धित अंश पर कार्यसमिति ने कहा है—

कांग्रेस का प्रस्ताव

"वक्तव्य में रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह असंगत है और बहुत कुछ आगे के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी कार्य समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि विधान सभा एक दम बेमेनतियों की नहीं बन सकेगी। और रियासतों की तरफ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका ऐसा जबर हो कि जो प्रांतों का चुनाव पद्धति से जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक मिलता जुलता हो।

अखिल भारत देशीराज्य लोकपरिषद् को—जनरल कौन्सिल ने डेलीगेशन के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मजूर किया:—

“केबिनेट डेलीगेशन और वाइसराय ने हिन्दुस्तान के लिए विधान बनाने के सम्बन्ध में समय समय पर जो वक्तव्य दिये, उन पर अ. भा. देशी रा० लोक परिषद् की जनरल कौन्सिल ने विचार किया। कौन्सिल को यह देख कर आश्चर्य और दुख हुआ कि इन तमाम बातचीतों और मशविरों में रियासती प्रजाजनो के प्रतिनिधियों को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कानून का रूप धारण कर सकता है और न उसका कोई परिणाम हो सकता है, जब तक कि वह रियासतों की नौ करोड़ जनता को लागू नहीं होगी। और जब तक इनके प्रतिनिधियों को इन मशविरों में शामिल नहीं किया जायगा, ऐसा कोई विधान बन भी नहीं सकता। हिन्दुस्तान के इतिहास में इस नाजुक प्रसंग पर रियासती जनता को जिन प्रकार में अलग रख कर उसकी अवगणना की गई उस पर यह कौन्सिल अपना रोष प्रकट करती है।

फिर भी कौन्सिल ने तमाम खतरों का पूर्ण विचार कर लिया है और स्वतंत्र और संयुक्त भारत के निर्माण में—रियासतों जिसका आवश्यक और स्वयं शासित अंग होंगी—सहयोग देने को वह अब भी तैयार है। रियासती जनता की नीति का निर्णय उदयपुर के पिछले अविवेशन में कर ही दिया गया है। यह कौन्सिल उसी पर कायम है। रियासतों में जनता की पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत हो और रियासतों स्वतंत्र सशस्त्र भाग के अंग हों। इस आधार पर वह नीति कायम की गई है। उसमें यह भी कहा गया था कि भारत का शासन-विधान बनाने के लिए जिन किसी सस्था का निर्माण होगा, उसमें रियासती जनता के प्रतिनिधि हों और वे व्यापक मताधिकार के आधार पर चुने जावें।

नेरेशो की तरफ से स्वतंत्र और संयुक्त भारत के पत्र में जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया है उसका यह कौन्सिल स्वागत करता है। स्वतंत्र

रियासतों के लिए ऐसे ही विधान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कौन्सिल की राय है कि इस त्रुटि की पूर्ति होना जरूरी है। विधान-परिषद में प्रान्तों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों का भी शुरू से शामिल रहना इष्ट है। ताकि रियासतों के प्रतिनिधि भी अलग बैठ कर जबकि प्रान्तों के प्रतिनिधि प्रान्तों का विधान बनाते रहेंगे रियासतों के विधानों के लिए कुछ आधारभूत बातों को तय कर लेंगे।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस कौन्सिल की राय है कि सीधे चुनावों के आधार पर बनी हुई धारा-सभाएं जहाँ जहाँ भी हों, उनके सदस्यों को विधान-परिषद के लिए रियासतों के प्रतिनिधि चुनने वाले मनदाता बना दिये जायें। पर यह कदम तभी उठाया जाय जब सम्बन्धित रियासतों में नये सिरे से धारा-सभाओं के स्वतन्त्र चुनाव हो जायें।

दूसरी तमाम रियासतों के लिए अ. भा. देशीराज्य लोकपरिषद की रीजनल कौन्सिल के द्वारा विधान परिषद के प्रतिनिधि चुने जायें। छोटी रियासतों की तरफ से सही प्रतिनिधि चुनने का मौजूदा स्थिति में यह अच्छे से अच्छा तरीका होगा।

कौन्सिल की यह भी राय है कि कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा चुनायी गई निगोशिएटिंग कमिटी में रियासती जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए।

स्थापित करने का काम करे ताकि उनके शासनो में किसी हद तक समानता लाई जा सके ।

इसी प्रकार जिम्मेदाराना हुकुमत की दिशा में रियासतों के भीतरी शासन में सुधारों के कदम जल्दी जल्दी बढ़वाने की दिशा में भी यह कौन्सिल काम करे । फिर यह कौन्सिल रियासतों के समुदायों के प्रश्न पर भी विचार करे और देखे कि इनके किस प्रकार न्याय दनाये जा सकते हैं, जो विशाल भारतीय न्याय की इकाई बनने लायक बनें हों और अन्य रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया जा सके ।

अंतःकाल की अवधि के बाद रियासतें एक एक या समूहों में मिल कर संघीय यूनियन में समान अविवार वाली बराबरी का इकाया होगी । उनका भीतरी शासन भी प्रान्तों के समान जनतन्त्र ही होगा ।

(जून ११ मनु १९४६ दिना.)

सतों के निवासियों की शिक्षा, आरोग्य, शासन प्रबन्ध अथवा अन्य सुख सुविधाओं पर लगाया जाता होगा । परन्तु इतनी छोटी-छोटी रियासतों की क्या तो आय हो, क्या उनको शासन प्रबन्ध हो, और क्या वे अपने प्रजाजनो को सुख-सुविधाये दे । यह तो सारी-की-सारी रकम इनके नरेशो या जागीरदारो के खानगी खर्च मे ही चली जाती है और प्रजाजन जीवन की आवश्यक शिक्षा-आरोग्य आदि की सुख-सुविधाओं मे वंचित रह जाते है ।

एक दूसरा उदाहरण ले । कानियावाड की २७४ छोटी रियासतों की आय १, ३५, ००,००० होती है । और इस आय मे २७४ छोटी-छोटी सरकारे चल रही है । इनमे १० जग बड़ी रियामतों को छोड दे तो प्रत्येक रियासत का औसत रकवा २५ वर्गमील और औसत आबादी ५०० मनुष्यो की पडती है । २०२ रियामने इतनी छोटी है कि उनका रकवा पूरा १० वर्गमील भी नहीं और १३६ रियामने ऐसी है, जिनका रकवा ५ वर्गमील के अन्दर-अन्दर है । ७० रियामने १ वर्गमील के भी अन्दर वाली हैं । स्पष्ट है कि ऐसी नामवारी रियासतों के लिये भावी शासन विधान मे कोई स्थान नहीं हो सकता ।

रह सकेंगी। परन्तु उदयपुर अधिवेशन में इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हुआ, उसमें इन दो शर्तों को ऊँचा कर दिया गया। उसमें ठीक मर्यादा तो नहीं बताई पर मोटे तौर पर यह बात जरूर कह दी कि वे ही रियासते स्वतंत्र इकायों के रूप में रह सकेंगी, जो अपने प्रजाजनों के लिये आधुनिक सुधार हुए शासन की तमाम सुख-सुविधाएँ मुहैया कर सकेंगी। इस प्रश्न पर लोक परिषद के जनरल कांसिल की जून १९४६ वाली बैठक में फिर विचार हुआ और अपने प्रान्तीय म्हादजों को कांसिल ने यह आदेश दिया कि वे अपने प्रदेशों में रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों की मलाह ले कर यह बतावे कि वहाँ उपर्युक्त कमीटियों को ध्यान में रखते हुए रियासतों का समूही करण किस प्रकार करना चाहते हैं। प्रत्येक प्रान्त ने इस सम्बन्ध में चर्चाये हुई। और प्रायः सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि इसी निर्णय पर पहुँच गये हैं कि —

(१) रियासत या उन के समूह छोटे छोटे नहीं, काफी बड़े हैं, जिनमें वे अपने प्रजा जनों को आधुनिक शासन की तमाम सुविधाएँ द सकें।

(२) बड़ी रियासतों को भंगे ही नहीं देने दिया जाय परन्तु छोटी रियासतों के अलग समूह बनाने या उनके बड़ी रियासतों में शामिल करने का प्रयत्न करके को बढ़ाने में बड़ा प्रयत्न होना चाहिए। प्रान्तों के मिला दना या फिर अन्यथा होगा।

(१) कश्मीर और जम्मू खुद बखुद एक काफी बड़ी रियासत है ।

(२) पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद ने यह तय किया है कि सिक्ख रियासतों को छोड़ कर शेष को ब्रिटिश प्रान्त में मिला दिया जाय ।

(३) हिमालय प्रदेश की छोटी रियासतों को भी पंजाब में मिला देने की सिफारिश इन रियासतों के प्रतिनिधियों ने की है ।

(४) राजपूताना के रिजनल कौन्सिल ने यह तय किया है कि समस्त राजपूताने का एक पूरा यूनिट बना दिया जाय । और अजमेर मेरवाड़े का ब्रिटिश जिला भी इस यूनिट में जोड़ दिया जाय ।

(५) मध्य-भारत में छोटी-मोटी बासठ रियासतें हैं । युक्त प्रान्त की रामपुर और बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकड़ाई नामक एक छोटी-सी रियासत भी मध्यभारत के साथ ही जुड़ी हुई है । प्रादेशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि इन दीगर प्रान्तीय रियासतों को अपने अपने प्रान्तों अर्थात् क्रमशः युक्त प्रान्त और मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाय । इसके बाद इतिहास, संस्कृति, भाषा, परम्परा और भूगोल की दृष्टि से मध्यभारत के दो स्वतंत्र विभाग रह जाते हैं—मालवा और बुन्देलखण्ड-वधेलखण्ड । प्रादेशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि मध्यभारत के ये ही दो स्वाभाविक यूनिट बना दिये जायें । मालवा में ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, और मालवा तथा भोपाल एजन्सी की रियासतें रहे और दूसरे यूनिट में बुन्देलखण्ड-वधेलखण्ड की तमाम रियासतें रहे । इस यूनिट को बड़ा और स्वतन्त्र बनाने के लिए भाषा और संस्कृति की दृष्टि से इनमें यू. पी. के दादा और जालौन जिले भी जोड़े जा सकते हैं जो वास्तव में बुन्देलखण्ड के ही भाग हैं । इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पुनः संगठन की चर्चाये चल रही हैं । अतः उसके भी वे हिस्से जो इन उपर्युक्त दो विभागों में संस्कृति भाषा वगैरा में मिलने जुलते हों, उन्हें इन समूहों में जोड़ दिया जाये ।

इस प्रकार मध्यभारत के दो ग्रुप होंगे उनका आकार आबंदी और आय इस प्रकार होगी:—

मध्य भारत के दो ग्रुपों के आंकड़े

ग्रुप	सि० की संख्या	संख्या	आबंदा १९४१	आय १९३६
नीची दुन्देलखण्ड	३४	२४,४२६	३४४२३३१	१,३६,२५०००
बृहत् मालवा	२५	५३,७८०	७६,८८८८६	५,६३,०१०००

(६) उड़ीसा की तमाम रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपनी गिरफ्तारों को प्रान्त के साथ मिला देने की सिफारिश की है। (नगेरों ने इन्का विरोध किया है।)

(७) महाराष्ट्र की रियासतें बहुत छोटी छोटी और गिनी हुई हैं। अतः इनके प्रतिनिधियों की सिफारिश है कि इन्को अपने प्रान्त में जोड़ दिया जाय।

(८) गुजरात काटियावार के गिरफ्तारों का संयोजन की कोई योजना अभी तक देखने की नहीं मिली है।

(१२) सीमान्त प्रान्त की रियासते प्रान्त में ही मिला ली जावे ।

(१३) बलूचिस्तान की कलात वगैरा रियासते ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रान्त में जोड़ दी जावे ।

यह तो मोटे तौर पर लोक प्रतिनिधि किस दिशा में सोच रहे हैं वह हुआ । नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा में सोच रहे हैं । वे न केवल ब्रिटिश प्रान्तों में अपने प्रदेशों को मिला देने के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते हैं कि उनकी अपनी रियासते अलग रहे और उनकी राजगद्दी और राजसत्ता भी बरकरार रहे । बड़ी रियासतों के बारे में जहाँ तक उनकी प्रादेशिक सीमाओं और राजगद्दी या राजवंश के बने रहने से तात्पर्य है, शायद यह सभव है. वशर्ते कि वे अपने राज्यों में प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन शुरू कर दें । परन्तु ऐसी रियासते तो ५-१० ही हो सकती हैं । शेष तमाम छोटी रियासतों को तो अपने अपने प्रादेशिक समूह बना कर सघ प्रणाली से ही राज्य करना होगा । और इन मधो में भी उत्तरदायी शासन तो होगा ही । पर प्रत्येक अग का अलग अलग नतीजा का मिल कर उत्तरदायी शासन होगा । इस चीज को नंग भी समझने लग गये हैं । परन्तु उनमें अभी इतनी दूरदर्शिता और साहस नहीं आया कि वे अभी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके अपने प्रजाजनों के दिलों में अपने लिए स्थान पैदा कर लें । इसके विपरीत वे अभी तक अपनी गौर जिम्मेदार निरकुशता के ही सपने देखते हैं । और इनके दिमाग और सलाहकार वगैरा भी इनने बहुत आगे नहीं हैं । शायद पीछे ही हैं । उत्तरदायी शासन देने का विचार अगर कोई राजा कर भी सके तो वे उसके इस कार्य को आत्मघातकी कहते हैं और आज हम उम्मेद में भी लोकमत के प्रति इनके दिलों में निगाह और दिग्दर्शन पाया जाता है । अपनी कोठियों में बैठे बैठे वे अब तक यही अनुमान नहीं लगा पाये हैं कि लोक-शक्ति क्या वस्तु है । वस्तु में पोलिटिकल डिस्टेंस के अन्तर्गत ये कर्मचारी ही नियामतों में लोक शक्ति के सपने रहे जाते हैं । इनके

है, बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। जनता चाहती है कि वह समस्त देश के साथ रहे अतः इस बात के लिए जनता बड़ी अधीर और आतुर है कि ये परिवर्तन जल्दी से जल्दी हो। इन परिवर्तनों में तथा रियासतों में जिम्मेदाराना हुक्मत की स्थापना में जितनी देरी होगी उनसे गहरा अस-
तोष फैलेगा और शायद अनिष्ट परिणाम तथा संघर्ष भी होने की सम्भा-
नाये है।

परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग कमिटी महसूस करती है कि रियासतों में जिम्मेदाराना हुक्मत की स्थापना के कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिए। ये कदम शेष भारत में हुए परिवर्तनों की दिशा में हो अर्थात् रियासतों में भी जनता की विश्वास पात्र अतःकालीन सरकारों की स्थापना हो। रियासतों की ये अतःकालीन सरकारें वहाँ पूर्ण उत्तरदायी शासनो की स्थापना के लिए तथा पड़ोसी रियासतों और प्रान्तों के साथ सघ बनाने या पूर्णतया मिल जाने के सम्बन्ध में- बातचीत करने के लिए लोकप्रिय विधान निर्मात्री सभ्य और के चुनावों की तैयारी के लिये उपयोगी-
तत्र निर्माण करने का काम करें।

अखिल भारत विधान परिषद की योजना से यह कार्य पद्धतिमेल खाती हुई है। और इससे विधान परिषद में रियासतों की तरफ से उचित प्रतिनिधि भेजने में भी मदद मिलेगी।

अखिल भारतीय और रियासती परिस्थिति की गंभीरता, तथा घटनाये जिस वेग से घटती जा रही है उन्हें देखते हुए ऊपर बताये अनुसार रियासतों की समस्या को मुलभाना जरूरी है। जब कभी यूनिन और मौलिक अधिकारों और अन्य विषयों सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हो और रियासतों के प्रतिनिधियों को अखिल भारतीय विधान परिषद में उपस्थित रहने की जरूरत हो, तो उसके लिए भी इन प्रश्नों की तरफ ध्यान देना जरूरी है

निगोजियेटिंग कमिटी के सम्बन्ध में

—ता. १८ सितम्बर की अपनी बैठक में छ. भा. देशी राज्यलोक-पत्रिण्ड की स्टैण्डिंग कमिटी ने नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया था—

स्टैण्डिंग कमिटी को अफसोस है कि निगोजियेटिंग कमिटी के सदस्यों की नियुक्ति न हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में कमिटी प्र० भा० देशी राज्य लोक पत्रिण्ड के ता० ११ जून के प्रस्ताव की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाती है।

स्टैण्डिंग कमिटी की राय है कि कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के अनुसार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जाना उचित है। क्योंकि उस वक्तव्य में कहा गया है कि अन्तिम विधान पत्रिण्ड में रियासतों को नै उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो ब्रिटिश भारत के विधाय में ६३ में

—ता० १४ सितम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में निगोजियेटिंग कमिटी के सदस्यों के नाम इस प्रकार प्रकाशित हुए हैं:—

- (१) भोपाल नवाब नरेन्द्र मण्डल के चान्तलर
- (२) महाराजा पटियाला प्रोचान्तलर
- (३) नवा नगर के जाम साहब
- (४) इगरपुर नरेश
- (५) नर मिर्जा इस्माइल, निजाम की एजेंस्यूलिजरी कमिटी के प्रेसीडेंट
- (६) सर रामस्वामी मुदालियर, मनोर के सीजान
- (७) सर मी. पी. रामस्वामी ऐयर, ट्राय एजेंसरी के सीजान
- (८) सर मुल्तान एहमद, कान्तिट्रिब्यूनल एजेंसरी के प्रोचान्तलर
- (९) मन्दाय के एम. फकीर, बीकानेर के प्रोचान्तलर

मीर मन्सूर मन्सूर इन कमिटी के सेक्रेटरी का काम करेंगे।

(अ प्र)

अधिक नहीं होगा । पर इन प्रतिनिधियों के चुनाव का निश्चय बाद में आवश्यक मशविरा करके कर लिया जावेगा । शुरू शुरू में रियासती का प्रतिनिधित्व निगोशियेटिंग कमिटी करेगी । फिर बाद में भारत मन्त्री ने अपने १७ मई के खुलासे में कहा है—निगोशियेटिंग कमिटी का निर्माण तमाम सम्बन्धित पक्षों की सलाह से किया जायगा ।

तदनुसार कमिटी का यह मत है कि जब तक निगोशियेटिंग कमिटी में रियासती जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसका निर्माण वैध नहीं माना जायगा ।”



के जानकार उन्हें सलाह देते कि नरेशों की निगह बानी पोलिटिकल एजन्ट किया करते हैं। उनसे शिकायत करनी चाहिए। इस तरह व्यक्तिगत मामले पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट के पास पास पहुँचते। किन्तु जनता को तो कुछ भान भी नहीं था। धीरे धीरे ब्रिटिश भारत की राजनैतिक हल चलो का उस पर भी असर पड़ने लगा और सामूहिक शिकायतें भी पोलिटिकल एजन्ट के पास कार्यकर्त्ताओं के पास जाने लगे। किन्तु ज्यों ज्यों उनका स्वाभिमान जागृत होने लगा कार्यकर्त्ताओं को अपने ही नरेशों की शिकायतें विदेशी सत्ता के राजनैतिक विभाग के पास ले जाना अपमानजनक मालूम होने लगा। और वे कांग्रेस के नेताओं के पास आने लगे। किन्तु जैसा कि हम देखते हैं कांग्रेस ने शुरू शुरू में कई वर्षों तक अपने आपको रियासती राजनीति से अलग रखा। वह समझते थे कि सारी बुराइयों की जड़ तो विदेशी सत्ता है। उसके हटने पर उसके भगोसे पर कूटने वाले नरेश अपने आप सीधे हो जावेंगे और दूसरे अगर मान लें कि हमें नरेशों से लड़ना है तो भी आज ही उनसे भी लड़ाई मोल लेना बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने रियान्ती जनता और कार्यकर्त्ताओं को यही समझाया कि अभी कांग्रेस उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। सबसे पहला और जरूरी मसाला तो है विदेशी सत्ता को यहां से हटाना। और इसलिए पिलहल रियान्ती में दीवार से तिर टकराने की अपेक्षा वे भी अपनी मार्ग मार्ग ब्रिटिश भारत की लड़ाई में ही लगा दें। नेताओं की इन मताह को रियान्ती कार्यकर्त्ताओं और जनता ने भी माना और ब्रिटिश भारत की लड़ाई में पूरा सहयोग दिया। और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ। हमें--

(१) ब्रिटिश भारत के नेता रियान्ती और रियान्ती कार्यकर्त्ताओं के अधिक सम्पर्क में आये और इन प्रश्न में उनकी दिलचस्पी बढ़ी।

(२) ब्रिटिश भारत और रियान्ती कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध

आक्रमण में अंग्रेज सरकार की ताकत भी कमजोर हुई ; कमजोर बंदूक शक्ति के सामने झुक चली ।

(३) कार्यकर्ताओं, तथा जनता पर भी असर पड़ा । रियामनी कार्यकर्ता अपने ब्रिटिश भाग्य के अनुभव की लेकर रियामनों में विविध प्रकार की सार्व-जनिक प्रवृत्तियाँ शुरू करने लगे और जनता भी अथ उभरी। इन सेवाओं में प्रभावित होने लगी ।

रियामनी अविकारियों के दृष्टि कोण में भी तमश, कुछ फर्क पड़ने लगा—यद्यपि उनके प्रत्येक व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ा ।

(४) रियामनों में अपने अविकारों की प्राप्ति के लिये छोटे बड़े पैमाने पर लडाइयाँ होने लगी और

(५) अन्त में ब्रिटिश भारत तथा रियामनों की जनता दोनों अपने भेद भावों को भूल कर हम नरह एक जीव हो गये कि १९४२ के पिछले सप्ताह में भारत-हिन्दुस्तान एक साथ बनी हो गया । रियामनों और ब्रिटिश भारत में कोई अन्तर नहीं रह गया और इस तरह का परिणाम क्या हुआ ? जैसा कि पण्डित है—

(३) इन घोषणाओं और प्रत्यक्ष घटनाओं से नरेशों की नींद एकदम उचट गई। और अब तक वे जो बिलकुल वे फिक्क थे और अपने प्रजाजनो की कोई परवाह नहीं करते थे सो होश में आ गये। प्रजा-सेवा की भाषा उनकी जवान से सुनाई देने लगी। देश की समस्त जनता के साथ वे भी भारतीय स्वतंत्रता को चाहते हैं ऐसे भाषण और प्रस्ताव भी होने लगे। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनकी पद-प्रतिष्ठा और रियासतों की सीमाये अच्युण्ण रहनी चाहिए।

(४) स्वतंत्र भारत तो सघ-वद्ध होगा। उसमें इतनी छोटी छोटी रियासतों का इकाई के रूप में बने रहना असंभव है। इसलिये नरेश यह भी समझ गये कि छोटी रियासतों को समूह बनाने होंगे। वे यह भी जान गये कि:--

(५) समूह बन जाने पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी। शासन को जनता की इच्छा के अनुकूल बन कर रहना होगा। ऐसा शासन तो जनतन्त्री पद्धति का उत्तरदायी शासन ही हो सकता है। ब्रिटिश प्रान्तों में जनतन्त्री शासन हो और रियासतों में एक तंत्री रहे यह तो असंभव है। अतः इसके लिये भी नरेश अपने को तैयार करने लग गये।

पर यह सब अभी कल्पना जगत और विचार क्षेत्र से होकर योजनाओं के रूप में केवल कागज पर आने लगा है। प्रत्यक्ष व्यवहार की दृष्टि से रियासतों के वातावरण में अभी कोई खास अन्तर नहीं पड़ा है। बल्कि इन सब घटनाओं की उल्टी प्रतिप्रिशा अनेक रियासतों में देखने में आती है। हैदराबाद, काश्मीर, फरीदकोट, भोपाल, बीकानेर वगैरा इसके उदाहरण हैं। इसका कारण नरेशों की निराशा हो सकती है। पर उसने भी बड़ा कारण भारत सरकार के राजनैतिक विभाग की शरास्त, नरेशों का स्वार्थ और रियासती कर्मचारियों की गुलामी भी हो सकती है और इस सब की तर में शायद अंग्रेज कौम की गन्दी नीयत भी हो। कौन जाने। हमने

भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में अब तक इतने और इतनी प्रकार से रोड़े अटकाये हैं कि उसकी नीयत में ऐसा शक होना आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। अन्यथा एक तरफ दिल्ली में मन्त्रि-मिशन काँग्रेस ने मत्ता के परिवर्तन के विषय में सलाह कर रहा है और दूसरी तरफ काश्मीर का प्रधान मन्त्री उमी क ग्रेस के खुद सभापति को गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। पोलिटिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं है ऐसा मैन मानेगा ? फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर अकथनीय जुल्म होते हैं। एक तरफ केन्द्र में अस्थाई सरकार कायम करने की चर्चा होती है और उधर कलकत्ता में भयंकर हत्याकाण्ड होते हैं। एक तरफ अस्थाई सरकार में लीग शामिल होने जा रही है और दूसरी तरफ पूर्व बंगाल में हिन्दुओं का कत्लेआम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण बलात्कार और जबरदस्ती की शादियाँ होती हैं और गाँव के गाँव जला दिये जाते हैं। बंगाल में बागी लोग का मन्त्री-मण्डल होगा। पर साम्राज्य सरकार को चलाने वाले गवर्नर और गवर्नर जनरल भी तो अभी विदा नहीं हो गये हैं। सूचनाएँ मिल जाने पर भी गवर्नर दार्जिलिंग की ओर गवर्नर जनरल बम्बई की सैर पर चले जाते हैं और अल्प संख्यक हिन्दू बहुसंख्यक आजा-ताइयों के सामने बलि के पशुओं के समान अर्पित और हत्या के लिये झोंक दिये जाते हैं। पूर्व बंगाल के विषय में जो बंगाल गवर्नर ने पार्लियामेंट को भेजे उनमें भी घटनाओं की वास्तविकता को दबाया गया है। इन सब को देख कर अंग्रेजों के नियत के विषय में शक होना अतिशय स्वाभाविक है।

ऐसी सूरत में क्या ब्रिटिश भारत की और क्या गिरगिटि जनता को बहुत साराधानी ने आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि सब कुछ ठीक है। अब भी नंगेशों को और दुर्भिक्ष लोग को हिन्दु मान की आजादी का रोका बना कर विदेशी हुकूमत अपने उस को दूर धरा करती है। या कम से कम ऐसा प्रयत्न तो करना चाहती है। अंग्रेजों की कि मुस्लिम लीग के क्रिश्चियन नेताओं ने धमकी दी है कम भी किसी

तीसरी ताकत को लाने का प्रयत्न भी हो सकता है । वह सचमुच आवेगी या उसे आने दिया जायगा या नहीं यह दूसरा सवाल है । परन्तु ये सब घटनाएँ और चिन्ह ऐसे हैं जो सकेत करते हैं कि हमें बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है । इसलिए जहाँ हम इस बात पर समाधान मान सकते हैं कि हमारी बहुत-सी समस्याएँ हल होती जा रही हैं । तहाँ हमें यह नहीं भूलना है कि ऐसी ही बल्कि इनमें भी कहीं अधिक मुश्किल समस्याएँ अभी हमारे सामने हैं और संभव है वे हम से अभी कहीं अधिक त्याग, परिश्रम, दक्षता, एकता और कुर्बानी की अपेक्षा करें ।

वे समस्याएँ क्या हैं ?

हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी विधान परिषद में रियासती जनता के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का है । विधान परिषद में रियासतों के ६३ प्रतिनिधि होंगे । पर इनका चुनाव कैसे होगा ? कुछ नरेशों ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी रियासतों से आधे प्रतिनिधि जनता के चुने हुए और आधे नामजद होंगे । वाजिब तो यही है कि विधान परिषद में सब के सब प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जायें । परन्तु यह कैसे संभव होगा यह कहना कठिन है । अतः कम से कम हमारा यह प्रयत्न तो जरूर हो कि हम अधिक से अधिक प्रतिनिधि जनता के चुने हुए भेजें । पर जब तक हमारी माँग के पीछे मजबूत और व्यापक संगठन का बल नहीं होगा वह सफल नहीं हो सकती । इसलिये एक मगठन के रूप में समस्त देशी राज्यों में इस समय यह जोरदार आन्दोलन छेड़ देने की जरूरत है कि विधान परिषद में जनता के प्रतिनिधि ही जायें । मगठन जितना बलवान होगा उतना ही उसका असर होगा ।

दूसरे अभी जो निगोशियेटिंग कमिटी बनी है उसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि नहीं है हालांकि भारत मन्त्री का यह साफ आश्वासन है कि उसके निर्माण के समय सभी सम्बन्धित दलों से मशविरा कर लिया

जायगा। परन्तु इसका प्रालन नहीं हुआ। हमें अपनी आवाज इस तरह बुलन्द करनी चाहिए कि इसमें प्रजाजनो का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। प्रांतों की तरफ ने जो प्रतिनिधि निगोशियेटिंग कमिटी में दान्तर्वात करने के लिए आवें उन पर, तथा ब्रिटिश सरकार पर भी हमें यह असर डालना है कि वे इस कमिटी के निर्माण को वैध न मानें और उसमें कोई व्यवहार न करें। अगर उन्होंने हमारी मांग को न माना तो हम मान कर दें कि उसके निर्णय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे। नचमुच यह एक अजीब बात है कि हमारे भाग्य का निर्णय राजा लोग और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि करने बैठे और उसमें हमारा कोई हाथ न हो। यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यही कमिटी निर्णय करने वाली है कि विधान परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जावेंगे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव न केवल जल्दी बल्कि सही तरीके से हो। और नंगो की मौजूदा सरकारों ने इसकी बहुत कम आशा है।

कि रियासतों के ये ग्रुप कहीं प्रतिगामी शक्तियों के गढ़ नहीं बन जावें। इसलिए छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में मिलाने के बजाय पड़ोस के प्रान्त में मिलाने पर ही हम अधिक जोर दें।

एक और बात है। कुछ नरेश जिनकी रियासतें स्वतंत्र ग्रुप बनने लायक बड़ी नहीं हैं अपने साथ दूसरी छोटी रियासतों को मिला कर उन पर अपनी छाप डालना चाहेंगे, छोटी रियासतों की जनता और उनके नरेशों को भी इस विषय में सावधान रहना होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि सच की इकाई के अन्दर कोई किसी पर अपना प्रभुत्व नहीं जतावे।

अब शासन का अन्तिम विधान बनाने का प्रश्न रह जाता है। जाहिर है कि—

(१) भारतीय संघ की समस्त इकाइयों में शासन का तरीका एकसा ही हो। प्रान्तों में एक तरह का और रियासतों में दूसरे प्रकार का शासन जरा भी बरदाश्त नहीं किया जा सकेगा।

(२) केन्द्रीय शासन में भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रान्तों के प्रतिनिधियों के समान भागीदार होंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि देश की मौजूदा अवस्था में नंगश —कम-से कम कुछ बड़े नरेश तो रहेंगे। और छोटे भी पेंशन के रूप में रहेंगे। बड़े नरेश अपने राज्यों में वैधानिक मुखिया के रूप में काम करेंगे। उनके अधिकार अत्यंत सीमित रहेंगे। सारे कानून धारा सभा के द्वारा बनेंगे और असल शासन धारा सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि-मण्डल के द्वारा ही होगा। छोटे नरेश शायद बारी बारी से साल साल दो दो साल के लिए अपने प्रान्तीय संघ के वैधानिक मुखिया रहेंगे। अभी नंगश मण्डल के भीतर और बाहर नरेशों के जो मशायिरे चल रहे हैं उनमें से तो भगसु

है। पार्लियामेंट राजा के खानगी खर्च की मद पर शासन की अन्य मदों की भांति प्रति वर्ष विचार नहीं करती। प्रत्येक राजा के शासन काल के प्रारम्भ में एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है और यह रकम—जब तक वह राजा राज्य करता है—प्रतिवर्ष उसे मिलती रहती है। इसमें फिर बीच में बार-बार जाँच या पुनर्विचार नहीं किया जाता। उस समय उसकी तमाम जरूरतों पर विचार कर लिया जाता है और तदनुसार उसमें फेर-बदल कर दिया जाता है। वस, इसके बाद जो रकम मंजूर हो जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। पर जो मंजूर होता है, शासन के दूसरे विभागों की भाँति बादशाह को भी उसकी मर्यादा में रहना पड़ता है। यह ख्याल करना भी गलत है कि इस प्रकार मंजूर हुई रकम का विनियोग करने में राजा फिर स्वतन्त्र है, और उसका ऑडिट वगैरा नहीं होता। ऑडिट हर साल होता है और प्रत्येक राजा के कार्य काल के अन्त में उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है और इसके प्रकाश में नये राजा के लिये बजट बनते हैं। यह भी ध्यान में रहे कि पार्लियामेंट से इंग्लैंड के राजा के खर्च के लिये जो रकम मंजूर होती है उसके अलावा उनके पास आय के अन्य कोई माधन नहीं होते। वेशक, कार्नवाल और लैक्सेटर की डचीज उसकी खानगी संपत्ति हैं, परन्तु इनका उपभोग वह नहीं करता। उसने यह संपत्ति राष्ट्र को अर्पित कर दी है और इंग्लैंड में यह परिपाटी है कि जब नया राजा सिंहासन पर आता है तब यह पार्लियामेंट को यह सदेश भेजता है कि “राजा की व्यक्तिगत जायदाद राष्ट्र को अर्पित है और वह अपने तथा अपने निर्वाह के लिये पूर्णतः पार्लियामेंट की उदारता पर निर्भर है।” स्मरण रहे कि राजा के लिये पार्लियामेंट से जो रकम मंजूर है उसमें तिगुनी आय इन जायदादों की है।^१

इंग्लैंड के राजा की सिविल लिस्ट सारे राष्ट्र के बजट के एक प्रतिशत का पन्द्रहवाँ हिस्सा है। पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें

विश्वास है नरेश समझदारी से काम लेंगे और इंग्लैंड के बादशाह की भाँति खुद ही अपने खर्च की रकमे कम कर लेंगे अथवा जनता को तो कम करनी ही होगी। पर असली सवाल है स्वराज्य के निर्माण का, हम उस पर विचार करें।

खैर, तो स्वराज्य की कुछ मोटी-मी सख्खे इस तरह धीरे धीरे बनती जा रही है। पर वह इतनी मोटी अस्थिर और अस्थायी है कि उसका अंतिम रूप क्या होगा यह कहना बहुत कठिन है। परन्तु जिस प्रकार हम अब तक आगे बढ़ते आये एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे भी इसी प्रकार मजबूती से कदम बढ़ाने हुए हमें जाना होगा। राष्ट्र निर्माता घटनाओं को उनके अपने प्रवाह पर नहीं छोड़ दिया करते। दूरदर्शिता के साथ सोच समझ कर चरमों पहले में अपने उद्देश्यों को कायम करते हैं और तदनुसार योजनाएँ बना कर दृढ़ता पूर्वक उन्हें पूरी करने में लग जाते हैं प्रवाह में वे बहते नहीं प्रवाह को मोड़ने की क्षमता रखते हैं।

अभी तक जो पू० महात्मजी के मार्गदर्शन में अपना गम्भीर नय किया है। उसके अनुसार कुछ मोटी मोटी बातें ये नय पार्श्व हैं—

- १ स्वराज्य अथवा उत्तरदायी शासन हम शान्त तरीकों से हासिल करेंगे।
- २ देश के दुम्हे दुम्हे नहीं होंगे। सभी जातियाँ हेलमेल में रहेंगी।
- ३ शासन का तरीका जनन्यात्मक होगा। सभी जनताएँ अहिंसा के आधार पर ही कायम हो सकना है।

जाहिर है जब तक संपूर्ण जनता अपने अधिकारों को अपने अधिकारियों की समझ कर के तदनुसार अपने कर्तव्यों के तत्पन में तथा साथ जायेंगी ऐसा अहिंसात्मक जनता नहीं आ सकता।

हमें जनता को अपने के लिए अहिंसा मार्ग पर बुझाना है जिससे कुछ किये जा सकना था हो सके है और इसी प्रकार अपने अधिकारों

रहेगा। पर हमें भीतर से भी इस प्रश्न को हल करने का अपना यत्न जारी रखना है उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा विचार कर लें।

सब से पहली बात तो यह है कि हमें इन तमाम परिवर्तनों के लिए जनता को भी तैयार करना है। इसलिए प्रत्येक रियासत में जन संगठनों का होना जरूरी है। अतः ऐसे जन संगठन जहाँ न हो वहाँ तुरन्त कायम किये जावे और जहाँ पहले से हो उनका विस्तार गांव गांव में फैला कर जनता में अपने अधिकारों और जिम्मेवारियों का भान पैदा कर देना चाहिए। आज भी ग्रामों की असंख्य जनता अज्ञान के घोर अंधकार में पड़ी है और उसके इस अज्ञान से अनुचित लाभ उठा कर छोटे मोटे व्यापारी, वकील, दूकानदार और सेठ-साहूकार उनका शोषण करते रहते हैं और सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उनको भय से आतंकित करते रहते हैं। हमें उनमें ऐसी जान डाल देनी है कि जिससे वे अन्याय के सामने मुँके नहीं और जुल्मों को कभी बरदाश्त नहीं करें। स्वतन्त्र और पुरुषार्थी देशों की जनता की सुख समृद्धि और पराक्रम की मिसालें दे कर उनके पुरुषार्थ और तेजस्विता को भी जगाना चाहिए और अच्छा और ऊँचा जीवन बिताने की प्रेरणा उनके अन्दर निर्माण करनी चाहिए। यह सब काम गांवों और कस्बों की मुकामी कमिटियों के जरिये हो सकता है। इन कमिटियों में कस्बे या गांव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्भय, त्यागी, और सूझ बूझ वाले नागरिक हों और वे जनता की रोजमर्रा की तकलीफों की तरफ ध्यान दे कर उन्हें दूर करने की कोशिश में रहें। जो केवल जनता की सुस्ती, अज्ञान, भीरुता से पैदा हुई हो उन्हें जनता द्वारा ही दूर करावें जिनमें सरकारी कर्मचारी कारण हों उन्हें इन कर्मचारियों को समझा कर दूर किया जाय और जिनको वे भी समझाने बुझाने पर दूर न करें उनके लिये जनता को लड़ने के लिए तैयार किया जाय। पर इतनी तैयारी एकदम नहीं होती। इसलिए कार्यकर्ताओं को

अधीर नहीं होना चाहिए। आम तौर पर जनता पहले यह चाहती है कि कार्यकर्ता इन तकलीफों को दूर करा दें और उसे कुछ नहीं करना पड़े। इसका कारण उसका स्वाभाविक भय और अज्ञान है इसलिए कार्यकर्ताओं को कुछ उठा कर भी जेल जा कर भी जनता की तकलीफें दूर करने का यत्न करना चाहिए। हमने अपने आप जनता की आत्मा भी धीरे धीरे जागती जाती है। कार्यकर्ताओं की कुशलता इसमें है कि वह जनता के सामने ऐसे कार्यक्रम रखते जायें कि जिससे वह अपने आप जनता की तेजस्विता और कार्य शक्ति का विकास होता जायें।

थोड़े से जनता के सामने हम यह लक्ष्य रखते कि वह अपने गाँव या कस्बे को एक छोटा-सा परिवार समझे और अपने परिवार की जरूरतें समझें कि जिन प्रकार उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा करने की चुनौती है उसी प्रकार हम अपने गाँवों को या राज्य को भी समझें और उसका पूरा शासन अपने हाथ में ले लेने के लिए जनता को समझावें। समाज की अनेक प्रकार से सेवा करनी होती है। इसी प्रकार उसकी अनेक जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों की पूर्ति और सेवा के विभिन्न मन्त्रों से बना कर प्रत्येक काम के लिए एक एक मन्त्र तैयार करना दी जाय। और वह सेवा में लग जायें।

प्राथमिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा, खेल क-
मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत और मन को प्रसन्न करने वाले तथा
ऊंचा उठाने वाले मकान के भीतर और मैदान में खेलने के तरह तरह के
खेलों की व्यवस्था बगैरा करने वाला भी एक महकमा हो सकता है ।

× बहुधन्धी सहकार समितियों की स्थापना द्वारा फसलों का माल तथा
बनी बनाई चीजें बेचने और जरूरत की बाहरी चीजें खरीदने की व्यवस्था
की जा सकती है जिससे कि ग्रामीणों को अपनी चीजों के अधिक से
अधिक दाम मिल जाय और बाहर की वस्तुयें किफायत से मिल सकें ।
बीच का मुनाफा उन्हें को मिल जाय । यह व्यापारी सहकारिता का एक
स्वतंत्र महकमा हो सकता है ।

ग्राम की रक्षा के लिए ग्रामीण जनता को बलवान और बहादुर
बनाना, स्वयं सेवक दलों का संगठन करना चोरो डाकुओं और बदमाशों
से गाँव की रक्षा करना और उन्हे जातीय दंगों से दूर रखना बगैरा काम
भी अत्यन्त महत्व पूर्ण है । यह काम भी एक कमिटी के सिपुर्द किया जा
सकता है ।

फिर, अपने अपने गाँव के भीतर यह सब करते हुए हमें अलग अलग
गाँवों के अन्दर पारस्परिक सम्बन्ध स्थापन करते हुए परगने (तहसील) और
जिल्लों के व्यवस्थित संगठन बना लेने चाहिएँ जिसमें सारा राज्य या सारा
देश एक सजीव शरीर की भाँति चैतन्यमय और क्रियाशील संगठन बन
जाय ।

मतलब यह कि हमें ठेठ नीचे से सम्पूर्ण स्वराज्य की रचना मजबूत
पाये पर करनी है । राजनैतिक मत्ता हमारे हाथ में लेने के लिए तथा उसके
हाथ में आ जाने के बाद भी यह काम तो करना ही होगा । क्योंकि यही
चीज है जिसके लिये स्वराज्य की जरूरत भी है । किन्तु इस असली अर्थात्

रचनात्मक कार्य की तरफ अब तक ठीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है । वह अगर जावे और हम उसमें सच्चे दिल से लग जायें तो अपने आर-
श्वराज्य का निर्माण हो जावे ।

लोक संगठनों को अपने राजनैतिक प्रचारात्मक काम के साथ साथ इन कामों को भी अपने हाथ में अवश्य लेना चाहिए । इस वास्तविक सेवात्मक संगठनात्मक, आर्थिक निर्माण करने वाले, जान बूझकर, नास्तुतिक उत्थान के और समाज को शुद्ध और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लोक-संगठन जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अधिक सकल और प्रभाव-शाली होगा । शामन पर भी उसका उतना ही अधिक असर होगा । केवल अखबारी प्रचार और भाषणों में लगे रहने वाले संगठनों के कानून भंग की लड़ाइयों में भी वह बल नहीं होगा । जो हमकी एक निठी में होगा । इसलिये इस वास्तविक सेवाजनित बल की उपासना में हम लग जायें । यही नकलता की चाबी है ।



पारिशिष्ट (१)

सन्धि वाली चालीस रियासतें (ट्रीटी स्टेट्स)

जिन रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार की संधियाँ हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं .—

रियासत का नाम	संधिका वर्ष
१ अलवर	१८०३
२ बहावलपुर	१८३८
३ बांसवाड़ा	१८३८
४ बड़ौदा	१८०५
५ भरतपुर	१८०५
६ भोपाल	१८१८
७ बीकानेर	१८१८
८ बूंदी	१८१८
९ कोचीन	१८०७
१० कच्छ	१८१७
११ दतिया	१८१८
१२ देवास (दोनों)	१८१८
१३ धार	१८१७
१४ धौलपुर	१८०६
१५ ग्वालियर	१८०४, १८४४
१६ हैदराबाद	१८००, १८५३
१७ इन्दौर	१८१८
१८ जयपुर	१८१८

रियासत का नाम

संधि का वर्ष

१६ जेसलमीर	१८१८
१७ जम्मू काश्मीर	१८४६
२१ भालावाड	१८३८
२२ जोधपुर	१८१८
२३ कलात	१८७६
२४ करौली	१८१७
२५ लैंगपुर	१८३८
२६ किशनगढ़	१८१८
२७ कोल्हापुर	१८१२
२८ कोटा	१८१७
२९ मैसूर	१८८१, १९१३
३० श्रीगङ्गा	१८१२
३१ प्रतापगढ़	१८१८
३२ रामपुर	१७६४
३३ रीवा	१८१२
३४ समथर	१८१७
३५ नावल वाडी	१८१६
३६ सिद्धिम	१८१४
३७ मिर्जापुर	१८२३
३८ नागपुर	१८०५
३९ टोंक	१८१७
४० उदयपुर	१८१८

(इण्डियन स्टेट्स एण्ड प्रिन्सिपलिटीज)

श्री मुन्मुक्क निरुपमिनी

परिशिष्ट (२)

छः प्रमुख रियासतें

जो स्वतन्त्र यूनिट के रूप में रह सकती हैं ।

	रकबा	आबादी	आय
हदराबाद	८२६६८	१६३३८५३४	१५८२ लाख (४५)
मैसोर	२६४८३	७३२८८६६	६३८ ,, (४२-४३)
बड़ौदा	८१७६	२८५५०००	३६३
गवालियर	२६३६७	४००००००	X -
नावणकोर	७६६१	६०७००१८	X -
जम्मू-काश्मीर	८४४७१	४०२१६१६	३२० (४२-४३)



परिशिष्ट (३)

निम्न लिखित रियासतों में किसी न किसी प्रकार की धारा
सभाएं हैं—

- १ मैसूर
- २ त्रावनकोर
- ३ बडोदा
- ४ जयपुर
- ५ बीकानेर
- ६ काश्मीर
- ७ हैदराबाद
- ८ कोचीन
- ९ इन्दौर
- १० भोपाल
- ११ जोधपुर
- १२ उदयपुर
- १३ गयासपुर
- १४ अजमेर
- १५ कोल्हापुर
- १६ रामपुर
- १७ भोर
- १८ सगुन्ना
- १९ सीता
- २० भावनगर
- २१ नागौर

- २२ देवास जूनियर
- २३ पुडु कोटाई
- २४ भावलपुर
- २५ पोरबन्दर
- २६ मडी
- २७ फलटन
- २८ कूचबिहार
- २९ जामखडी
- ३० कपूरथला
- ३१ बून्दी



नाम रियासत	रकबा	आवादी
१२ भिलोदिया	६	२५५८
१३ बिहोरा	१	२६६
१४ बिलवारी	१	२९
१५ खम्भात	३६२	८७७६१
१६ छालियर	११	२६४६
१७ छोटा उदेपुर	८६०	१४४६६०
१८ चिचली गादेद	२७	१३०५
१९ छोरगला	१६	२७१५
२० छुदेसर	२	६४४
२१ धरनावती	७६	४३४३
२२ धमासिया (वनमाला)	१०	२३७६
२३ धरमपुर	७०४	११२०३१
२४ धारी	३	१४५४
२५ दोदका	३	१४४६
२६ दुधपूर	१	१२६
२७ गाधवोरीयद	१२८	११२६३
२८ गाडवी	१७०	७७६७
२९ गोठारडी	३	४३०
३० गोथडा	४	११५६
३१ इतवाद	६	१५६६
३२ जभुघोडा	१४३	११३८५
३३ जावहर	३०८	५०३६१
३४ जेसार	१	५११
३५ झारी घरखाडी	८	५०३
३६ जिरल कमसोली	५	३०३३
३७ जुमरा	१	३०३

नाम रियासत	रकबा	आवादी
३८ कदाना	१३२	१७५६०
३९ कानोदा	३	१३८७
४० कासला पागिनु मुवाडा	१	१३३
४१ किरली	२१	१२५८
४२ लुनावाडा	६८८	६५१६२
४३ मडिवा	१६	५५६५
४४ मेवली	५	१७०२
४५ मोका पागिनु मुवाडा	१	२०७
४६ नाहरा	३	४५३
४७ नालिया	१	१७६
४८ नानगाम	३	६२५
४९ नासवाडी	१६	६५५६
५० पालामनी	१२	२७५८
५१ पलास बिहिर	२	२३६
५२ पान तलावही	५	६३५
५३ पद्	६	२३४१
५४ पिपलादेवी	३	१२५
५५ पिपरी	७२	३३६३
५६ पीचा	३	१०१८
५७ राइरा	३	५५४
५८ राजनिगा	१५१७	२ ६०८६
५९ राजपुर	१	१६५
६० रामपुरा	४	१६८२
६१ रेगन	४	५८७
६२ रानिन	४६	६०१०७

नाम रियासत	रकबा	आबादी
६३ सजेली	३४	८०८३
६४ सत	३६४	८३५३८
६५ शानोर	११	१८४०
६६ शिववारा	४	४६६
६७ सिहोरा	१५	४५३२
६८ सिधियापुरा	४	६६७
६९ सुरगाना	३६४	१५२३५
७० उचाद	८	३३६२
७१ उमेटा	२४	५६२२
७२ वध्यावन	५	१४७
७३ वाजिरिया	२१	५६६८
७४ वखतापुर	१	३६०
७५ वरनोलमल	३	६८४
७६ वरनोल नानी	१	८७
७७ वरनोल मोटी	२	३६२
७८ वासन सेवाष्टा	१२	१६०६
७९ वासन विरपुर	१२	४१७१
८० वसुरना	१३२	७३०८
८१ विरमपुरा	१	१०७
८२ वोरा	५	१६०७

राजपूताना एजेन्सी

८३ अलवर	११५८	१६७५१
८४ वासवाडा	१६०६	२२५१०६
८५ वृदी	२२२०	२१६७२०
८६ दा ला	३४७	६३१७०

नाम रियासत

रकबा

आबादी

८७ बोनपुर

११७३

२५,१८६

८८ बोनपुर

१,६०

२,७२१४

८९ बैलु

१५५६०

२६३१,७७५

९० बैलुमेर

१६०६१

७६२५५

९१ भागलपुर

८२३

१,०८,८२०

९२ बोनपुर (मोहर)

३६०११

२,१२,५३८२

९३ बोनपुर

१२२८

१,०५,०५५

९४ बोनपुर

४७५५

६,८८,८०४

९५ बोनपुर

३१०

२,५५,६११

९६ बोनपुर

१०६६

१६,११,४६

९७ बोनपुर

८८३

१,८८,८३३

९८ बोनपुर

४०५

७४,०१६

१०० बोनपुर

१६६४

१,८८,६८८

१०१ बोनपुर (मोहर)

२५५३

३,०३,६०

१०२ भागलपुर

१०६०३

१,५६,६६१०

१०३ भागलपुर

१६०६

२,५०,०६

१०४ भागलपुर

२,००,००

६,३०,००८

१०५ भागलपुर

८८८

८,३०,००८

२०

८,३०,००८

मिनिम बजे नी

१०६ मिनिम

२,००,००

१,००,०००

मिनिम बजे नी

१०७ भागलपुर

१,६०,००

१,००,०००

१०८ भागलपुर

१,६०,००

१,००,०००

मोम रियासत

	रकबा	आबादी
१०६ फरीदकोट	६६८	१६४३६४
११० भिंद	१२६६	६२४६७६
१११ कपुरथला	५६६	३१६७५७
११२ खैरपुर	६०५०	२२७१८३
११३ लुहारू	२२६	२३३३८
११४ मालेरकोटला	१६५	८३०७३
११५ मडी	११३६	२०७४६५
११६ नाभा	६४७	२८७५७४
११७ पटौडी	५३	१६५७३
११८ पटियाला	५६४२	५६६६९४
११९ सुकेत	३६२	५८१०८

मैमोर पजेन्सी

१२० मैमोर

२६४७५ ६५५०३१२

मदगास स्टेटस् पजेन्सी

१२१ बगनापल्ली	१७५	१२०३६
१२२ कोचीन	१११७	१००५०१६
१२३ पुदुकोट्टी	११०६	१००६६१
१२४ सतुर	१६०	१३५८३
१२५ त्रावनकोर	७६२५	५०६५६७३

पंजाब हिल स्टेटस् पजेन्सी

१२६ बागल	१००	२६३५०
१२७ बागट	३३	६८६१२

नामरियासत	रकबा	आबादी
१२८ बालामन	५७	६८६४
१३६ शाह ईर	३४३६	१००१६२
१३० भज्जी	६४	१५४१३
१३१ विलामपुर (कोह्लू)	४५३	१००६६४
१३२ डरकोटी	५	५३१
१३३ घामी	२८	५२३२
१३४ नलमिया	१६२	५६८१८
१३५ केओन्थाल	१८६	६५५६०
१३६ कुमारमेन	८४	१२७८१
१३७ कुर्गीहर	७	२०६१
१३८ कुथर	२१	३७६०
१३९ मेहलोग	४६	८१५५
१४० मंगल	१४	१२४८
१४१ मन्तगढ़ (हिंदुर)	२७६	५००१५
१४२ मिरसुर (गान)	१०४६	१४८५६८
१४३ भारोन	८६	१५६८
१४४ बिजा	५	६६४
१४५ तुमन	२७४	२६००१
१४६ मेगरी	३३	३१६७
१४७ डेरी (गहवाल)	१५००	५७०००६

मार्थ वेस्ट फ्रांटियर पञ्चमी

१४८ ला	२०५	३६०००
१४९ निगान	४०००	८००००
१५० डि	३०००	२५००००
१५१ पल्ला	३६	१०३४

नाम रियामत	रकबा	आवादी
१५२ स्वाट	१८००	२१६०००

काश्मीर एजन्सी

१५३ जम्मु और काश्मीर	८५८८५	३६४६२४३
१५४ नागीर	१२४५	१३६७२
१५५ हुंजा	६८४८	१३२४१

हैदराबाद रेसीडेन्सी

१५६ हैदराबाद	८२६६८	१४४३६१४८
--------------	-------	----------

ग्वालियर रेसीडेन्सी

१५७ बनारस	८७५	३६११६५
१५८ ग्वालियर	२६३८७	३५२३०७०
१५९ खनियाधाना	६८	१७६७०
१६० रामपुर	८६२	४६४६१६

बलूचिस्तान एजन्सी

१६१ कलात	७३२७८	३४२१०१
१६२ लासबेला	७१३२	६३००८

भूटान रेसीडेन्सी

१६३ भूटान	१८०००	३०००००
-----------	-------	--------

सेन्ट्रल इंडिया एजन्सी

१६४ गजयगढ	८०२	८५८३५
-----------	-----	-------

नाम रियासत	रकबा	आबादी
१६५ अलीपुरा	७२	१५३१६
१६६ अलिराजपुर	८३६	१०१६६३
१६७ बकापथरी	५	१३१६
१६८ बावनी	१२१	१६१३२
१६९ बरौंधा	२१८	१६०७१
१७० बड़वानी	११७८	१४१११०
१७१ बैरी	३२	४२६६
१७२ भैसांदा	३२	४२६७
१७३ भोपाल	६६२४	७२६६५५
१७४ बिहट	१६	४५६५
१७५ बिजावर	६७३	११५८५२
१७६ बिजना	८	१५६७
१७७ छतरपुर	११३०	१६१२६७
१७८ चरलारी	८८०	१२०३५१
१७९ दतिया	६१२	२५८८३४
१८० देवास (सानियर)	४४६	८३३२१
१८१ देवास (जूनियर)	४१६	७०५१३
१८२ धार	१८००	२४३५२१
१८३ धुरवाई	१५	२०३०
१८४ गंगोली	३६	४६६५
१८५ गोरीगढ़	७१	६७१३
१८६ इन्दौर	६६०२	१३०३१८६
१८७ जावगा	६००	१००१६६
१८८ जमो	७०	७८०३
१८९ मन्डुआ	१३३६	१६५५०२
१९० मिमनी	१८	२६५०

नाम रियासत	रकबा	आवादी
१६१ जोबट	१३१	२०१५२
१६२ कामता राजुला	१३	१११४
१६३ कठियावाडा	७०	६०६६
१६४ खिलचीपुर	२७३	४५५८३
१६५ कोठी	१६६	२१४२४
१६६ कुरवाई	१४२	२२०७६
१६७ लुगासी	४५	६१६२
१६८ मैहर	४०७	६८६६१
१६९ मकडाई	१५५	१५५१६
२०० मथवार	१२६	२८६७
२०१ महमूदगढ	२६	२६५८
२०२ नागोद (उचेरा)	५०१	७४५८६
२०३ नैगवा रेवाइ	१२	२३५२
२०४ नरसिंहगढ	७३४	११३८७३
२०५ ओरछा	२०८०	३१४६६१
२०६ पाहरा (चौबेपुर)	२७	३४६६
२०७ पालदेव (नया गाँव)	५३	८१५७
२०८ पन्ना	२५६६	२१२२३०
२०९ पठारी	३०	२१४०
२१० पिपलोदा	७२	६६२७
२११ राजगढ	६६२	१३८६१
२१२ रतनमाल	३२	२१८३
२१३ रतलाम	६६३	१०७३२१
२१४ रीवा	१३०००	१५८७१५५
२१५ समार	१७८	३३३०७
२१६ सरीला	३५	६०२२

नाम रियासत	रकबा	आबादी
२१७ भीतामऊ	२६२	२८४०२
२१८ सोहावल	२५७	४२१६२
२१९ तारोन (पायरोडी)	१६	३३८७
२२० मैलाना	२६७	३५२२३
२२१ डोरी पतहपुर	३६	५५६७

डेकन स्टेट पन्ड कोल्हापुर रेसिडेन्सी

२२२ अक्कलकोट	४६८	६२६०५
२२३ श्रीध	५०४	७६५०७
२२४ भोर	६१०	१४१३४६
२२५ जमखिडी	५२४	११४२८२
२२६ जंजीग	३७६	११०३८८
२२७ जन	६८०	६११०१
२२८ कोल्हापुर	३०१७	६५७१३७
२२९ कुरंदवाड (भीनियर)	१८२	४४२०१
२३० " (जूनियर)	११६	३६५८३
२३१ मिरज (भीनियर)	३१०	६३५५७
२३२ " (जूनियर)	१६६	४०६८६
२३३ मुघोल	३६८	६२८१०
२३४ पगटन	३६७	५८७११
२३५ राम दुर्ग	१६६	२५१०१
२३६ स मल्ली	११३८	२१८११८
२३७ सावटुर	७३	२०३२०
२३८ सावतगाडी	६३०	२०५८६
२३९ ताडी (रंगोटी)	१२	१७१

नाम रियासत	रकबा	आनादी
ईस्टर्न स्टेट एजन्सी		
२४० अयगढ	१६८	४०१४८
२४१ अथमल्लिक	७३०	६४२७६
२४२ बामरा	१६८८	१५१०५६
२४३ बाराकवा	१५४	४६६८६
२४४ बसतर	१३०६२-	५२४७२१
२४५ बाँध	१२६४	१३५२४८
२४६ बोनाई	१२६६	२१६७२२
२४७ चगभाकर	६०६	२३३२२
२४८ छुनिवादन	१५५	३१६६८
२४९ कूचविहार	१३१८	५६०८६६
२५० हसपल्ला	५६८	४२६५०
२५१ धेकनल	१४६५	२८४३२८
२५२ गंगापुर	२४६२	३५६३८८
२५३ हिडोल	६८४८	१३२४१
२५४ जासपुर	१६६३	१६३६६८
२५५ कालाहाडी (करौद)	३७४५	५१३७१६
२५६ ककैर	१४३१-	१३६१०१
२५७ कवरधा	७६८	७२८२०
२५८ केजहर	३०६६	४६०६१७
२५९ खैरागढ	६३१	१५७१००
२६० गाँडारा	२१४	७७६३०
२६१ खरमोवन	१५३	४३११०
२६२ कोरिया	१६३१	६०८८६
२६३ मयूरभंज	१२४३	८८६६०३

नाम रियासत	रकबा	आबादी
२६४ नादगोव	८७१	१८२३८०
२६५ नरसिंगपुर	१६६	४०८८२
२६६ नवागढ़	५६०	१४२३६६
२६७ नीलगिरि	२८४	६८५६८
२६८ पाललद्वारा	४५२	२७६७५
२६९ पाटना	२३६६	५६६६२४
२७० रायगढ़	१४८६	२७७५६०
२७१ रायराखार्ड	८३३	३५७१०
२७२ रानपुर	२०३	४७७१३
२७३ मरनी	१३८	४८०८६
२७४ सागनगढ़	५४०	१२८६६७
२७५ सैरगढ़	११६	१३८६७१
२७६ सोनपुर	६०६	२३७६१५
२७७ सुग्गुजा	६५५	५०१६३६
२७८ ताला	३६६	६६७०२
२७९ टिगरीया	४६	२१६८०
२८० तिरुग	४११६	३८२५०
२८१ उदपुर	१०५५	६७७३८

आमाम स्टेट्स

२८२ भारत	..	७१७
२८३ मीरिस	..	१०५५८
२८४ तालीन	..	१०१०
२८५ म. म. म.	..	१४ ०३
२८६ म. म. म. म. म.	...	१३३
२८७ म. म. म. म. म.	८६३८	१०५५ ६

नाम	रियासत	रकबा	आवादी
२८८	मारीएव	...	३१६२
२८९	मावैग	..	३२१८
२९०	मावसेनराम	...	२००७
२९१	मायलिम	...	२०८६५
२९२	नोबोसोह फोह	...	२५४६
२९३	नगस्पग	..	३६५३
२९४	नंगस्टग	...	११४५७
२९५	राम ब्राई	२६८५
२९६	नाम रव्लाव	..	१४२७३
२९७	छैरा	६७३८

बरमा स्टेट्स

२९८	कोतारावाडी	...	
२९९	कैवोगई	७००	१४२८२
३००	वावेलेक	५६५	१३८०२

वेस्टर्न इण्डिया स्टेट एजन्सी

(रकबा वर्गमील मे है । और आवादी सन १९३१ की गणना के अनुसार है ।)

३०१	अकादिया	२	१६३
३०२	अलामपुर (दीवानी)	३	५००
३०३	अलिदा	२५	२६५४
३०४	अबलियरा	८०	१०१७८
३०५	अमरापुर	८	१७७१
३०६	आनन्दपुर	१३	६२४
३०७	आनंदपुर	२५	२५२६

नाम	श्रियासन	रकवा	ग्रावादी
३०८	आनन्दपुर	७०	३७६८
३०९	अनके बालिया	१७	२२३६
३१०	बात्रा	१०	८२४२
३११	बागानग (मज्जम्)	२५	६५०
३१२	,, (न०१)
३१३	,, (न०२)
३१४	बजाना
३१५	बामन बोर	१२	८१२
३१६	बनटवा (मज्जम्)	२७	१५६१३
३१७	,, (तालूका)	५६	७८३८
३१८	बरवाला	४५	८८५५
३१९	भादली	१५	४११२
३२०	भटगना	१५	११०६
३२१	भावटा	७	१४०१
३२२	भलावा	६	३०६
३२३	भलमन भादली	३	...
३२४	भालगावडा	१६	१६०३
३२५	भटगिया	३	
३२६	भालिगा	२	२१८
३२७	भाभन	४	४६५
३२८	भाभनग	२६६१	५००२७१
३२९	भिमोना	२६	१११६
३३०	भोरा (गन)	३०	३३१५
३३१	भोरा	१	
३३२	भोरा	१	३१
३३३	भोरा	१	१८१

गाम रियासत

रकबा

आबादी

३३४	बिलखा	१०७	२०५८६
३३५	बोडानोनेस	१	२०५
३३६	बोलुन्द्रा	६	१०७८
३३७	छलाला	५	६५०
३३८	छनचाना	६	३४०
३३९	छमरडी (बचानी)	७	१८६१
३४०	छम्पराज (जासा)	५९	६११२
३४१	चरखा	१०	११३४
३४२	चिरोडा -	१	३६७
३४३	चितराव (दिवानी)	१	२७८
३४४	चौबारी	१३	४७२
३४५	चौक	४	१६३३
३४६	चोटीली	१०८	८९३४
३४७	चुडा	१०८	८९३४
३४८	चुडा सोराथ.	१४	१९१०
३४९	कछ	८२४९	५१४३०७
३५०	दाभा	१२	१७७४
३५१	ददालिया	२८	४०६२
३५२	दहिदा	२	९८७
३५३	दारोड	४	२६९
३५४	दसडा	१२९	९८८५
३५५	दाथा	६८	१३१४८
३५६	देदन (मजमू)	२५	४०११
३५७	देदन	२४	१७७८
३५८	देदरदा	२	७१७

१३८

रियासतों का सवाल

नाम रियासत

रकबा

आबादी

३५६	देदगडा		
३६०	दिलोली	१	
३६१	देवदर	२	
३६२	.. (यना)	—	४८४५
३६३	देरडी जानवाई	—	४४५५
३६४	देरोल	२	६८६
३६५	दिवालिया	१०	—
३६६	धोला (दिवानी)	११	८३७
३६७	धोलखा	१	२६५
३६८	धगणा	४ -	४००
३६९	अगडा	४४	६७३८
३७०	अोन	११६७	८८६६१
३७१	धुदराल	८८२	२७६३६
३७२	इमाल बज्जु	१२	२६३६
३७३	गावट	७	११०६
३७४	गभाली	१०	११३६
३७५	गभीना	५	१६६१
३७६	गदवा	११	६७१
३७७	गधूला	२३	२३६२
३७८	गधीना	१	३३
३७९	गग्गली (मोटी)	१	२२६
३८०	गग्गली (नानी)	१	३८४
३८१	गग्गिडाड	२	२३६
३८२	गग्ग		२२११६
३८३	गग्ग		६५१

नाम रियासत	रकबा	आवादी
३८४ गिगासरन	६	७०३
३८५ गोडल	१०२४	२०५८४६
३८६ घुनडियाला	१५	१८२५
३८७ हडला	२४	५६१५
३८८ हडोल	२७	—
३८९ हलारिया	६	१००८
३९० हापा	२	—
३९१ हरसुपुर (स्टेट)	७	४८८६७
३९२ इवेज	७	१३५०
३९३ ईडर	१६६६	२६२६६०
३९४ इजपुरा	२	—
३९५ इलोल्	१६	४६६२
३९६ इटारिया	६	१०५०
३९७ जाफराबाद (जजीरा)	५३	१२०८३
३९८ जाखान	३	४६८
३९९ जलिया (दिवानी)	३६८६	३१३३
४०० „ (वायाजी)	२	५००
४०१ „ (मानाजी)	६	२०३
४०२ जसदन	२६६	२८०३६
४०३ जेतपुर-भायावटार	११	११०६
४०४ „ सनाला	७	६८९
४०५ भामर	४	५६१
४०६ भमवा (विलानी)	४	६०६
४०७ भामराहद	४	५०६
४०८ भिन्नुवाडा	१६४	३१,५८३

नाम रियासत	रकबा	आयादी
४०६ जूनागढ़	३,३३७	५४५,१५२
४१० जूनापट्टार	०	२२४
४११ कडोली	८	—
४१२ कमादिया	४	७२३
४१३ कमालपुर	४	६३२
४१४ कानेर	२	२६६
४१५ कनजाल	१	२५१
४१६ कंकासियाली	७६	२३३
४१७ कनपुर (इस्वारिया)	३	१४४४
४१८ कनधारिया	१४	१७५२
४१९ करियाना	१०	३०६४
४२० कर्मद	३	१८४
४२१ करोल	११	१०८५
४२२ कच्छलपुग	१	—
४२३ कटोदिया (घनानी)	१	३८१
४२४ कथरोटा	१	२३८
४२५ कटोहन (थाना)	१०	५८०३
४२६ केसरिया	३	३३४
४२७ ग्यादन	८	२५०५
४२८ गभावा	६	१११७
४२९ गजनाद	१०	६८३
४३० गरिया	५	५६०
४३१ गरी दामना	३०	४००४
४३२ गिरा बड़ा	३०	—
४३३ गिरादी	११	१६८७

नाम रियासत	रकबा	आवादी
४३४ खिजडिया	—	२४३४
४३५ „ (वावरा थाना)	२	३२६
४३६ खिजडिया डोसाजी (सोंगद थाना)	१	२५४
४३७ खिजडिया नयानी (लखापादर थाना)	१	१३३
४३८ खिरासरा	४७	४६६३
४३९ कोटडा नयानी	३	१२४२
४४० „ पिथा	२५	७०७०
४४१ „ संगानी	६०	१०४२०
४४२ कोथारिया	२७	२४०७
४४३ कुवा	३	३१४
४४४ लखापदर	५	५७०
४४५ लखतर (लखतर थाना)	२४७	२३७५४
४४६ ललियाद	४	६३०
४४७ लाथी	४१	६३००८
४४८ लिखी	६	—
४४९ लिम्बडा	७	१७६५
४५० लिबडी	३४४	४०६८८
४५१ लोधिका (मजमू)	८	१७३२
४५२ „ (मुलवाजी)	७	२५७६
४५३ „ (विजयसिंगजी)	७	२४४८
४५४ मागोडी	२३	३२३८
४५५ मागुना	५	—
४५६ महुवानाना	७६	३५६
४५७ मलिया	१०३	१२१४२
४५८ मालपुर	६७	१३४४०

नाम रियासत	रकबा	आबादी
४५६ मववाटर (वनटवा)	१०१	२६०८४
४६० मनाववा	५	४८५
४६१ मानपूर	११	६६१
४६२ मनसा	२५	१६६४२
४६३ मवाटिवा	६	४७०
४६४ मायापटर	१४	११३२
४६५ मेहमदपुरा	१	—
४६६ मेनगानी	३४	३६४२
४६७ मेवासा	२४	६४५
४६८ मोहनपुर	८६	१४२६१
४६९ मोनवेल	३१	२७५४
४७० मोरछोयना	१	४८३
४७१ मोरवी	८२२	११३०२३
४७२ मोटाकोथामना	३	—
४७३ मुली	१३३	१७१०६
४७४ मुनीलादेरी	१५	३०३४
४७५ मुंजपुर	३	४८६
४७६ नाटाला	१२	६१६
४७७ नटनगगा	१४	१२०१
४७८ नरानगा	३७६१	४०२१६२
४७९ नरानिवा	२३	३६७२
४८० निगताला	२	४४४
४८१ नोपनगगा	१	१३१
४८२ नोपगाम (गिरानी)	—	३२२६
४८३ नर	१	२३०

नाम रियासत	रकबा	आवादी
४८४ पालज	२	—
४८५ पलाली	४	६२४
४८६ पाल	२१	३४६६
४८७ पालियद	८५	८७५८
४८८ पालिताना	३००	६२१५०
४८९ पन्थवदा (बल्लानी)	१	४२०
४९० पटडी	१६५	१६५७३
४९१ पेठापुर	११	५३७६
४९२ पिपलिया	३०	१२६०
४९३ पिठाडिया जोतपुर	१०२	७८१३
४९४ पोर बदर	६४२	११५७७३
४९५ प्रेमपुर	२५	—
४९६ पुन्दरा	११	२३३०
४९७ राधनपुर	११५०	७०५३०
४९८ रायसाक्ली	६	६३६
४९९ राजकोट	२८२	७५५४०
५०० राजभारा (चौकथाना)	१	६०४
५०१ राजपुर	२२	२११८
५०२ राजपुर (हलार)	१५	२६६१
५०३ रामनका	२	४८४
५०४ रामास	६	१६१४
५०५ रामपडदा	५	६२४
५०६ रामपुरा	१	—
५०७ रानासन	३०	४८११
५०८ राधिया	३	८३८

नाम रियासत	रकबा	आबादी
५०६ रानीगाम	३	८६३
५१० रानीपुरा	१	—
५११ रत्नपुरदा (चौकथाना)	५	५६१
५१२ रतनपुर धमानका	३	६०२
५१३ रोही सारा	१	५७२
५१४ रुपाल	१६	४५१५
५१५ साहूका	६	७८५
५१६ सामाधियाला (चौकथाना)	१	६१०
५१७ सामाधियाला	१	२०६
५१८ मामा (छुभादिया)	१	१२०६
५१९ समला	१३	१११२
५२० सनाला	३	५५०
५२१ सनोसरा	१३	१०२२
५२२ सेंतालपुर (थाना)		४१३
५२३ सरदारगढ	३६	५०७५
५२४ सलनौनेम	३	२६६
५२५ सयम्बा	१८	१६३१
५२६ सानासना	२५	०
५२७ सनडाग गावडी	१३	१५०३
५२८ सायला	२२२	१५२८१
५२९ सैजरागर	२६	११०३
५३० सैतडीतडाग	१	३५१
५३१ शहापुर	१०	१५०१
५३२ शिवाग	१	२६७
५३३ शिवाग नाइली	१	१७०८

नाम रियासत	रकबा	आबादी
५३४ सोगढ (बछानी)	१	१५६३
५३५ सुदामडा ढढलपुर	१३५	७७४२
५३६ सुदासना	३२	८६२५
५३७ सुइगम	२२०	५८४०८
५३८ लाजपुरी	७	—
५३९ ललसाना	४३	२४७२
५४० तावी	१२	७७५
५४१ तेजपुरा	४	—
५४२ तेरवाडा	६१	५७३६
५४३ थाना देवली	११७	१६०५
५४४ थाराङ	१२६०	५४३११
५४५ थारा	७८	१०६४१
५४६ टिवा	३	—
५४७ टोडाबछानी	१	६३५
५४८ उमरी	१०	—
५४९ उँटडी	६	४४३
५५० वडल भण्डारिया	१	४५८
५५१ वडाली	२	७५६
५५२ वाडिया	६०	१३७१६
५५३ वडोद (भालावाद)	११	१४१८
५५४ वडोद (दिवानी)	—	६३२
५५५ वाघावडी (वाघवोरी)	३	१०७
५५६ वखतापुर	४	—
५५७ वला	१६०	१४०६६
५५८ वलासना	२१	३६७१

नाम रियासत	रकबा	आबादी
५५६ बाना	२४	३०८६
५६० बनाला	३	३८८
५६१ बनगध्रा	(३)	३०६
५६२ बनोद	५७	४६७६
५६३ बरसोदा	११	४०२३
५६४ बसासठ मजमू	१६	६२३६
५६५ बावटीघरवाला	४	१५२१
५६६ बावटी बहानी	१	२७७
५६७ बिल्यानोनेस	—	२०६
५६८ बेसारीया	३	६५३
५६९ बिछावद	३	४३१
५७० बिलयानगर	१३५	८१६१
५७१ बिरपुर	६६	८०५०
५७२ बिरसोदा	३	—
५७३ बिरवा	३	११६
५७४ बिठलगढ़	५६	४०७३
५७५ बड़गवि	२८	३६२८
५७६ बटवान	२४२	४२६०६
५७७ ब'क'नेर	४१७	४१३५६
५७८ बाग	६५६	२०७३१
५७९ बागही (१)	१००	३६००
५८० " (२)	८०	१८११
५८१ बासना	३०	३६०७
५८२ बसरादा (मार्जी स्टेट)	३६	४७१
५८३ बैनबाद	३०	३८१६

परिशिष्ट ५

रियासतों का वर्गीकरण

१. जन संख्या के अनुसार—

जिनकी आबादी १ करोड़ से ऊपर है—

५० लाख से ऊपर किन्तु १ करोड़ से कम है—

१०	५० लाख	१
५	१०	१
४	५	१
३	४	१
२	३	२
१	२	३६
१० हजार	१	१२६
१	१० हजार	१६
१ सौ	१	१३
	१ सौ	३

जिनकी आबादी का ठीक-ठीक पता नहीं—

२०

५८१

२. आय के अनुसार—

जिनकी आय एक करोड़ से ऊपर है—

५० लाख से ऊपर किन्तु एक करोड़ से कम है—	६
२५ " ५० लाख " "	१३
१० " २५ " "	३०
५ " १० " "	३८

जिनकी आय ५० लाख में ऊपर मिल्तु एक जगोह में कर है—

॥	४	॥	५	॥	१५
॥	३	॥	४	॥	२४
॥	२	॥	३	॥	२४
॥	१	॥	२	॥	११
॥	१० हजार	॥	१	॥	१३
॥	४०	॥	५० हजार	॥	१५
॥	३०	॥	४०	॥	३४
॥	२०	॥	३०	॥	३६
॥	१०	॥	२०	॥	३३
॥	१	॥	१००	॥	१५२
॥		॥	१००	॥	१८
॥	अभाव				०

५८४

३. रकबे के अनुसार—

जिनका रकबा	५० हजार वर्गमील में ऊपर है—	३
॥	२० ॥ ॥ मिल्तु ५० हजार वर्गमील में ऊपर	३
॥	१० ॥ ॥ २० ॥ ॥	३
॥	१ ॥ ॥ १० ॥ ॥	२६
॥	१ ॥ ॥ १ ॥ ॥	१११
॥	१ ॥ ॥ १ ॥ ॥	१६८
॥	५० ॥ ॥ ५० ॥ ॥	५०
॥	५० ॥ ॥ ५० ॥ ॥	५०
॥	५० ॥ ॥ ५० ॥ ॥	५०
॥	५० ॥ ॥ ५० ॥ ॥	५०
॥	५० ॥ ॥ ५० ॥ ॥	५०

५८४

परिशिष्ट (६)

लोक-परिषद्

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् के
अधिवेशनों के सभापति

नाम	सन्	स्थान
(१) दीवान बहादुर श्री रामचन्द्र राव.	१९२७	बम्बई
(२) श्री सी. वाई चिन्तामणि	—	—
(३) श्री रामानन्द चटर्जी	१९३१	„
(४) श्री नरसिंह चिन्तामण केलकर	—	—
(५) श्री के. नटराजन	१९३४	दिल्ली
(६) डा. पट्टाभिसीतागमैया	१९३६	कराची
(७) पं० जवाहरलाल नेहरू	१९३६	लुधियाना
(८) पं० जवाहरलाल नेहरू	१९४१	उदयपुर

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् का विधान

(उदयपुर अधिवेशन में परिवर्तित तथा मंजूर)

धारा १—अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् का नाम अखिल भारत देशी लोक-परिषद् होगा।
समस्त भारत के हिस्सों के रूप में देशी निवासी के जमा
द्वारा शान्तिपूर्ण और उचित उपायों के द्वारा उन्मत्त
शान्ति प्राप्त करना है।

- (६) दक्षिण की रियासते, (महाराष्ट्र और कर्नाटक में)
- (१०) पंजाब की रियासते,
- (११) हिमालय की पहाड़ी रियासते,
- (१२) बिलोचिस्तानी रियासते, (कलात लासबेला खरन और खेरपुर)
- (१३) काठियावाड़ की रियासते (कच्छ सहित)
- (१४) राजपूताना की रियासते

(ख) स्टैंडिंग कमिटी जब कभी उचित समझेगी, तब नये सिरे से विभाजन करके प्रदेश बना सकेगी ।

धारा ५--रियासती प्रजा के संगठन, चाहे उनका नाम प्रजा-मंडल, लोक परिषद्, प्रजा परिषद्, स्टेट कॉंग्रेस, नेशनल कांग्रेस या ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राज्य-समूह के अन्दर काम करते हो, या विशेष परिस्थितियों में स्टैंडिंग कमिटी की मजूरी से बाहर ने काम करने हों। इस विधान के अनुसार प्रादेशिक परिषद् द्वारा या मीने अन्रिल भागत देशी राज्य लोक परिषद् में सबद्ध या स्वीकृत किये जा सकते हैं।

धारा ६--(क) कोई भी प्रादेशिक कॉन्सिल उन प्रदेश के अन्दर किसी भी रियासती प्रजा संगठन को संग्रह कर सकेगी, बशर्ते कि-

(१) वह इस विधान की धारा १ को प्रस्ताव द्वारा मन्जूर कर चुकी हो.

(२) उसकी सदस्य सूची में आठवाँटी के प्रति एक लाख या कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक सदस्य हों,

(ख) स्टैंडिंग कमेटी को अधिकार होगा कि वह अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् से, किसी कारणवश सम्बद्ध या स्वीकृत न हो सकनेवाले प्रजा-संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि नामजद करे।

धारा ६—(क) धारा २ में बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक प्रादेशिक कौंसिल होगी, जो इस प्रकार बनेगी:—

(१) उस प्रदेश के अन्दर के पारिषद् के प्रतिनिधि, तथा पारिषद् के प्रेसीडेंट और भूतपूर्व प्रेसीडेंट जो उस प्रदेश में रहते हों।

(२) रीजनल कौन्सिल के टेलीग्राफों द्वारा अपनी सख्या के $\frac{1}{2}$ तक कोआप्ट किये हुए व्यक्ति। इन कोआप्ट किये हुए मेम्बर्स को भी प्रतिनिधि के अधिकार होंगे।

(ख) हर प्रादेशिक कौन्सिल को स्टैंडिंग कमेटी के सामान्य नियन्त्रण व निगरानी के अर्थात् अपने प्रदेश के समस्त कार्य-संचालन का अधिकार होगा।

(ग) प्रादेशिक कौन्सिलें इस विधान के अनुसार रहनेवाले अपने नियम बना सकेंगी। पारिषद् की स्टैंडिंग कमेटी की मन्जूरी के बाद वे नियम काम में आ सकेंगे।

(घ) यदि कोई प्रादेशिक कौन्सिल इस विधान के अनुसार कार्य न करेगी तो स्टैंडिंग कमेटी उस प्रदेश में, पारिषद् का काम चलाने के लिये अस्थायी कौन्सिल बना सकेगी।

रा १०—(क) जनरल कौन्सिल निम्न लिखित व्यक्तियों की बनेगी।

(१) हर प्रादेशिक कौन्सिल द्वारा उस कौन्सिल के
मेम्बरों की तादाद पर हर पांच के पीछे एक मेम्बर
के हिसाब से चुने हुए मेम्बरान।

वशतें की जनरल कौन्सिल में हर प्रादेशिक
कौन्सिल को कम से कम दो प्रतिनिधि आवश्यक
भेजने का अधिकार होगा, और,

(२) जनरल कौन्सिल के चुने हुए मेम्बरों द्वारा अपनी
तादाद के $\frac{1}{2}$ तक कोऑप्ट किये गये मेम्बर।

(ग) जनरल कौन्सिल के प्रत्येक मेम्बर को, अपने वोट
का इस्तेमाल करने के लिये सेंट्रल प्रॉविंस को ५) ६०
फीस अदा करना होगा।

(घ) जनरल कौन्सिल उस राज्य में होगा जो एक कमरा, जो
परिचित अपने एन्तिशेन में निश्चित कर चुकी होगी,
और अपने कार्यकाल में सेवा देने वाले नवम नये
सामानों को भी निश्चित होगी।

(च) जनरल कौन्सिल का समय ३० दिन, या कुछ मेम्बर
समय के २५ दिन, जो भी कम होगा, होगा।

रा ११—(क) स्ट्रेट्स फोर्ट्स में प्रेसीडेंट, व डिप्टी प्रेसीडेंट, एक
या अधिक सचिव के स्ट्रॉन्ग, एक क्लर्क और
१६ अन्य मेम्बर होंगे। प्रेसीडेंट, डिप्टी प्रेसीडेंट, व सचिव
उपरोक्त के चुने जायेंगे। प्रेसीडेंट स्ट्रेट्स फोर्ट्स
के गवर्नर, डिप्टी प्रेसीडेंट व सचिव
उपरोक्त के मेम्बरों के चुने जायेंगे।

(ख) स्टेन्डिंग कमेटी परिषद् की कार्यकारिणी होगी, और उसे आ भा दे रा लोक-परिषद् तथा जनरल कौन्सिल द्वारा निश्चित की हुई नीति तथा प्रोग्राम को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा ।

(ग) स्टेन्डिंग कमेटी का कोरम ६ का होगा।

(घ) स्टेन्डिंग कमेटी को निम्नलिखित अधिकार भी होंगे—

१ विधान का मुनासिब अमल कराने तथा विशेष परिस्थितियों को निवटारने के लिये नियम बनाना, तथा हिदायते जारी करना ।

२ गलत व्यवहार, लापरवाही या कर्तव्य के न पालने की सूचना से किसी कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहे, करना ।

३ तमाम अगभूत कमेटियों का निर्गन्त निपटारा तथा पथप्रदर्शन ।

धारा १२—(क) परिषद् का प्रेसीडेंट अगले अधिवेशन तक काम करता रहेगा । वही जनरल कौन्सिल का भी अध्यक्ष होगा ।

हुआ हिमाचल जनरल कॉमिन्स के समक्ष उसकी जानकारी के लिए पेश किया जायगा ।

धारा १३—(क) स्टेटिंग कमेटी प्रादेशिक कॉमिन्सों में प्रेसीडेंट के चुनाव के विषय में सुझाव मांगेगी ।

(ग) जनरल कॉमिन्स के मेम्बर इस सुझाव हुई सूची में से पद के अभियोजन में कम से कम एक बार पहले प्रेसीडेंट का चुनाव करेंगे ।

(ग) स्टेटिंग कमेटी इस चुनाव के लिए नियम बनायेगी ।

धारा १४—(क) वरिष्ठ अभियोजन, स्टेटिंग कमेटी द्वारा निर्दिष्ट विषयों पर ध्यान दे सकने पर होगा ।

(ग) जिस प्रोजेक्ट में अभियोजन होने वाला होगा तथा ही प्रस्तावित अभियोजन के लिए आवश्यक समिति निर्माणाधीन होगी ।

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् की वर्तमान स्थायी-समिति

१ अध्यक्ष	श्री. पं. जवाहरलाल नेहरू
२ कार्यवाहक अध्यक्ष	,, डॉ. पट्टाभि सीतारामैया
३ उपाध्यक्ष	,, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
४ कोषाध्यक्ष	,, कमलनयन बजाज
५ मन्त्री-	,, जयनारायण व्यास
६ ,,	,, बलवन्तराय मेहता
७ ,,	,, टी. एम. वर्गिस
८ ,,	,, द्वारकानाथ काचरु
९ सदस्य	,, स्वामी रामानन्द तीर्थ
१० ,,	,, पच. के. वीरण्णा
११ ,,	,, आचार्य नरेन्द्रदेव
१२ ,,	,, बाल गंगाधर खेर
१३ ,,	,, खान अब्दुल समदखां
१४ ,,	,, हीरालाल शास्त्री
१५ ,,	,, ई. इखेदा वाडियर
१६ ,,	,, शारंगधरदास
१७ ,,	,, बी. व्ही. शिखरे
१८ ,,	,, शिवशंकर रावल
१९ ,,	,, वैजनाथ महोदय
२० ,,	,, वृषभानदास

स्टैंडिंग कमेटी के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

(उदयपुर अधिवेशन में नीचे लिखे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मजूर हुए हैं, जो लोक परिषद् के संगठन में सम्बन्ध रखते हैं । परन्तु वे भी यश दिये जा रहे हैं ।)

(१) सार्वजनिक आलोचना न हो

देशी राज्य लोक परिषद् की नीति और प्रवृत्तियों से विरोधी रही हैं। कुछ आधारभूत मामलो में यह विरोध लगातार जारी रहा है, बढ़ा है और आज भी वह इन सगठनों के प्रकाशनो में पाया जाता है। यह साफ जाहिर है कि इस लोकपरिषद् में कोई कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटी असरदार ढंग से काम नहीं कर सकती, यदि उसके सदस्यों में इस प्रकार सिद्धान्तों का विरोध हो। इसके अलावा भी विधान की धारा ३ के अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद् के कार्यक्रमों का खुला विरोध करेगा वह इसकी कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटियों का सदस्य नहीं रह सकेगा।

चू कि इनका सवाल कुछ व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि ऐसे माने हुए दलों की नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखता है, जो कि सुविदित हैं और विवादग्रस्त नहीं हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि स्वीकृति माँगा जावे, या अनुशासन सम्बन्धी कार्य के लिए कारण बताने के लिए आरोप कायम किये जावे। इसलिए यह निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या ग्रेडिकल डेमो-क्रैटिक पार्टी का कोई सदस्य अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् के सगठनों में किसी कार्यकारिणी में न चुना जावे और न किसी चुने हुए पद या कमेटी में रखा जावे। यह फैसला सम्बन्धित और स्वीकृत संस्थाओं के लिए भी लागू होगा। यदि ऐसे कोई व्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके हों, तो उनसे पूछा जावे कि इस नियम के अनुसार वे जिस समिति के चुने हुए सदस्य हो गए हैं, उसकी सदस्यता से उन्हें पृथक् क्यों न किया जावे।

परिशिष्ट (७)

छोटी रियासतों के

प्रजामण्डलों के लिए नमूने का विधान

- धारा १—नाम—इस संस्था का नाम ...राज्य प्रजा मण्डल है ।
- धारा २—उद्देश्य—इस प्रजा मण्डल का उद्देश्य अग्नित भारत देशी राज्य लोक परिषद् के मार्गदर्शन में, ... राज्य की जनता के लिए शान्त और उन्नित उपायों द्वारा उन्नतशी शासन व नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है ।
- धारा ३—सदस्यता—राज्य का निवासी, पोट भी स्त्री या पुरुष, जिसकी उम्र १८ वर्ष की या ज्यादा हो, इस प्रजा मण्डल के उद्देश्य को मंजूर करने पर और नार अना मास्यमा चन्द्रा अदा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा ।

- धारा ६—तहसील कमेटियां—किसी भी तहसील की सब मामूली मुकामी कमेटियों के डेलीगेटों को मिला कर तहसील कमेटी होगी, जो तहसील के अन्दर प्रजा मण्डल के कामों की देख-रेख करेगी ।
- धारा ७—जनरल कमेटी—राज्य भर की कुल मुकामी कमेटियों से चुने हुए डेलीगेटों की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके अलावा हर मुकामी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेक्रेटरी भी बलि-हाज श्रोहदा डेलीगेट होंगे और इस जनरल कमेटी को विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का सर्वोच्च अधिकार होगा । इसका मामूली तौर पर हर साल वार्षिक अधिवेशन होगा । डेलीगेट प्रारम्भिक सदस्यों के हर १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के हिसाब से चुने जावेंगे ।
- धारा ८—एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी—एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी सात से १५ मेम्बर्स तक की हो सकेगी । और उसको प्रेसिडेन्ट नामजद करेगा । व्हाइस प्रेसिडेन्ट और खजांची के अलावा एक जनरल सेक्रेटरी, व एक से ज्यादा सेक्रेटरी हो सकेंगे ।
- धारा ९—एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी के काम और अधिकार—यह जनरल कमेटी की हिदायतों के मुताबिक कार्य संचालन करेगी । और वही अनुशासन सम्बन्धी सब मामलों के निर्णय करने का अधिकार रखेगी । इस कमेटी को चुनाव सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने के लिए और दूसरे मामलों के लिए सब कमेटी मुकदमों या खुद फैसला करने का अधिकार होगा । लेकिन झगड़ों में सम्बन्धित व्यक्ति कोर्ट नहीं दे सकेंगे । यही कमेटी अधिवेशन की वार्षिक मुकदमों करेगी और उसका सुनासिव इन्तजाम करेगी ।

धारा १०—प्रेसिडेंट--हम अधिवेशन की तारीख से कम से कम दो महीने पहिले प्रेसिडेंट की नामजदगी के परर्ने, जिन पर कम से कम तीन डेलीगेटों द्वारा नामजदगी हो, प्रधान कार्यालय में आ जाना चाहिये। इन सब पर एकभीस्मूटिंग कमेटी में विचार होगा और आये हुए तमाम नामों की इतना तमाम मुकामी कमेटियों और तमाम कमेटियों में भेज दी जावेगी। प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी प्रधान कार्यालय में आई हुई रिटायरों के मुताबिक वार्डें हुई तारीख व मुकाम पर प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी रोट लिखे जायेंगे। जिनमें सिर्फ डेलीगेट ही हिस्सा ले सकेंगे। हर कमेटी पर एक डम्मीगार के विषय आये हुए रोटों की तयार, प्रधान कार्यालय हो, चुनाव के तीन दिन के अन्दर बनाना पड़ेगी। प्रजा मण्डल के प्रेसिडेंट के कमेटी या एक डम्मीगार कमेटी द्वारा मुहरों की हुई विशेष मतकमेटी एवं एक प्रेसिडेंट की गोपनीय होगी।

धारा १३—खाली जगह की पूर्ति—सामान्यतः खाली जगह की पूर्ति उसी तरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या चुनाव होता है ।

धारा १४—कोरम—प्रजा मण्डल की हर कमेटी का कोरम एक चौथाई का होगा ।

धारा १५—केन्द्रीय संस्थाओं की हिदायतों- की पाबन्दी--यह संस्था अपनी केन्द्रीय संस्था, अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् या उसकी प्रादेशिक शाखा, मध्यभारत प्रादेशिक देशी राज्य लोक परिषद् से आई हुई हिदायतों का ख्याल रखेगी ।

आवश्यक नोट,

मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिषद् ने मध्यभारत की छोटी रियासतों के लिये यह नमूने का विधान बनाया है । इसमें प्रजा मण्डल का नाम, उद्देश्य, स्थानीय हालात के लिहाज से अन्य आवश्यक नियम जोड़े जा सकते हैं ।

परिशिष्ट (८)

नरेन्द्र मण्डल

शासन सुधार के विषय में माण्टेग्नु नेम्सपोर्ट रिपोर्ट के दमों अन्तर्गत में रियासतों के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं। इनकी पूर्ति की दिशा में ता० ८ फरवरी १९२१ को ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा दिल्ली में चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस अर्थात् नरेन्द्र मण्डल का उद्घाटन किया गया। इस अनसर पर पढ़े जाने के लिए मन्नाट ने खुद अपना एक मन्देश भेजा था। जिसमें कहा गया था कि "राजा-मन्नाजान्त्रों का यह मण्डल उनके अपने तथा प्रजाजनो के स्थायी लाभ का पोषक होगा; ऐसी हमें आशा है। हमें यह भी आशा है, कि अपने राज्य तथा ब्रिटिश भारत के हितों को आगे बढ़ाने हुए वे में समस्त साम्राज्य का भाग लेंगे। यह नरेन्द्र मण्डल हमें एक दूसरे को समझने में सहायक होगा, हम एक दूसरे में अधिक नजदीक आनेमें और देशी राज्य तथा समस्त साम्राज्य के सामान्य हितों की हमारे अभिवृद्धि और विकास होगा।"

ऐसे प्रत्येक ग्रूप का एक प्रतिनिधि उसमें रहेगा। भारतवर्ष में कुल ११८ पूर्वाधिकारवाली सलामी की इकदर रियासते हैं। इनमें से केवल १०८ ही मण्डलमें शरीक हुईं। शेष, उदाहरणार्थ—हैदराबाद, मैसूर, नावणकोर, कोचीन, बड़ौदा और इन्दौर-नरेन्द्रमण्डल की सदस्य नहीं बनीं। अन्य कारणों के साथ इन्होंने इसकी वजह यह भी बताई कि नरेशों के लिये व्यक्तिगत दृष्टि से यह अत्यंत अनुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवहारों का हामी अपने को बना ले, जो शायद उनके प्रजाजनो को पसन्द न हो। नरेशों को जो कुछ कहना हो अपने मन्त्रियों के माफत कहना या करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेवारी पर वे कुछ न कहे-करे, क्योंकि उनकी जानकारी बहुत अधूरी होती है। अनुभव और वक्तृत्व शक्ति की भी उनमें कमी होती है। जिनके नरेशों को सलामी का अधिकार नहीं है, ऐसी १२७ छोटी रियासतों की तरफ से मण्डल में १२ प्रतिनिधि हैं। सर पी एस शिवस्वामी ऐयर ने इसके कर्तव्य और सत्ता के विषय में एक बार कहा था—

मैं आपकी बुद्धिमत्ता भरी सलाह के लिए एहसानमन्द हूँ। आपके सामने इस वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं आशा करता हूँ, आप उसे निश्चयपूर्वक पूरा करेंगे। आप के समस्त अपने प्रजाजनों की भलाई और तस्करी करने की जिम्मेवारी है और मुझे विश्वास है, आप इसे पूरा करने में तनमन से जुट जावेंगे। आप साबित कर देंगे कि देश का गौरव पूर्ण इतिहास में आपसे अपने महान गौरवशाली पूर्वजों की भाँति एक महान विस्फोट प्रकाशित होगा। समय के साथ आप ही बनना चाहिए। मुझे विश्वास है, इस परिपट में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर आप विचार कर रहे हैं, उनके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। तमीरा।

